



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(श्रसाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुद्धवार, 7 दिसम्बर, 1955

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

Establishment Branch

NOTIFICATION

Simla-4, the 6th December, 1955

No. A-107-112/54.—Himachal Pradesh Government announce with regret the death of Shri Parkash Chandra Singha, a nominee of the Himachal Pradesh Government under training at the Mountaineering Institute, Darjeeling, on December 3, 1955. Shri Singha caught double pneumonia while hiking in the hills on November 28, 1955. He died on the way while he was being brought to Darjeeling.

Shri Singha, who was in the early thirties, was the son of R. S. Amin Chand, a well known orchard owner of Kotgarh and a social figure of Himachal Pradesh. After passing his B. Sc. (Agr.), Shri Singha took to farming and orchard raring and in 1953 went to England to make a special study in Entomology. While in England he was awarded Fellowship of the Royal

Entomological Society.

Shri Singha was a keen sportsman and took to mountaineering during his college days. In 1945 he climbed Churi Chanani and later on the Kolahi peak (14,000 ft.)

He was one of the founder members of the Himachal Winter Sports Club and took great interest in its activities and helped in organising them.

Being of a very amiable nature, Shri Singha was very popular amongst all sections of the people. By his untimely death, the Government of Himachal Pradesh have lost a keen sportsman and a social worker.

The Government convey profound sorrow and feelings of heart-felt sympathies to his young widow, children, R. S. and Mrs. Amin Chand and other relations.

BASANT RAI,

न॰ इ० पी०-६७

Registered No. E. P.-97



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(श्रमाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 1955

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH विधान सभा विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-4, दिनांक 22 नवम्बर, 1955

सं० वी. एस. 71/55.—गवन मेंट आफ पार्ट "सी" स्टेर्स ऐक्ट, 1951 की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 4 अक्तूबर, 1955 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किए गए निम्नलिखित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर दी है और उसे अब हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 126 के अधीन सर्व साधारण की सुचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

श्रिधिनियम सं० 8, 1955

हिमाचल प्रदेश जाति-बहिष्कार निवारण अधिनियम, 1955

हिमाचल प्रदेश में जाति बहिष्कार निषेध करने का

अधिनियम

यह गणतन्त्र के छुटे वर्ष में निम्नलिखित रूप में ऋधिनियमित किया जाता है:

- 1. सं चित्र नाम, प्रसार श्रीर प्रारम्भ.—(1) इस श्रिधिनयम का संचित्र नाम हिमाचल प्रदेश जाति-बहिष्कार निवारण श्रिधिनयम, 1955 होगा।
 - (2) इसका प्रसार समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में होगा।
 - (3) यह तुरन्त प्रचलित होगां।
- 2. परिभाषा.—जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकृल न हो, इस अधिनिया में
 - (क) "समुदाय (community)" का तात्पर्य ऐसे जन समूह से है जिसके सदस्यों का इस तथ्य के आधार पर पारस्परिक सम्बन्ध हो कि वे जन्म से, धर्म-परिवर्तन से या किसी धार्मिक संस्कार का पालन करने से एक ही धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय (creed) से सम्बन्ध रखते हैं, और इसके अन्तर्गत जाति या उप जाति भी है;
 - (ख) "जाति-बहिष्कार (excommunication)" का तात्पर्य किसी व्यक्ति को ऐसे समुदाय से निकालना है जिसका वह सदस्य हो, श्रीर जिससे वह ऐसे श्रिधिकारों श्रीर विशेषाधिकारों (privileges) से वंचित हो जाए जो उसके या उसको श्रीर से समुदाय के किसी सदस्य द्वारा दीवानी प्रकार के बाद से वैधानिक रूप में प्रवर्तनीय हो;

स्पद्धीकरण.—इस तथ्य के होते हुए भी कि किसी अधिकार का निश्चय नितान्त रूप से समुदाय के धार्मिक संस्कार, रसम, नियम या रिवाज के सम्बन्ध में उठे किसी प्रश्न के निर्णय पर निर्भर है, पद प्रहण करने या सम्पत्ति या किसी धार्मिक स्थान में पूजा करने या शव जलाने या दफनाने का अधिकार इस खण्ड के प्रयोजनार्थ दीवानी प्रकार के वाद द्वारा वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार के अन्तर्गत होगा।

3. जाति-वहिष्कार मान्य नहीं होगा श्रोर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा. — तत्काल प्रचलित किसी विधि, प्रथा या रिवाज में किसी बात के विषरीत होते हुए भी किसी समुद्राय के सदस्य का कोई भी जाति-वहिष्कार मान्य नहीं होगा श्रोर उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा।

4. शास्ति. — जो कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करे, जिससे समुदाय के किसी सदस्य का जाति-वहिष्काः हो जाए या जो ऐसा करने में सहायक हो, वह दोषी ठहराए जाने पर एक हजार रुपए तक के अर्थ दगड़ का भागी होगा।

स्पष्टीकर्गा — जब वह व्यक्ति, जिस पर इस धारा के अधीन अपराध करने का आरोप लगाया गया हो, व्यक्तियों की निर्मामत संस्था या संघ हो या निर्मामत न हो, और यदि उक्त संस्था या संघ की बैठक में अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया हो तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिस ने जाति-वहिष्कार से सम्बद्ध निर्णय के पद्म में मत दिया हो, यह समभा जायगा कि उसने अपराध किया है।

- 5. इस श्रिधिनयम के श्रधीन श्रिधकार त्रेत्र.—कोड ग्राफ क्रिमनल प्रोसीजर, 1898 (Code of Criminal Procedure, 1898) में किसी बात के होते हुए भी, पहली श्रेणी के मिजिस्ट्रेट के न्यायालय से कम श्रेणी का कोई भी न्यायालय धारा 4 के ग्रधीन दण्डनीय किसी भी श्रपराथ की श्रन्वी ज्ञा नहीं करेगा।
 - 6. अपराध संज्ञान करने की रीति. कोई भी न्यायालय
 - (क) उस दिनांक से एक वर्ष समाप्त हो जाने पर, जिस दिनांक को अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया हो, और
 - (ल) हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे पदाधिकारी, जो डिस्ट्रिकट मजिस्ट्रेट से कम पदबी का न हो, की पूर्व स्वीकृति लिए विना;

धारा 4 के अधीन दगड़नीय अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

शिमला-4, दिनांक 26 नवम्बर, 1955

ची॰ एस०-70/55.—गवर्नमैंट त्राफ पार्ट "सी" स्टेट्स ऐक्ट, 1951 की धारा 26 की उपधारा (2) के त्रधीन भारत के राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 17 त्रक्त्वर, 1955 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किए गए निम्नलिखित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर दो है त्रौर उने अब हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 126 के त्रधीन सर्व साधारण को सूचनार्थ इस श्रिधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

ऋधिनियम सं० 9, 1955

हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1955

31 मार्च, 1956 को समाप्त होने वाले वर्ग की सेवाओं के लिए संचित निधि में से कतिपय राशियां चुकाने ग्रीर उन का विनियोग करने के हेतु

अधिनियम

यह निम्नांलखित रूप में विधान सभा द्वारा अधिनियमित किया जाए:--

- 1. संद्याल नाम.--यह अधिनियम 1955 का हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (न०) कहला गा।
- 2. वर्ष 1955-56 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से 97,61,000 रूपए निकाला जाना.—31 मार्च, 1953 को अन्त होने वाले वर्ष, किए गए कतिपय व्ययों को पूरा करने के हेतु उन को चुकाने के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य के संचित धन में से अनुमूची के तीसरे स्तम्भ में विशिष्ट राशियों चुकाई जाएं, जो उस स्तम्भ में विशिष्ट राशियों, जिन का जोड़ सतानवें लाख और इक्सट हजार रुपए है उस से अधिक नहीं होंगी।
- 3. विनियोग हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से जिन राशियों को इस अधिनियम के द्वारा चुकाने और प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है, उन राशियों का विनियोग, 31 मार्च, 1956 को अन्त होने वाले वर्ष के विषय में अनुसूची में प्रदर्शित सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

श्रतुस्ची (धारा 2 श्रीर 3 देखिये)

ग्रनुरान	स्त्रीकृत	सेवाए तथा प्रयोजन	निम्नलिखित रा	निम्नलिखित राशियों से अनिधिक	
तरी	संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीवृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4		5
1	1	मालगुजारी	24,000		24,000
4	2	दन	1,32,000		1,32,000

1		2	3	4		5
9		3	सामान्य प्रशासन के कारण ब्यय	22,000	_	22,000
10		4	न्याय प्रशासन	20,000	_	20,000
12		5	पुलिस	50,000	_	50,000
15		6	चिकित्सा	34,000	_	34,000
16		7	जन स्वास्थ्य	6,34,000		6,34,000
17		8	<u>क</u> ्रांष	4,43,000		4,43,000
18		9	पशु चिकित्सा	25,000		25,000
20	o .	10	उद्योग तथा प्रदाय	1,000	_	-1,000
2	2	11	ऋन्य सिविल वर्कस	7,06,000	_	7,06,000
> 2	4	12	साधारण राजस्य से वितयोपित विद्युत योजनास्त्रों पर व्यय	51,000	_	51,000
2	7	13	लेखन सामग्री ऋौर छपाई	39,000	_	39,000
2	8	14	विविध	7,35,000	_	7,35,000
3	80	15	बस व जल की सेवाओं पर व्यय	1,85,000	-	1,85,000
;	31	16	सामूहिक विकास योजना राष्ट्रीय विस्तार सेवा विकास दोव ऋौर लोकल डवेल्पमैट वर्कस	11,00,000		11,00,000
7	32 - A	17	सार्व जिन्क स्वास्थ्य की तरक्की पर पूँ जी व्यय	10,90,000	_	10,90,000
	33	18	कि सुधार एवं स्रोज की योजनास्रों पर पूंजी लागत	1,55,000		1,55,000
į.	34	19	राजस्व लेखे के बाहिर नागरिक कार्यों पर पूंजी लागत	21,62,000	_	21,62,000
	35	20) विद्युत योजनास्त्रीं पर पूर्जी व्यय	15,73,000	_	15,73,00
	~	<u> </u>	1	•		_•

1	2	3	4	5
36	21	राजस्व लेखे के बाहिर पथ परि- वहन योजनास्त्रों पर पूंजी व्यय	4,07,000	4,07,000
37	22	राजकीय व्यापार की योजनास्त्रों पर पूंजी व्यय	43,000 —	43,000
38	23	ऋगा तथा ऋग्रिम धन जिन पर व्याज लगता है	1,30,000 —	1,30,000
τ,		जोड़	97,61,000	97,61,000

शिमला-4,दिनांक 26 नवम्बर, 1955

सं० वो॰ ऐस०-185 55. — गवर्नमेंट ग्राफ पार्ट 'सी' स्टेटस ऐक्ट, 1951 की घारा 26 की उपधारा (2) के ग्रधीन भारत के राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 22 श्रक्त्वर, 1955 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किए गए निम्नलिखित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर दी है, श्रीर उसे ग्रव हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया यिनमों के नियम 126 के ग्रधीन सर्व साधारण की स्चनार्थ इस श्रिधस्चना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

श्रिधिनियम सं० 10, 1955

हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1955

हिमाचल प्रदेश दड़ी जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था श्रिधिनियम, 1953 में संशोधन करने क

अधिनियम

यह गण्तन्त्र के इटे वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:

- 1. संदिष्त नाम, प्रसार श्रीर प्रारम्भः—(1) इस श्रिधिनयम का संद्विष्त नाम हिमाचल प्रदंश बड़ी जमीदारी उन्मृलन तथा भृमि व्यवस्था (संशोधन) श्रिधिनयम, 1955 होगा।
 - (2) इसका प्रसार समस्त हिमाचल भ्रदेश राज्य में होगा।
 - (3) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

- 2. 1953 की ऋधिनियम संख्या 15 की धारा 54 में संशोधन. हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन तथा भूम व्यवस्था ऋधिनियम, 1953 (जिसे यहां से आगो मृल ऋधिनियम कहा गया है) की धारा 54 की उपधारा (1) के खरड (छ) के परादिक (इ) के खरडों (क) तथा (ख) को हटा कर उन के स्थान पर निम्नलिखित खरड (क) तथा (ख) रखे जाएं:—
 - "(क) प्रथम मार्च, 1956 से पहले काश्तकारी की ऐसी सूमि या भूमियां विनिहित गीति से विशिष्ट करगा, जिस से या जिन से वह काश्तकार को निष्कासित करना चाहता है; श्रीर
 - (ख) 30 सितम्बर, 1956 से पहले उक्त निष्कासन की कार्यवाहियां त्यारम्भ करेगा।"
- 3. 1953 की श्रिधिनियम संख्या 15 की धारा 55 में संशोधन. मृल श्रिधिनियम की धारा 55 के खरड (क) के पश्चान् निम्नलिखित परादिक बढ़ा दिया जाए:—

"परन्तु 28 फरवरी, 1953 से पूर्व देय लगान के किसी बकाया के सम्बन्ध में काश्तकार निष्कासन के योग्य नहीं होगा, यदि वह 26 जनवरी, 1957 को या इस से पहले बकाया की आधी राशि चुका देता है।"

शिमला-4, दिनांक 26 नवम्बर, 1955

सं० वी॰ ऐस॰-178/55.—गवर्नमैंट ग्राफ पार्ट 'सी' स्टेटस ऐस्ट, 1951 की धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति महोदय ने दिन क 26 ग्राक्त्रवर, 1955 को, हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किए गए निम्नलिखित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर दी है, ग्रीर उसे ग्राव हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 126 के ग्राधीन सर्व साधारण की स्चनार्थ इस ग्राधिस्चना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

ग्राधिनियम सं० 11, 1955

हिमाचल प्रदेश भूराजस्व (संशोधन), अधिनियम 1955

हिमाचल प्रदेश भूराजस्व श्रिधिनयम, 1953 में संशोधन करने का अधिनियम

भारतीय गगातंत्र के **छ**टे वर्ष में हिमाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में ऋधिनियनित किया जाए।

- 1. संतिष्त नाम इस ऋघिनियम का नाम हिमाचल प्रदेश भूराजस्य (संशोधन) ऋघिनियम, 1955 होगा:
 - 2. हिमाचल प्रदेश ऋधिनियम संख्या 6, 1954 की धारा 4 में संशोधन —हिनाचल

प्रदेश भूराजस्य ऋधिनियम, 1953 (ऋधिनियम संख्या 6, 1954, जिसे यहां से आगे मूल ऋधिनियम कहा गया है) की धारा 4 में खंड (18) के स्थान पर निम्निलिखित खंड रखा जाए अर्थात :—

- ''(18) ''राज्य शासन'' का तात्पर्य हिमाचल प्रदेश राज्य के उपराज्यपाल से है ;''
- 3. हिमाचल प्रदेश ऋधिनियम संख्या 6, 1954 की धारा 17 में संशोधन मूल श्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) में शब्द "विचाराधीन" के पश्चात् शब्द "या उसके द्वारा निर्णात" जोड़े जाएं।
- 4. हिमाचल प्रदेश श्रधिनियम सं० 6, 1954 की धारा 45 में संशोधन मूल श्रधिनियम की धारा 45 के परादिक में शब्दों और अंकी "पहली अप्रैल, 1948 के बाद की" के स्थान पर शब्द और अंक "अप्रैल, 1948 के प्रथम दिन के मध्य की अविध में " रख दिए जाएं।
- 5. हिमाचल प्रदेश ऋधिनियम सं० 6, 1954 की धारा 83 संशोधन मूल अधिनियम की धारा 83 में
 - (क) उपधारा (1) में ---
 - (त्र) शब्दों ''श्रौर यदि फाइनेन्शियल कामश्नर'' के स्थान पर शब्द ''या यदि फाइनेन्शियल कमिश्नर'' रखे जाएं ;
 - (ग्रा) परादिक में शब्दों ''त्रौर किए गए संविदां' के स्थान पर ''या किए गए संविदां'' रें रखे जाएं।
 - (ख) उपधारा (2) में शब्द ''सम्पत्ति'' के स्थान पर शब्द ''ऋ चल सम्पति'' रखे जाएं।
- 6. हिमाचल प्रदेश ऋधिनियम सं० 6, 1954 की धारा 90 में संशोधन. मूल ऋधिनियम की धारा 90 में शब्दों ''श्रोर यह प्रमाणित'' के स्थान पर 'या यह प्रमाणित'' राज्य रहे बाएं।
- 7. हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं० 6, 1954 की धारा 102 में संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 102 में शब्दों "या भृराजस्व के किसी बकाया का, जो भृराजस्व के रूप में वसूल किया जा सकता हो" के स्थान पर शब्द "या ऐसी राशि को, जो भृराजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती हो" रखे जाएं।
- 8. हिमाचल प्रदेश ऋधिनियम सं॰ 6, 1954 की धारा 141 में संशोधन .-- मूल ऋधि- नियम की धारा 141 में :--
 - (क) उपधारा (1) के अन्त में शब्द "श्रीर माल अधिकारी राज्यशासन की ओर से एक अन्य मध्यस्थ मनोनीत करेगा" वढा दिए जाएं।
 - (ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाए, अर्थात् :--
 - "(2) माल अधिकारी ऐसोक रखों केश्राधार पर, जीवह श्रमिलिखित करेगा, वसी भी पत्त

के मनोनयन को अस्वीकार करने का आदेश दे सकेगा और यह अपेदा कर सकेगा कि वह पद्म ऐसी अविधि में, जो आदेश में विशिष्ट की जाएगी, फिर से नामांकन करे और यदि इस प्रकार विशिष्ट अर्वाध में अन्य मध्यस्थ मनोनीत नहीं किया जाता तो माल अधिकारी समय समय पर उस अविध को बढ़ा सकेगा या निर्देश के आदेश (order of reference) को रह कर सकेगा।"

- 9. हिमाचल प्रदेश अधिनयम सं० 6, 1954 की धारा 149 में संशोधन मून अधिनियम की धारा 149 में संशोधन : --
 - (क) उपधारा (1) में शब्दों "इस अध्याय" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम" रखे जाए ;
 - (ल) उपधारा (2) में शब्दों ''श्रन्तिम पूर्ववर्ती उपधारा'' के स्थान पर शब्द, श्रंक श्रोर के।ध्वक ''धारा 148 की उपधारा (1)'' रखे जाएं।

शिमला-4, दिनांक 26 नवम्बर, 1955

सं ० वी ० एस०-175/55.—गवर्न मेंट आफ पार्ट 'सी' स्टेटम ऐक्ट, 1951 की धारा 26 की उपधारार (2) के अधीन भारत के प्ट्रपति महोदय ने दिनांक 8 नवम्बर, 1955 को, हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किए गए निम्नलिखित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर दी है, और उसे अब हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 126 के अधीन सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिम्चना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

द्धिनियम सं० 12, 1955

हिमाचल प्रदेश मिनिस्टर्ज एएड पार्लियामैंटरी मैकेटरीज मैलरीज एएड एलाऊंसिज (संशोधन) अधिनियम, 1955

हिमाचल प्रदेश मिनिस्टर्ज एएड पार्लियामैंटरी सैब्रैटरीज सैलरीज एएड एलाऊंसिज '
ऐक्ट, 1952 में संशोधन करने का

अधिनियम

यह गरातन्त्र के छटे वर्ष में निम्निलिखित रूप में ऋघिनियमित किया जाता है:

1. सं त्तिप्त नाम ऋौर प्रारम्मः—(I) इस ऋधिनियम का नाम हिमाचल प्रदेश मिनिस्टर्ज एएड पार्तियामैन्टरी सैंक टरीज सैलरीज एएड एलाऊ सिज (संशोधन) विधेयक, 1955 होगा।

(2) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

- 2. हिमानल प्रदेश मिनिस्टर्ज एएड पार्जियामैंटरी सैकैटरीज सैलरीज एएड एजाऊं।सेज ऐक्ट, 1952 की धारा 4 में संशोधन —हिमानल प्रदेश मिनिस्टर्ज एएड पार्जियामैंटरी सैकैटरीज सैलरीज एएड एलाऊंसिज ऐक्ट, 1952 (Himachal Pradesh Ministers' and Parliamentary Secretaries' Salaries and Allowances Act, 1952) की धारा 4 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (3) बढ़ा दी जाए:—
 - "(3) In respect of the rental value of the free furnished residence or house rent allowance in lieu thereof, no charge has whatsoever of income tax levied under the Income Tax Act, 1922, shall fall on the Minister and it shall be borne by the Government".

दिनांक शिमला-4, 26 नवम्बर, 1955

सं इया वी०-एस०-176 55.—गवर्नमैंट ब्राफ पार्ट 'सी' स्टेट्स एक्ट, 1951 की घारा 26 की उपधारा (2) के ब्राधीन भारत के राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 8 नवम्बर, 1955 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किए गए निम्नलिखित विभेषक पर स्वीकृति प्रदान कर दी है, ब्रौर उसे न का हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 126 के ब्राधीन सर्वसाधारण की स्वनार्थ इस अधिस्वना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

श्रिधनियम सं० 13, 1955

हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटिव एमैम्बली (सैलरीज एएड एलाऊंमिज) (संशोधन) अधिनियम, 1955

हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटिव एमैम्बली (सेजरीज एएड एलाऊंसिज) ऐक्ट, 1952, में संशोधन करने का अधिनियम

यह गणतंत्र के इंटे वर्ष में निम्नलिखित रूप में त्राधिनियमित किया जाता है:

- 1. संनिष्त नाम ऋौर प्रारम्भ .—(1) इस ऋधिनियम का संनिष्त नाम हिमाचल प्रदेश लैं जिस्लैटिव एसैम्बली (सैलरीज एएड एलाऊ सिका) (संशोधन) ऋधिनियम, 1955 होगा।
 - (2) यह तुरन्त प्रचलित होगा।
- 2. हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटिव एसेम्बली (सेलरीज एएड एलाऊ सिज) ऐक्ट, 1952, [Himachal Pradesh Legislative Assembly (Salaries and Allowances) Act,

1952] की धारा 4 में संशोधन.—हिमाचल प्रदेश लैंजिस्लेटिय एसैम्बली (सैलरीज एएड एलाऊंसिज ऐक्ट, 1952 की धारा 4 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नर्लिखत उपधारा (3) बढ़ा दी जाए:—

"(3) In respect of the rental value of the free furnished residence or house rent allowance in lieu thereof, no charge whatsoever of income-tax levied in accordance with the Income Tax Act, 1922, shall fall on the Speaker and it shall be borne by the Government."

शिमला-4, दिनांक 26 नवम्बर, 1955

संख्या वी। एस० 174/55.— गवर्नमेंट आफ पार्ट "सी" स्टेट्स ऐक्ट, 1951 की भारा 26 की उपधारा (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 17 नवम्बर, 1955 की, हिमाचल प्रदेश विधोन सभा द्वारा पारित किए गए निम्नलिखित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर दी है, और उसे अब हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 126 के अधीन सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकारित किया जाता है।

अधिनितम सं । 14, 1955

हिमाचल प्रदेश की छोटी नहरों का अधिनियम, 1955

हिमाचल प्रदेश में छोटी नहरों के नियन्त्रण और प्रबन्ध की सुन्यवस्था करने और उन पर उन्नति-शुल्क लगाने का

अधिनियम

यह गरातन्त्र के खटे वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया बाता है:

ग्रध्याय 1

प्रारम्भिक

- 1. संचित्त नाम और प्रसार.— (1) इस अधिनियम का नाम हिमाचल प्रदेश की छोटी नहरों का अधिनियम, 1955 होगा।
 - (2) इसका प्रसार समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में होगा।
- 2. श्रिधिनियम का प्रवर्तन (1) इस श्रिधिनियम के उपवन्ध उस सीमा तक श्रीर उस रीति से प्रवृत्त होंगे, जो यहां से श्रागे यथास्थिति या तो श्रमुसूची 1 में वा श्रमुसूची 2 में विशिष्ट प्रत्येक नहर के लिए न्यवस्थित है।

- (2) इस त्राधिनियम का प्रारम्भ होने के पश्चात् किसा भी समय राज्यसासन समय समय पर
 - (क) किसी भी नहर को अनुस्ची 1 में या स्थितिअनुसार अनुस्ची 2 में रख सकेगा, या किसी नहर को एक अनुस्ची से निकाल कर दूसरी अनुस्ची में रख सकेगा और उसके पश्चात् इस अधिनियम के ऐसे उपबन्ध, जो उक्त अनुस्ची में समाविध्य नहरों पर प्रयुक्त होते हों, या उक्त उपबन्धों में से ऐसे उपबन्ध, जो राज्य शामन निदेशित करे, उक्त नहर पर प्रयुक्त होंगे, या
 - (ख) इस अधिनियम के प्रवर्तन (operation) से किसो भी ऐसी नहर को मुक्त कर सकेगा, जो या तो अनुसूची 1 में समाविष्ट हो या अनुसूची 2 में समाविष्ट हो :

परन्तु कोई भी नहर अनुसूची 1 में नहीं रखी जाएगी, जब तक-

- (क) शासन को पूर्ण तथा या अंशतया उस पर स्वामित्व प्राप्त न हो, या
- (ख) इस ऋधिनियम का प्रारम्भ होने के समय शासन या कोई स्थानीय प्राधिकारी उसका प्रबन्ध न करता हो, या
- (ग) जिन स्थानों में यह श्रिधिनियम प्रसारित है, उन स्थानों में उसका कुछ भाग उनके श्रान्टर श्रीर कुछ भाग बाहर स्थित न हो, या
- (घ) जो श्रमुसूची 2 में समाविष्ट की गई हो श्रीर राज्यशासन के निदेशाधीन श्रमुमुची 1 मैं न रख दी गई हो ।
- 3. परिभाषायें.—जब तक विषय अथवा संदर्भ में कोई बात प्रतिकृत न हो, इस अधिनियम में—
 (1) "लाभधारी (beneficiary)" का किसी नहर के सम्बन्ध में ताल्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे
 - तत्कालार्थ उक्त नहर से प्रत्यक् अथवा अप्रत्यक् रूप में लाभ पहुंच रहा हो या लाभ पहुंचे; (2) ''उन्नतिशुल्क (betterment charges)'' का तात्पर्य अध्याय 3 के अधीन तिचन
 - 2) ''उन्नातशुल्क (betterment charges)' का तात्वय अध्याय 3 के अधान सिच योजना में समाविष्ट भूमियों पर त्रारोपित शुल्क से हैं;
 - (3) "नहर" का ताल्पर्य किसी भी नहर, प्राकृतिक या कृत्रिम कूल (artificial channel) या प्राकृतिक जलोल्मारण (line of natural drainage) या किसी जलाशय (reservoir), बन्द (dam) या तटबन्द (embankment), कृए, श्रीर उद्दाही
 - सिंचन प्रबन्ध (lift irrigation arrangement) से है, जो जल प्रदाय या जलसंग्रह या भूमि को बाद या रेत से बचाने के लिए निर्मित, संघृत या नियन्त्रित हों श्रीर इसके अन्तर्गत हैं,—ऐसे जलमार्ग या सहायक कर्म
 - (subsidiary works), जिन की परिभाषा इस भाग में टी गई हैं ;
 (4) "क्लेक्टर" का तात्पर्य जिले के मुख्य मालअधिकारी से है और ऐसा पदाधिकारी भी इसमें
 - सम्मिलित है, जिसे इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर की समस्त या कोई सी शक्तियां प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया गया हो ;

जल प्रदाय (water-supply) का निरीक्षण श्रीर श्रानियमन करने की शिक्ति.—श्रीर किसी भी ऐसी सूमि, भवन या जल-मार्ग (water-course) पर, जिस के लिए कोई जल कर (water-rate) वसूल किया जा सकता हो, या मन्पूर्ण अथवा अंशरूपेण परिहृत (remitted) हो या उसके भूराजस्व में स्माविष्ट हो, प्रदत्त-जल के प्रयोग का निरीक्षण या आनियमन करने या उससे सिंधित अथवा जल-कर (water-rate) से प्रभागत सूमि को मापने और ऐसे समस्त कार्य करने के लिए प्रवेश कर सकेगा, जो उक्त नहर का उन्तित आनियमन श्रीर प्रवन्ध करने के लिए आवश्यक हो;

चरों में प्रवेश करने के श्राभिप्राय की सृचना. —परन्तु यदि उक्त कलेक्टर या व्यक्ति रहने के मकान से संयोजित किसी भवन या संलग्न आंगन या बाग में प्रवेश करना चाह, जिसे किसी नहर से बहता देखा पानी न दिया जाता हो, तो वह ऐसे भवन, आंगन या बाग के स्वामी (occupier) को सात दिन पहले अपने इस अभिप्राय की लिखित सचना देगा;

प्रवेश द्वारा हुई च्रिति के लिए प्रतिधन — इस धारा के अधीन प्रवेश करने की प्रत्येक दशा में, कलेक्टर इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर ऐसी चृति के लिए, जो इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही करने से हो जाए, प्रतिधन का निर्धारण और उसकी चुकती करेगा।

24. सरम्मतों श्रीर श्राकस्मिक घटना श्री (accidents) की रोकथाम के लिए प्रवेश करने की शक्ति.—किसी नहर में किसी श्राकिसिक घटना (accident) के हो जाने पर या श्राकास्मक घटना का भय होने पर कलेक्टर श्रथवा इस हेन् उस के सामान्य या विशेष श्रादेशों के श्रधीन कार्य करने पाला व्यक्ति उक्त नहर से संलग्न भूमियों पर प्रवेश कर सकेगा श्रीर वे समस्त कार्य कर सकेगा, जो श्राकिस्मक घटना को रोकने श्रीर मरम्मत करने के लिए श्रावश्यक हों;

भूमि की च्रिति के लिए प्रतिधन — प्रत्येक ऐसी दशा में क्लेक्टर इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिए. जाने पर ऐसी किसी भी च्रित (damage) के लिये, जो इस धारा के अधीन की गई किसी कार्यवाही से हो जाए, धारा 66 के ऋधीन प्रतिधन निर्धारित करेगा और चुकाएगा।

- 25. नहर की मिट्टी जमा करने श्रीर किनारों की मरम्भत के लिये मिट्टी खोदने के हेतु नहर से संलग्न भूमि पर कब्जा करने की शिक्त श्रीर चिति के लिए प्रतिधन.—
 (1) क्लेक्टर या इस हेतु उसके सोमान्य या विशेष श्रादेशाधीन कार्य करने थाला कोई भी व्यक्ति नहर में ऐते श्रान्तर (distance) तक, जो शासन नियमों द्वारा निश्चित करे, किसी नहर से संलग्न भूमि पर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए कब्जा कर सकेगा:—
 - (क) नहर से खोटी गई मिट्टी उस भूमि पर जमा करने के लिए, या
 - (ख) नहर की मरम्मत के हेतु उस भूमि से मिही खोदने के लिए,

इस सम्बन्ध में कलेक्टर को प्रार्थनापत्र दिए जाने पर वह ऐसी किसी भी चृति (damage) के लिए, जो इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही से हो जाए, प्रतिधन नियत करेगा और चुकाएगा।

(2) जिस भूमि पर उपधारा (1) के अधीन किसी प्रयोजन के लिए इस अधिनियम का श्रारम्भ होने के पश्चात् कब्जा किया गया हो और वह तीन वर्ष से अधिक अविध तक ऐसे कब्जे में रही हो उसका स्वामी यह अपेज्ञा कर सकेगा कि उक्त भूमि धारा 55 के उपबन्धों के अनुसार स्थायी रूप से आर्जित की जाएगी।

26. श्रांतवर्ती जल मार्ग (intervening water-course) द्वारा जल प्रदाय (supply of water).— जब कभी कलेक्टर को किसी नहर से जल देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाए ख्रीर उसे यह ब्रावश्यक मालूम हो कि इस प्रकार जल दिया जाना चाहिए ख्रीर किसी विद्यमान जलमार्ग द्वारा ही दिया जाना चाहिए, तो वह ऐसे जलमार्ग (water-course) के संधारण (maintenance) के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को उस दिन, जो इक्त सूचना के दिनांक से चौदह दिन पूर्व का न हो, यह कारण बतलाने की सूचना देगा कि उक्त रूप से जल क्यों न दिया जाए ख्रीर उस दिन परिपृच्छा करने के उपरान्त कलेक्टर यह निश्चय करेगा, ख्राया कि उक्त जल मार्ग (water-course) द्वारा जल दिया जाए ख्रीर यदि दिया जाए तो किन शतों पर दिया जाए।

प्राधीं तब तक उक्त जलमार्ग (water-course) का जल प्रयोग करने का ऋधिकारी नहीं होगा जब तक उसने उक्त जलमार्ग के ऐसे किसी भी परिवर्तन के, जो उसे उस में से जल देने के लिए ऋगवश्यक हो, व्यय चुका न दिए हों ऋौर उक्त जल-प्रदाय (water-supply) के प्रथम व्यय का वह भाग भी न चुका दिया हो जो क्लेक्टर निश्चित करे। उक्त प्रार्थी उक्त जल-मार्ग (water-course) के संधारण-व्यय (cost of maintenance) के ऋपने भाग का उस समय तक उत्तरदायी भी रहेगा, जब तक वह उसका प्रयोग करता रहे।

- 27. नया जल-मार्ग (water-course) बनाने के लिए प्रार्थनापत्र. कोई भी व्यक्ति, जो नया जलमार्ग (water-course) बनाना चाहता हो, कलेक्टर को एक लिखित प्रार्थनापत्र दे सकेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे :—
 - (म्र) कि उस ने उस भूमि के, जिसमें से वह उक्त जल-मार्ग (water-course) ले जाना चाहता हो, स्वामियों से उतनी भूमि पर जितनी उक्त जलमार्ग (water-course) के लिए स्रावश्यक होगी, कब्जे (acquire) का ऋषिकार प्राप्त करने का स्नमफल प्रयत्न किया है;
 - (त्रा) कि वह त्रपनी त्रोर से श्रीर त्रपने व्यय पर उक्त श्राधिकार श्रार्जित करने के लिए समस्त त्रावश्यक कार्य कलेक्टर द्वारा किए जाने की इच्छा करता है;
 - (इ) िक वह उक्त अधिकार अर्जन करने में और जल-मार्ग (water-course) बनाने के समस्त व्यय स्वयं वहन (defray) करने के योग्य है।
 - 28. तटुपरान्त कलेक्टर की प्रक्रिया यदि कलेक्टर का यह विचार हो कि (ऋ) ऐसा जल-मार्ग (water-course) बनाना आवर्थक है, और
 - (त्र्रा) प्रार्थना पत्र के विवरण सत्य हैं,

तो वह प्रार्थी को ऐसी राशि, जो कलैक्टर प्रारम्भिक कार्यवाहियों का व्यय जुटाने के लिए त्रावश्यक समभे, त्रार प्रतिधन की ऐसी राशि, जिस के सम्बन्ध में वह यह विचार करे कि उक्त राशि धारा 31 के ऋधीन देय होने की सम्भावना है, जमा करने के लिये कहेगा श्रीर उक्त राशि जमा कर दिए जाने पर वह उक्त जल-मार्ग (water-course) के श्रिष्कतम उपयुक्त रेखाकरण (alignment) के सम्बन्ध में परिष्ट- छा करवाएगा श्रीर उस भूनि का श्रांकन करेगा, जिम पर उम की सम्मिति में जल-मार्ग बनाने के लिए कन्जा करना श्रावश्यक होगा श्रीर तुरन्त प्रत्येक ऐसे ग्राम में, जिस में से जल-मार्ग (water-course) ले जाने का विचार हो, इस श्राश्य की एक स्चना प्रकाशित करेगा कि उक्त ग्राम की इतनी भूमि इस प्रकार श्रांकित की गई है।

- 29. विद्यमान जलमार्ग (water-course) के हस्तांतरण (transfer) के लिए प्रार्थना पत्र कोई भी व्यक्ति, जो यह चाहता हो कि कोई विद्यमान जल-मार्ग (water-course) उसके वर्तमान स्वामी से उसे हस्तांतरित कर दिया जाए तो वह निम्नलिखित रूप में विवरश् देते हुए कलेकटर के पास प्रार्थना पत्र दे सकेगा—
 - (त्र्य) कि उसने उक्त जल-मार्ग (water-course) के स्वामी से उक्त हस्तांतरम् करने का श्रमफल प्रयत्न किया है;
 - (त्रा) कि उस की यह इच्छा है कि वलेक्टर उस की ग्रोर से श्रीर उसके व्यय वर उक्त हस्तांतरण के लिए समस्त श्रावश्यक कार्य करे;
 - (इ) कि वह उक्त हस्तांतरण के समस्त व्यय जुटा सकते के योग्य है। इस के पश्चात् प्रक्रिया — यदि कलेक्टर का यह विचार हो कि —
 - (क) उक्त हस्तांतरण उस जल-मार्ग (water-course) से सिचाई का अन्त्रा प्रयन्थ करने के लिए ज्यावश्यक है, त्रौर
 - (ख) प्रार्थ ना पत्र में दिए गए विवरण टीक हैं,
 - तो कलेक्टर प्रार्थी को अपने पास ऐसी राशि, जो वह उक्त हस्तांत ए के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यवाहियों का व्यय जुटाने और प्रतिधन की ऐसी राशि, जो धारा 31 के उपबन्धों के अधीन देय हो जाए, जमा कराने के लिए कहेगा और ऐसी राशि जमा कर दिए जाने पर वह प्रार्थना पत्र की एक स्चना प्रत्येक प्रभावित ग्राम में प्रकाशित करेगा।
- 30. जल मार्गी (water-courses) के हस्तांतरण या निर्माण पर श्राप्तियां, उनकी पिर्णृच्छा श्रीर उनका निरचय.—(1) जब यथास्थिति, धारा 28 या धारा 29 के श्रधीन सूचना-प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन के मध्य ऐसी भूमि या जलमार्ग (water course) में, जो सूचना में निर्दिष्ट हो, स्वत्व रखने वाला व्यक्ति कलेक्टर के पास उस संरचना (construction) या हस्तांतरण (transfer), जिसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया हो, से सम्बद्ध श्रपनी श्रापत्तियों का विवरण देते हुए उपरोक्त रूप से प्रार्थना पत्र देता है, तो कलेक्टर स्वत्व रखने वाले श्रान्य व्यक्तियों को यह सूचना देगा कि वह ऐसे दिन, जो उक्त सूचना में विणित होगा, या श्रन्य ऐसे दिन, जिस के लिए कार्यवाहियां स्थिगत की जाएं, विवादशस्त विषय की परिष्टुन्छ। प्रारम्भ करेगा या स्थितिश्रनुतार उक्त श्रापत्तियों की प्रान्यता के सम्बन्ध में परिष्टुन्छ। श्रारम्भ करेगा या स्थितिश्रनुतार उक्त श्रापत्तियों की प्रान्यता के सम्बन्ध में परिष्टुन्छ। श्रारम्भ करेगा।

- (2) इस प्रकार नामांकित दिनांक या उपरोक्त ऋनुवर्ती दिनांक को कलेक्टर स्थिति ऋनुसार विवाद या श्रापित की सुनवाई श्रौर निश्चय श्रारम्भ करेगा।
- 31. कब्बा लेने से पहले जल-मार्ग (water-course) बनाने या उसके हस्तांतरम्म के व्यय प्रार्थी चुकाएमा. यथास्थिति धारा 27 या धारा 29 के श्रधीन किसी भी प्रार्थी को तब तक उक्त भूमि या जल मार्ग (water-course) का कब्बा नहीं दिया जाएमा. जब तक उसने कलेक्टर द्वारा नामांबित (named) व्यक्ति को ऐसी राशि, जो कलेक्टर उक्त रूप में कब्बो में ली गई या हस्तांतरित भूमि या जलमार्ग के लिए श्रौर ऐसी किसी चृति के जिए, जो उक्त भूमि का श्रंकन करते समय या कब्बा लेने में हुई हो, प्रतिधन के रूप में निश्चित करे, उक्त कब्बे या हस्तांतरम्म से उद्भूत समस्त व्ययों के साथ न चुका दी हो।

प्रिंधन निश्चय करने में प्रिक्रिया.—इस धारा के ऋषीन दिये जाने वाले प्रतिधन का निर्धारण धारा 66 में दी गई व्यवस्था के ऋनुसार किया जाएगा, किन्तु कलेक्टर यदि उस व्यक्ति की, जिसे प्रतिधन दिया जाना है, ऐसी इच्छा हो तो प्रतिधन का पारिनिण्य इस प्रकार से वब्जे में की गई या इस्तांतरित भूमि या जल मार्ग (water-course) के सम्बन्ध में देय लगान (rent charge payable) के रूप में कर सकेगा।

प्रतिधन श्रीर व्ययों की वस्तूली. — यदि उक्त प्रतिधन श्रीर व्यय उसे पाने के श्रिधिकृत व्यक्ति की मांग पर नहीं चुकाए जाते तो धनराशि कलेक्टर वस्तूल कर सकेगा श्रीर वस्तूल हो जाने पर उसे पाने के अधिकृत व्यक्ति की चुका देगा।

- 32. वे शर्तें, जो उसर्रुपार्थी पर बाध्य होंगी, जिसे कब्जा दिया गया हो .—(1) जब उक्त किसी प्रार्थी ने धारा 31 में वर्णित शर्तों का उचित रूप से पालन किया हो तो उसे उपरोक्त भूमि या जलमार्ग (water-course) का कब्जा दे दिया जाएगा ख्रीर तदुपरान्त उस पर ख्रीर उसके स्वस्व के प्रतिनिधि पर निम्नलिखित नियम ख्रीर शर्तें बाध्य होंगी:—
 - (क) समस्त दशास्रों में ---

प्रथम. — उक्त जलमार्ग (water-course) के निर्माण से पूर्व विद्यमान रास्ते स्त्रीर उस से स्त्रवहद्ध जलोत्सारण के लिए स्रीर स्त्रास पास की भूमियों की मुविधा के लिए उस के स्त्रार पार उपयुक्त यातायात का प्रकथ करने के लिए स्रावश्यक कर्म प्रार्थी द्वारा बनाए जाएंगे स्त्रीर वह या उस के स्वत्वों का प्रतिनिधि कलेक्टर के समाधानानुसार उनका संधारण करेगा।

दूसरी. - धारा 28 के उपबन्धों के ऋधीन जलमार्ग के लिए कब्जे में की गई भूमि केवल उक्त जल-मार्ग (water-course) के प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाई जाएगी।

तीसरी. — प्रम्तावित जलमार्ग (water-course) प्रार्थी द्वारा, जब प्रार्थी की भूमि का कब्जा प्राप्त होता है, उसके पश्चात् एक वर्ष के मध्य, कलेक्टर के समाधानानुसार पूरा किया जाएगा।

(ख) उन दशात्रों में जहां भूमि पर कब्जा या जलमार्ग (water-course) का हस्तांतरग् लगान (rent charge) की शर्तों (terms) पर होता है—

चौथी.-प्रार्थी या उसके स्वत्व का प्रतिनिधि उस समय तक, जब तक वह उक्त भूमि या जलसार्ग

- 10. उन्नित शुल्क (betterment charges) की अनुमूची का ऋतिम होना.— धारा 9 को उपधारा (4) के अन्तगत प्रकाशित अन्तिम अनुमूचियों के अधीन लगाए जा सकने बाले उन्नित-गुल्क ग्रंतिम होंगे।
- 11. उन्नित शुल्कों की मांग.—(1) जब घारा 9 की उपधारा (4) के अधीन राजपत्र में उन्नित-शुल्कों की अनुस्ची प्रकाशित कर टी गई हो ता कलेक्टर उनके सम्बन्ध में एक मांगपत्र (demand statement) विहित रूप में तैयार करेगा, जिसमें उन राशियों का पूरा ब्योरा होगा, जिसे देने के लिए प्रत्येक मुस्वामी या उस मूमि में स्वत्व रखने वाला ब्यक्ति उत्तरदायी होगा, आर मांग की सूचना की तामील उस ब्यक्ति पर करवाएगा।
- (2) कोई भी भृस्त्रामी या उनत भूमि में स्तत्व रखने वाला व्यक्ति ऐसी अवधि में, जो मांग की सूचना के दिनांक से विहित् की जाए, मांग या उसके किसी भाग पर आपित करते हुए एक याचिका (petition) कलेक्टर के पास भेज सकेगा और याचिका का विहित रीति से निर्णय किया जाएगा और इस सम्बन्ध में दिये गए आदेश पर विहित रीति से अपील की जा सकेगी।
- (3) मांग की सूचना के अन्तर्गत देय कोई भी राशि, उन आदेशों के प्रतिबन्धाधीन, जो उपधारा (2) के अन्तर्गत अपील के अधीन दिए गए हों, विहित समय में चुकाई जाएगी।
- 12. कुछ योजनाओं का उन्नित-शुल्क आरोपण से मुक्त होना.—शासन किसी भी योजना या योजना-श्रेणी (class of schemes) को जो नहर की परिभाषा के अन्तर्गत हो, उन्नित-शुल्क आरोपण से मुक्त कर सकेगा, यदि आनश्यक परिश्च्छा के उपरान्त शासन का यह समाधान हो गया हो कि ऐसी योजना या योजनाओं से भूमि के मूल्य में या उस की वार्षिक उपज में सारत: कोई वृद्धि नहीं हुई है।
- 13. उन्नित-शुल्कों की वसूली का स्थान.—जब किमी चेत्र में फसल न हुई हो तो इस अधिनियम में या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी शासन ऐसी अविध तक, जो वह उचित समक्ते, ऐसे उन्नित शुल्कों की वस्ती का सम्पूर्णक्षेण या अंशरूपेण स्थान कर सकेगा।
- 14. उन्नित-शुल्कों का श्रमिभाजन (Apportionment of betterment charges).—उन्नित-शुल्क (betterment charges) भूस्वामी श्रौर उक्त भूमि में स्वस्व रखने वाले व्यक्ति से विहित श्रनुपात में वसूल किए जा सकेंगे:

परन्तु एक ही भूमि के भूस्वामी श्रीर उस में स्वत्व रखने वाले श्रन्य व्यक्तियों के मध्य कोई भी उक्त श्रीभभाजन करते समय उस भूमि से सम्बद्ध उक्त व्यक्तियों के मध्य उपज या पूंजी मूल्ब (capital values) की बटाई से सम्बन्धित प्रचलित व्यवहार (prevailing practice) का उचित ध्यान रखा जाएगा:

परन्तु यह भी कि बहां एक से ऋधिक भूस्वामी हो उस ऋवस्था में भूस्वामी से वयूल किए जाने योग्य भाग के लिए वे संयुक्त ऋौर पृथक रूप से (jointly and severally) उत्तरदायी

होंगे। त्रीर इसी प्रकार जहां भूमि में स्वत्व रखने वाले व्यक्ति एक से ऋधिक हीं उस ऋवस्था में वे उन से वसल किए जाने योग्य भाग के लिए संयुक्त ऋौर पृथक रूप से (jointly and severally) उत्तरदायी होंगे।

- 15. उन्तिति-गुल्क (betterment charge) भूमि पर एक भार होगा.—इस अध्याय के उपवन्धों के अधीन देय उन्तित-गुल्क को भूराजस्व के सिवाए भूमि से सम्बन्धित अपन्य समस्त देथ भारों (charges) से पूर्वता दी जाएगी और उस सीमा तक वह भूमि पर एक भार समभा जाएगा और भूराजस्व के बकाया की भान्ति वसूल किया जा सकेगा।
- 16. उन्नित-शुल्क का प्रभाव किसी भी अन्य आरोप्य शुल्क पर नहीं पड़ेगा.— इस क् अध्याय के उपबन्धों के अधीन किसी भूमि के सम्यन्ध में देय उन्नित-शुल्क से, तत्काल प्रचिलत अन्य किसी भी विधि के अधीन आरोप्य अन्य किन्हीं करों या शुल्कों (rates or charges) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 17. दीवानी न्यायालयों के ऋधिकारचेत्र पर स्कावट इस अध्याय के अधीन किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य से सम्बद्ध विषय के सम्बन्ध में किसी भी दीवानी न्यायालय को अधिकार चेत्र प्राप्त नहीं होगा।
- 18. कायंबाहियों से मुक्ति.— उस अबस्था में जहां संधारण के लिए लाभधारी उत्तरदायी हों ऐसी किसी हानि के लिए, जो लाभधारियों के संधारण से सम्बन्धित प्रमाद के कारण नहर का जल व्यर्थ होने या रुक जाने से हुई हो या शासन द्वारा संख्त नहरों की दशा में ऐसे किसी कारण से हुई हो, जो शासन के बस से बाहिर के हों या कलेक्टर द्वारा नहर में की गई मरम्तीं, आपरिवर्तनों या वृद्धियों के कारण हुई हो या कलेक्टर द्वारा उस में जलप्रवाह के उचित नियंत्रण के लिए किये गए उपायों से हुई हो या सिंचन के स्थापित कम (established course) का उस अवस्था में संधारण करने से हुई हो, जहां कलेक्टर ऐसा करना आवश्यक समभे, शासन के विषद्ध प्रतिधन या उन्नतिशुलकों की वापसी के हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।
- 19. नियम बनाने की शिक्ति.—(1) शासन राजपत्र में ऋधिस्त्रना दे कर इस अध्याय के उपवन्धों के प्रयाजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकेगा।
- (2) विशेषतया श्रौर पूर्ववर्ती शक्ति की सामान्यता पर प्रतिकृल प्रभाव न डालते हुए इन नियमों द्वारा निम्नलिखित समस्त या उन मैं से किसी विषय की व्यवस्था की जा सकेगी, श्रर्थात्—
 - (क) वह रीति, जिसके अनुसार इस अध्याय के अधीन स्चनाएं या उन्नित-शुल्कों की अनुस्चियां प्रकाशित की जाएंगी;
 - (ख) वह रीति, जिसके अनुसार सिचाई की योजना में किन्हीं भूमियों या भूमि की किन्हीं श्रे शियों (class of lands) से सम्बद्ध उन्नित-शुल्कों के मान (rates) की गणना की जाएगी;
 - (ग) धारा 11 की उपधारा (1) के ऋषीन मार्गपत्र बनाने का रूप (form) स्त्रीर उन्हें तैयार करने की प्रक्रिया;

- (घ) मांग की सूचनाएं तयार करने का ढंग और उनकी तामील की रीति:
- (च) वह समय, जिस के मध्य धारा 11 के अधीन मांग की मूचनाओं के विरुद्ध आपत्तियों दायर की जा सकेंगी, उन आपत्तियों का निश्चय करने की प्रक्रिया और वे प्राधिकारों जिन के पास और वह रीति जिसके अनुसार और वे शर्तें जिन के प्रतिवन्धाधीन, उन सूचनाओं के विरुद्ध अपीलें दायर की जा सकेंगी;
- (छ) वह समय, जिस के मध्य मांग की सूचना के पश्चात् उन्नित-शुल्क (betterment charges) देय होंगे, श्रौर वह रीति, जिस के अनुसार उन्त शुल्क वस्ल किए जा सकेंगे;
- (ज) वह रीति, जिसके अनुसार भूस्वामियों और भूमि मैं स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों के मध्य उन्नति शुल्कों का अभिभाजन किया जा सकेगा;
- (भ) वह रीति, जिसके अनुसार और वे शर्तें जिन के प्रतिक्याधीन कोई भी पदाधिकारी इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन अपनी शक्तियां प्रयोग करेगा; और
- (ट) अन्य ऐसा कोई भी विषय, जिसे इस अध्याय के अधीन विहित करने की आवश्यकता हां।

ऋध्याय 4

श्रनुसूची 1 में समाविष्ट नहरों पर श्वर्तनीय उपबन्ध

- 20. यह म्हाध्याय म्हानुमृची 1 में समाविष्ट नहरों पर ही प्रवतनीय होगा.— उस दशा को स्होहकर, जब शासन धारा 80 के ऋधीन म्हान्यथा निदेश दे, इस म्हाध्याय के उपबन्ध केवल उन्हीं नहरों पर प्रश्नुत होंगे, जो अनुमूची 1 में तत्कालार्थ समाविष्ट हों।
- 21 कलेक्टर की सामान्य शिक्तियां. (1) किसी नहर या जल माग (water-course) मैं या नहर अथवा जलमार्ग पर किन्हों भी अधिकारों के विद्यमान होते हुए भी कलेक्टर—
 - (क) उन नहरों के कुशल संधारण (efficient maintenance) श्रौर उन्हें चलाने के लिए या उनके जल को उचित रूप से बांटने के लिए उन के नियन्त्रण, प्रबन्ध श्रौर संचालन की समरत शक्तियां प्रयोग कर सकेगा, श्रौर
 - (ख) जब कभी श्रौर जब तक जलमार्ग, जलद्वार या मोरी की प्रथागत उचित मरम्मत नहीं की जाती या ऐसे जलमार्ग, जलद्वार या मोरी को जान बूक्त कर चृति पहुँचाई जाती है या श्रम् चत रूप से उस की बृद्धि की जाती है, जिस से किम व्यक्ति को, या जलद्वार या मोरी की दशा में, किसी जलमार्ग या किसी व्यक्ति को, जल प्रदाय किया जाता हो, तो ऐसे ब्ल मार्ग, जलद्वार या मोरी श्रथवा किसी व्यक्ति को जल का प्रदाय रोक सकेगा।
- (2) किसी ऐसी चृति के लिए, जो उपघारा (1) के अघीन दिए गए आदेश से हुई हो शासन के विरुद्ध चृतिपूर्ति (compensation) के लिए कोई भी दावा (claim) प्रवर्त्नीय नहीं होगा, किन्तु ऐसा व्यक्ति, जिस की हानि उपघारा (1) (क) के अघीन दिए गए आदेश से हुई हो,

जलप्रदोग के लिए देय साधारण शुल्कों (ordinary charges) की ऐसी वापसी की मांग कर सकेगा जो राज्यशासन द्वारा प्राधिकृत हो :

परन्तु यदि धारा 40 (1) के अधीन तैयार किए गए या पुनरावृत्त अधिकार-अभिलेख में या ऐसे अधिकार-अभिलेख, जो धारा 40 (3) के अधीन इस आधिनयम के अन्तर्गत बनाया गया दुर्गा समका गया हो, में प्रविष्ट या शासन और किसी व्यक्ति के मध्य किसी निर्वन्ध में अगीकृत कोई जल अधिकार उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी कार्य के परिणाम स्वरूप सारतः कम हो जाता है तो कलेक्टर उस व्यक्ति के पत्त में उस के अधिकार की कमी के सम्बन्ध में धारा 66 के अधीन प्रतिधन (compensation) का परिनिर्णय करेगा।

- (3) इन्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 के अधीन नहर का जल प्रयोग करने के किसी भी अधिकार का अजेन नहीं होना या वह उसके अधीन अर्जित किया गया हुआ नहीं समक्ता जाएगा और न ही राज्य शासन किसी व्यक्ति को जल देने के लिए बाध्य होगा।
- 22. राज्य शासन की प्रतिधन देने के पश्चान् किसी भी अनुस्चित नहर से सम्बद्ध अधिकार का निजम्बन यासमाप्ति करने की शाकि.—(1) शासन किसी भी समय किसी भी ऐसे अधिकार को निजम्बन या समाप्त कर महेगा, जिसका किसी भी व्यक्ति को नहर में या नहर पर इक प्राप्त हो, यदि ऐसे अधिकार-प्रयोग से अन्य सेचकों के हित पर या नहर के अन्छे प्रवन्ध, नहर को उन्नित या उसकी हु दे पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ता हो।
- (2) ऐसी प्रत्येक दशा में राज्य शासन ऐसे न्यिक को, जिस का अधिकार निलम्बित या समाप्त हो गया हो प्रतिधन दिलबाएगा, जो धारा 66 के अधीन कलैक्टर द्वारा निर्धारित (assess) किया जाएगा। इस धारा के प्रयोजनार्थ प्रतिधन नियत करने में कलेक्टर अधिकार के प्रकार और उस अवधि, जिस के मध्य धारा का लाम उठाया गया हो, और ऐसे निलम्बन या समाप्ति से सम्भावित कृति damage) का ध्यान रखेगा।
- 23. प्रवेश करने और सर्वे इत्यादि करने की शकिन किलेक्टर या अन्य व्यक्ति, जो कलेक्टर के सामान्य या तिशेष आदेश से कार्य कर रहा हो, किसी भी ऐसी भूमि पर प्रवेश कर सकेगा, जो नहर से संलग्न हो या जिस में से कोई नहर बनाने का विचार हो, और वहां पर सर्वे या समतलन (level) कर सकेगा तथा अधीभूमि की खुटाई या उसमें छेदन (bore) कर सकेगा;

श्रीर उपयुक्त भूमि-चिन्ह (land-marks), तलिन्ह (level-marks) श्रीर जल-मापन यन्त्र (water gauges) बना तथा लगा सकेगा ;

श्रीर श्रन्य समस्त ऐसे कार्य कर सकेगा, जो उक्त कलेक्टर के प्रवन्धाधीन विद्यमान (existing) या परियोजित (projected) नहर से सम्बद्ध किसी परिष्टच्छा के उचित श्रामियोजन (prosecution) के लिए श्रावश्यक हों;

भूमि माफ करने की शक्ति. और जहां अन्यथा ऐसी परिष्ठका पूर्ण न हो सके कलेक्टर या उक्त अन्य व्यक्ति किसी मी खड़ी फसल या बाड़ या जंगल या उस के माग-को काट सकेगा और संफ कर सकेगा; जल प्रदाय (water-supply) का निरीत्ताण श्रीर श्रानियमन करने की शिक्ति.—श्रीर किसी भी ऐसी भूमि, भवन या जल-मार्ग (water-course) पर, जिस के लिए कोई जल कर (water rate) वमूल किया जा सकता हो, या मम्पूर्ण श्रयवा श्रांशरूपेण परिहृत (remitted) हो या उसके भूराजस्य में स्माविष्ट हो, प्रदत्त-जल के प्रयोग का निरीत्त्रण या श्रानियमन करने या उससे सिंचित श्रयवा जल-कर (water-rate) से प्रमाग्ति भूमि को मापने श्रीर ऐसे समस्त कार्य करने के लिए प्रवेश कर सकेगा, जो उक्त नहर का उचित श्रानियमन श्रीर प्रवन्ध करने के लिए श्रावश्यक हों;

घरों में प्रवेश करने के अभिप्राय की सृचना. परन्तु यदि उक्त कलक्टर या व्यक्ति रहने के मकान से संयोजित किसी भवन या संलग्न आंगन या बाग में प्रवेश करना चाह, जिसे किसी नहर से बहता हुआ पानी न दिया जाता हो, तो वह ऐसे भवन, आंगन या बाग के स्वामी (occupier) को सात दिन पहले अपने इस अभिप्राय की लिखित सचना देगा;

प्रवेश द्वारा हुई चिति के लिए प्रतिधन — इस धारा के अधीन प्रवेश करने की प्रत्येक दशा में, कलेक्टर इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर ऐसी चिति के लिए, जो इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही करने से हो जाए, प्रतिधन का निर्धारण और उसकी चुकती करेगा।

24. मरम्मतों श्रीर श्राकस्मिक घटनाश्री (accidents) की रोकथाम के लिए प्रवेश करने की शक्ति —िकसी नहर में किसी श्राकस्मिक घटना (accident) के हो जाने पर या श्राकांस्मक घटना का भय होने पर कलेक्टर श्रथवा इस हेतु उस के सामान्य या विशेष श्रादेशों के श्रधीन कार्य करने वाला व्यक्ति उक्त नहर से संलग्न भूमियों पर प्रवेश कर सकेगा श्रीर वे समस्त कार्य कर सकेगा, जो श्राकस्मिक घटना को रोकने श्रीर मरम्मत करने के लिए श्रावश्यक हों;

भूमि की च्रिति के लिए प्रतिधन. — प्रत्येक ऐसी दशा में कलेक्टर इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिए जाने पर ऐसी किसी भी च्रित (damage) के लिये, जो इस धारा के अधीन की गई किसी कार्यवाही से हो जाए, धारा 66 के अधीन प्रतिधन निर्धारित करेगा और चुकाएगा।

- 25. नहर की मिट्टी जमा करने छोर किनारों की मरम्भत के लिये मिट्टी खोदने के हेतु नहर से संलग्न भूमि पर कब्जा करने की शांकत छोर चिति के लिए प्रतिधन.—
 (1) क्लेक्टर या इस हेतु उसके सोमान्य या त्रिशेष आदेशाधीन कार्य करने थाला कोई भी व्यक्ति नहर से ऐसे अन्तर (distance) तक, जो शासन नियमों द्वारा निश्चित करे, किसी नहर से संलग्न भूमि पर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए कब्जा कर सकेगा:—
 - (क) नहर से खोदी गई मिट्टी उस भूमि पर जमा करने के लिए, या
 - (ख) नहर की मरम्मत के हेतु उस भूमि से मिही खोदने के लिए,

इस सम्बन्ध में कलेक्टर को प्रार्थनापत्र दिए जाने पर वह ऐसी किसी भी चृति (damage) के लिए, जो इस धारा के ऋधीन किसी कार्यवाही से हो जाए, प्रतिधन नियत करेगा और चुकाएगा।

(2) जिम भूमि पर उपधारा (1) के ऋधीन किसी प्रयोजन के लिए इस ऋधिनियम का श्रारम्भ होने के पश्चान् कब्जा किया गया हो ऋौर वह तीन वर्ष से ऋधिक ऋविध तक ऐसे कब्जे में रही हो उसका स्वामी यह ऋषेज्ञा कर सकेगा कि उक्त भूमि धारा 55 के उपभन्धों के ऋनुसार स्थायी रूप से ऋार्जित की जाएगी।

26. श्रःतवंतीं जल मार्ग (intervening water-course) द्वारा जल-पदाय (supply of water). — जब कमी कलेक्टर को किसी नहर से जल देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाए श्रौर उसे यह श्रावश्यक मालूम हो कि इस प्रकार जल दिया जाना चाहिए श्रौर किसी विद्यमान जलमार्ग द्वारा ही दिया जाना चाहिए, तो वह ऐसे जलमार्ग (water-course) के संधारण (maintenance) के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को उस दिन, जो तकत सूचना के दिनांक से चौदह दिन पूर्व का न हो, यह कारण बतलाने की सूचना देगा कि उक्त रूप से जल क्यों न दिया जाए श्रौर उस दिन परिपृच्छा करने के उपरान्त कलेक्टर यह निश्चय करेगा, श्राया कि उक्त जल मार्ग (water-course) द्वारा जल दिया जाए श्रौर यदि दिया जाए तो किन शतों पर दिया जाए ।

पार्थी तब तक उक्त जलमार्ग (water-course) का जल प्रयोग करने का ऋधिकारी नहीं होगा जब तक उसने उक्त जलमार्ग के ऐसे किसी भी परिवर्तन के, जो उसे उस में से जल देने के लिए ऋावश्यक हो, व्यय चुका न दिए हों ऋौर उक्त जल-प्रदाय (water-supply) के प्रथम व्यय का वह भाग भी न चुका दिया हो जो क्लेक्टर निश्चित करें। उक्त प्रार्थी उक्त जल-मार्ग (water-course) के संधारण-व्यय (cost of maintenance) के ऋपने भाग का उस समय तक उत्तरदायी भी रहेगा, जब तक बह उसका प्रयोग करता रहे।

- 27. नया जल-मार्ग (water-course) बनाने के लिए प्रार्थनापत्र. कोई भी व्यक्ति, जो नया जलमार्ग (water-course) बनाना चाहता हो, कलेक्टर को एक लिखित प्रार्थनापत्र दे सकेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे :—
 - (त्र) कि उस ने उस भूमि के, जिस में से वह उक्त जल-मार्ग (water-course) ले जाना चाहता हो, स्वामियों से उतनी भूमि पर जितनी उक्त जलमार्ग (water-course) के लिए ब्रावश्यक होगी, कब्जे (acquire) का ब्रावकार प्राप्त करने का ब्रायक्त प्रयन्त किया है;
 - (श्रा) कि वह अपनी स्रोर से और अपने व्यथ पर उक्त ऋधिकार अर्जित करने के लिए समस्त स्रावश्यक कार्य कलेक्टर द्वारा किए जाने की इच्छा करता है:
 - (इ) कि वह उक्त अधिकार अर्जन करने में और जल-मार्ग (water-course) बनाने के समस्त व्यय स्वयं वहन (defray) करने के योग्य है।
 - 28. तदुपरान्त कलेक्टर की प्रिकेश.—यदि कलेक्टर का यह विचार हो कि —
 (ऋ) ऐसा जल-मार्ग (water-course) बनाना आवश्यक है, और
 (ऋ) प्रार्थना पत्र के विवरण सत्य हैं,

तो वह प्रार्थी का ऐसी राशि, जो कलेक्टर प्रारम्भिक कार्यवाहियां का व्यय जुटाने के लिए त्रावश्यक समभे, त्रीर प्रतिधन की ऐसी राशि, जिस के सम्बन्ध में वह यह विचार करें कि उक्त राशि धारा 31 के त्राधीन देय होने की सम्भावना है, जमा करने

के लिये कहेगा श्रीर उक्त राशि जमा कर दिए जाने पर वह उक्त जल-मार्ग (water-course) के श्रिधिकतम उपयुक्त रेखाकरण (alignment) के सम्बन्ध में परिपृच्छा करवाएगा श्रीर उस भूमि का श्रांकन करेगा, जिस पर उस की सम्मित में जल-मार्ग बनाने के लिए कन्जा करना श्रावश्यक होगा श्रीर तुरन्त प्रत्येक ऐसे ग्राम में, जिस में से जल-मार्ग (water-course) ले जाने का विचार हो, इस श्राश्य की एक मुचना प्रकाशित करेगा कि उक्त ग्राम की इतनी भूमि इस प्रकार श्रांकित की गई है।

- 29. विद्यमान जलमार्ग (water-course) के हम्तांतरण् (transfer) के लिए प्रार्थना पत्र कोई भी व्यक्ति, जो यह चाहता हो कि कोई विद्यमान जल-मार्ग (water-course) उसके वर्तमान स्वामी से उसे हस्तांतरित कर दिया जाए तो वह निम्नलिखित रूप में विवरश् देते हुए कलेकटर के पास प्रार्थना पत्र दे सकेगा—
 - (त्र) कि उसने उक्त जल-मार्ग (water-course) के स्वामी में उक्त हस्तांतरण करने का त्रामफल प्रयत्न किया है;
 - (त्रा) कि उस की यह इच्छा है कि क्लेक्टर उस की स्रोर से स्रौर उसके व्यय पर उक्त हस्तांतरण के लिए समस्त स्रावश्यक कार्य करे;
 - (इ) कि वह उक्त हस्तांतरण के समस्त व्यय जुटा सकने के योग्य है। इस के पश्चात् प्रक्रिया.—यदि कलेक्टर का यह विचार हो कि—
 - (क) उक्त हस्तांतरगाँ उस जल-मार्ग (water-course) से सिन्दाई का ऋच्छा प्रवन्भ करने के लिए ग्रावश्यक है, श्रौर
 - (ख) प्रार्थ ना पत्र में दिए गए विवरण टीक हैं,
 - तो कनेक्टर प्रार्थी को अपने पाम ऐसी राशि, जो वह उक्त हस्तांत ए के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यवाहियों का व्यय जुटाने और प्रतिधन की ऐसी राशि, जो धारा 31 के उपबन्धों के अप्रीन देय हो जाए, जमा कराने के लिए कहेगा और ऐसी राशि जमा कर दिए जाने पर वह प्रार्थना पत्र की एक स्वाना प्रत्येक प्रभावित ग्राम में प्रकाशित करेगा।
 - 30. जल मार्गी (water-courses) के हस्तांतरण या निर्माण पर आपत्तियां, उनकी परिवृच्छा और उनका निश्चयं.—(1) जब यथास्थिति, धारा 28 या धारा 29 के अधीन स्चना-प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन के मध्य ऐसी भूमि या जलमार्ग (water course) में, जो स्चना में निर्दिष्ट हो, स्वत्व रखने वाला व्यक्ति कलेक्टर के पास उस संरचना (construction) या हस्तांतरण (transfer), जिसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया हो, से सम्बद्ध अपनी आपत्तियों का विवरण देते हुए उपरोक्त रूप से प्रार्थना पत्र देता है, तो कलेक्टर स्वत्व रखने वाले अन्य व्यक्तियों को यह स्चना देगा कि वह ऐसे दिन, जो उक्त स्चना में विणित होगा, या अन्य ऐसे दिन, जिस के लिए कार्यवाहियां स्थिगत की जाएं, विवादग्रस्त विषय की परिवृच्छा प्रारम्भ करेगा या स्थितिअनुसार उक्त आपत्तियों की मान्यता के सम्बन्ध में परिवृच्छा आरम्भ करेगा।

- (2) इस प्रकार नामांकित दिनांक या उपराक्त अनुवर्ती दिनांक का कलेक्टर स्थिति अनुमार विवाद या आपित की मुनवाई और निश्चय आरम्भ करेगा।
- 31. कब्जा लेने से पहले जल-मार्ग (water-course) बनाने या उनके हस्तांतरण के व्यय प्रार्थी चुकाएगा. यथास्थित धारा 27 या धारा 29 के अधीन किसी भी प्रार्थी को तब तक उक्त भूमि या जल मार्ग (water-course) का कब्जा नहीं दिया जाएगा जब तक उसने कलेक्टर द्वारा नामांकित (named) व्यक्ति को ऐसी राशि, जो कलेक्टर उक्त रूप में कब्जो में ली गई या हस्तांतरित भूमि या जलमार्ग के लिए और ऐसी किसी चांत के लिए, जो उक्त भूमि का अंकन करते समय या कब्जा लेने में हुई हो, प्रतिधन के रूप में निश्चित करे, उक्त कब्जे या हस्तांतरण से उद्भूत समस्त व्ययों के साथ न चुका दी हो।

प्रिंधन निश्चय करने में प्रिक्रिया.— इस धारा के ऋधीन दिये जाने वाले प्रतिधन का निर्धारण धारा 66 में दी गई व्यवस्था के ऋनुसार किया जाएगा, किन्तु कलेक्टर यदि उस व्यक्ति की, जिसे प्रतिधन दिया जाना है, ऐसी इच्छा हो तो प्रतिधन का पारेनिए य इस प्रकार से व्यक्ते में की गई या इस्तांतरित मूम या जल मार्ग (water-course) के सम्बन्ध में देय लगान (rent charge payable) के रूप में कर सकेगा।

प्रतिधन स्रीर व्ययों की वाम्ली. — यदि उक्त प्रतिधन स्रीर व्यय उसे पाने के स्रिधिकृत व्यक्ति की मांग पर नहीं चुकाए जाते तो धनराशि कलेक्टर वसल कर सकेगा स्रीर वस्ल हो जाने पर उसे पाने के स्रिधिकृत व्यक्ति को चुका देगा।

32. वे शर्तें, जो उम्रुपार्थी पर बाध्य होंगी, जिसे कब्जा दिया गया हो .—(1) जब उक्त किसी प्रार्थी ने धारा 31 में वर्णित शर्तों का उचित रूप से पालन किया हो तो उसे उपरोक्त भूमि या जलमार्ग (water-course) का कब्जा दे दिया जाएगा ख्रोंर तदुपरान्त उस पर ख्रोर उसके स्वत्व के प्रतिनिधि पर निम्नलिखित नियम ख्रौर शर्तें बाध्य होंगी:—

(क) समस्त दशास्रों मैं —

प्रथम.— उक्त जलमार्ग (water-course) के निर्माण से पूर्व विद्यमान रास्ते ग्रीर उस से ग्रायरुद्ध जलोत्सारण के लिए ग्रीर ग्रास पास की भूमियों की मुविधा के लिए उस के ग्रार पार उपयुक्त यातायात का प्रबन्ध करने के लिए ग्रावश्यक कर्म प्रार्थी द्वारा बनाए जाएंगे ग्रीर वह या उस के स्वत्वों का प्रतिनिधि कलेक्टर के समाधानानुसार उनका संधारण करेगा।

दृस्तरी. - धारा 28 के उपबन्धों के ऋधीन जलमार्ग के लिए कब्जे में की गई भूमि केवल उक्त जल-मार्ग (water-course) के प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाई जाएगी।

तीसरी. -- प्रस्तावित जलमार्ग (water-course) प्रार्थी द्वारा, जब प्रार्थी की भूमि का कब्जा प्राप्त होता है, उसके पश्चात् एक वर्ष के मध्य, कलैक्टर के समाधानानुसार पूरा किया जाएगा।

(ख) उन दशाश्रों में जहां भूमि पर कन्जा या जलमार्ग (water-course) का हस्तातरग्। लगान (rent charge) की शतों (terms) पर होता है—

चौथी. - प्रार्थी या उसके स्वत्व का प्रतिनिधि उस समय तक, जब तक वह उदत भूमि या जलमार्ग

(water-course) पर काविज रहे, उसके लिए उस मान (rate) से ऋौर उन दिनों लगान देगा, जो कलेक्टर प्रार्थी को कब्जा देने के समय निश्चित करे।

पांचित्री यिंद इन नियमों के मंग से भूमि के कब्जे का अधिकार समाप्त हो जाए, तो उपरोक्त लगान (rent) चुकाने का उत्तरदायित्व तब तक जारी रहेगा जब तक प्रार्थी या उसके स्वत्व के प्रतिनिधि ने भूमि को उस की मौलिक दशा में वापम न कर दिया हो या उक्त भूमि की किसी भी चृति के लिए प्रतिधन के रूप से ऐसी राशि और ऐमे व्यक्तियों को, न चुका दी हो, जो क्लेक्टर निश्चित करे।

छटी. — कलेक्टर उस व्यक्ति का प्रार्थ नापत्र प्राप्त होने पर, जो उक्त लगान (rent) या प्रतिधन लेने का हकदार हो, देय लगान (rent) की राशि का निश्चय करेगा या उक्त प्रतिधन की राशि का निर्धारण करेगा ख्रोर यदि प्रार्थी या उसका स्वत्व का प्रांतिनिधि उक्त लगान (rent) या प्रतिधन नहीं चुकाता तो कलेक्टर उस राशि को उसके देय होने के दिनांक से 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय ब्याज के साथ वस्तुल करेगा ख्रोर वस्तुल हो जाने पर उसे उसके पाने के हकदार व्यक्ति को चुका देगा।

- (2) यदि इस घारा द्वारा विहित नियमों ऋौर शतों का पालन नहीं होता या इस ऋिषिनयम के अधीन निर्मित या हस्तांतरित जलमार्ग (water-course) का लगातार तीन वर्ष तक प्रयोग नहीं होता तो प्रार्थी या उसके स्वत्व के प्रतिनिधि का उक्त भूमि या जलमार्ग (water-course) में कृष्णा करने का ऋधिकार विलक्षल समान्त हो जाएगा।
- 33. कलेक्टर का नहरों में से मेशियां (outlets) बनाना . कलेक्टर किसी नहर से किसी जलमार्ग (water-course) में जल-प्रदाय (water-supply) करने का आनियमन करने के लिए जलद्वार (sluice) या मोरी (outlet) बना सकेगा या मरम्मत कर सकेगा या उसे आपरिवर्तित कर सकेगा।
- 34. दीर्घ अन्तर तक साथ साथ वहने वाले जलमार्गों (water-courses) को एक जलमार्ग (water-course) में वदलने की शक्ति.—(1) उन दशाश्रों में जहां जलमार्ग (water-courses) साथ साथ बहते हों या इस प्रकार स्थित हों कि वे जल-प्रदाय (water-supply) का मितव्ययिता से प्रयोग करने (economical use) में या उचित प्रवन्य करने में बाधा पहुंचाते हों तो कलेक्टर, यदि इस प्रयोजन के लिए उसे प्रार्थ नापत्र दिया जाए, या स्वयं स्वामियों से यह अपेद्या कर सकेगा कि वे उसके समाधानानुसार जलमार्गों (water-courses) को मिलाए या उनके सम्बन्ध में ऐसी पद्धति स्थानापन्न करें, जो उसने अनुमोदित कर दी हो।
- (2) यदि स्वामी ऐसे समय में, जो कलेक्टर नियत करे, उपधारा (1) के ऋधीन उसके द्वारा दिए गए ऋगदेश का पालन न कर सकें, तो वह स्वयं कर्म निष्पादित कर सकेंगा।
- (3) यदि कहीं उपधारा (1) या उपधारा (2) के श्रधीन कोई जलमार्ग (water-course) पुनः वनाया गया हो या नई पद्धित स्थानापन्न की गई हो तो कलेक्टर जल का वह भाग नियत करेगा, जो जलमार्ग (water-course) को प्रयोग में लाने के श्रिधिकारी व्यक्ति प्रयोग करेंगे।
- 35. वृद्धियों (extensions), श्रीर श्रापरिवर्तनों (alterations) के लिए कब्ज़ करने के सम्बन्ध में प्रयोज्य प्रक्रिया किसी जलमार्ग को बनाने के लिए भूमि पर कब्ज़ा करने के हेत्र

यहां से पूर्व व्यवस्थित प्रिक्रिया किसी जलमार्ग (water-course) की किसी भी वृद्धि या त्रापरिवर्तन (alterations) के लिए या जल-मार्ग (water-course) की सफाइयों (clearances) की मिट्टी जमा करने के लिए भूमि पर कब्जा करने के सम्बन्ध में प्रयुक्त होगी।

- 36. धारा 34 के अधीन कर्म निष्पादन करने का व्यय किस के द्वारा देय होगा.— धारा 34 के अधीन प्रत्येक दशा में कर्म निष्पादन या पूर्ण करने का व्यय वह व्यक्ति या वे व्यक्ति चुकाएंगे, जो जलमार्ग (water-course) से लाभ उठा रहे हों, जिसका निश्चय प्रत्येक दशा में कलेक्टर करेगा।
- 37. लाभधारियों को श्रम प्रदाय करने का निर्देश देने की राज्यशासन की शक्ति राज्यशासन श्रीधसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि लाभधारी निम्नलिखित प्रयोजन में से किस, एक अथवा अधिक प्रयोजनों के लिए शासन को किसी नहर के सम्बन्ध में अप्रकुशल अम (unskilled labour) प्रदान करने के लिए बाध्य होगा:—
 - (क) निर्माण,
 - (ख) कुशलता पूर्व क संधारण,
 - (ग) रेत की वार्षिक सफाई,
 - (घ) नहर से सम्बद्ध कोई भी आवश्यक कर्म निष्पादित करना।
- 38. श्रम व्यय उन स्वामियों द्वारा वहन किया जाएगा, जो भूमि से लाभ उठाएं गे.—(1) शासन श्रिवस्चना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि कोई नहर किसी ऐसी सम्पदा या सम्पदाश्रों की भूमि सींचने के लिए, जो श्रिवस्चना में निर्दिष्ट की जाएंगी, किसी नदी (river), जलधारा (stream), उपनदी (creek) या श्रम्य नहर से बनाई जाएगी श्रौर ऐसी संरचना (construction) का व्यय सम्पूर्ण रूपेण या श्रांशरूपेण ऐसी भूमि के स्वामियों द्वारा वहन किया जाएगा, जिस को नहर से लीम पहेंचे।
- (2) इस ऋिनियम के उपबन्ध नई नहरों के सम्बन्ध में प्रयुक्त होंगे. अनुसूची 1 में समाविष्ट नहरों के निर्मागा, मरम्मतों, संधारण (maintenance) और प्रबन्ध से सम्बद्ध इस अधिनियम के उपबन्ध उपधारा (1) के अधीन जारी की गई शासकीय अधिसूचना के अनुपालन में बनाई गई नहरों पर प्रयुक्त होंगे।
- 39. धारा 38 के श्रधीन श्रिधिसूचना जारी करने पर कलेक्टर की शिक धारा 38 के श्रधीन श्रिधिसूचना जारी करने पर कलेक्टर समय समय पर सामान्य या विशेष श्रादेश द्वारा—
 - (क) प्रत्येक सेचक द्वारा दिए जाने वाले अम का या किये जाने वाले काम का परिमाण निश्चित कर सकेगा,
 - (ख) प्रबन्धित श्रमिकों की उपस्थिति, वितरण (distribution) श्रौर नियन्त्रण या काम करने के ढंग का श्रानियमन कर सकेगा,

- (ग) ऐसे किसी भी व्यक्ति का श्रम निर्धारित कर सकेगा, जो इस धारा के अधीन दिए गए आदेश का पालन नहीं कर पाता, और उक्त श्रम का व्यय वस्ज कर सकेगा, और
- (घ) इस प्रकार वस्तुल किए गए समस्त व्ययों की एक निधि बनाएगा और उसे उन नहरों, जिन पर अधिस्त्रना प्रयुक्त होती हो, के लिए काम पर लगाए गए अमिकें। की रसद पर या धारा 40 में विशिष्ट अधिकार अभिलेखों के उपवन्धों, यदि कोई हो, के प्रतिबन्धाधीन उनै के हित से सम्बद्ध अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए व्यय कर देगा:

परन्तु उपरोक्त रूप से निर्धारित व्यय उस राशि से ऋधिक नहीं बड़ेगा, जो अमिकों में से प्रत्येक ऐ.ने अमिक, जिसके विपय में ऋपराध हुआ है, के प्रत्येक दिन के अम के लिए उस चेत्र में प्रचित्त हो।

- 40. नहर के लिए अभिलेख तैयार करने की शांक (1) जब कभी राज्य शासन विशेष आदेश द्वारा या इस अधिनियम के प्राधिकाराधीन बन ए गए नियमों द्वारा ऐसा करने का आदेश दे, तो कलेक्टर किसी भी नहर के लिये एक आभिलेख तैयार करेगा या पुनरावृत्त करेगा, जिस में निम्नलिखित समस्त विषय या इन में से कोई भी विषय प्रदर्शित किया जाएगा, अर्थात्—
 - (क) सिंचाई की प्रथा या नियम,
 - (ख) जल के अधिकार और वे शर्ते, जिन के अनुसार अधिकार का उपयोग किया जाएगा,
 - (ग) चांक्कयां (mills) लगाने, उनकी मरम्मत करने उन के पुनर्निर्माण श्रौर चलाने के श्रिधिकः श्रौर वे शर्ते, जिन के श्रृतुसार इन श्रिधिकारों का उपयोग किया जाएगा, श्रौर
 - (घ) ऋत्य ऐसे दिपय, जो शासन इस सम्बन्ध में नियमों द्वारा विहित करे।
- (2) इस प्रकार तैयार किए गए या पुन्रावृत्त ऋभिलेख में की गई प्रविष्टियां ऋभिलिखित विषयों से सम्बद्ध विवाद के साद्ध्य के सामान संगत होंगी ऋौर तब तक सत्य मानी जाएंगी, जब तक उसके विपरीत प्रमाणित न हो जाय या विधिपूर्वक नई प्रविष्टियां न कर दी जाएं:

परन्तु किसी ऐसी प्रविष्टिका इस प्रकार ऋर्थ (construed) नहीं निकाला जाएगा, जिस्से इस ऋषिनियम द्वारा शासन को प्रदत्त कोई भी शक्तियां सीमित हो जाएं।

- (3) जब उपधारा (1) में कथित समस्त या किसी विषय को प्रदर्शित करने वाला ऋभिलेख शासन द्वारा स्वीकृत भूराजस्व के किसी बन्टोबस्त (settlement) के दौरान बनाया जा चुका हो ऋौर मालऋधिकारी द्वारा ऋभिप्रमाणित हो चुका हो, तो वह ऋभिलेख इस धारा के ऋधीन बनाया गया हुआ समक्ता जायगा।
- (4) स्वत्व रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति कलेक्टर या कलेक्टर के निदेशाधीन कार्य करने वाले व्यक्ति को इस धारा के अधीन ठीक प्रकार से अभिलेख तैयार करने के लिए समस्त आवश्यक सूचनः देने के लिए बाध्य होगा।

(5) जहां तक हो सके हिमाचल प्रदेश भ्राजस्व श्रिधिनियम, 1953 के श्रध्याय 4 के उपवन्ध प्रत्येक ऐसे श्रिभिलेख को तैयार करने श्रीर पुनरावृत करने में प्रवृत्त होंगे।

जल-कर (water-rates)

- 41. जल-कर (water-rates) लगाना .— (1) स्वामियों या सेन्कों के साथ बिए गए किसी निर्बन्ध की शतों (terms) के प्रतिबन्धाधीन, शासन ऋधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि प्राधिकृत रीति से किसी नहर का जल प्रयोग करने के लिए कर लगाया जाएगा या कर लगाए जाएंगे। ऐसे कर या करों को जल कर संग्रह करने के व्यय ऋौर पद्धति के संधारण (maintenance) ऋौर प्रवर्तन-व्ययों (operation) का उचित ध्यान रखते हुए । निश्चित किया जाएगा।
- (2) शासन ग्राधिस्त्रना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि उपरोक्त कर या करों (rate or rates) के म्रातिरिक्त या वरले में नहर का जल प्राप्त करने वालो भूमि पर तत्कालार्थ निर्धारित भूराजस्व, भूमि की श्रेणी अनिर्सिन्तत से सिन्चत में परिवर्तित हो जाने के परिणाम स्वरूप, बढ़ा दिया जाएगा:

परन्तु निर्धारण का नया कर (rate)उस से ऋधिक नहीं बढ़ेगा, जो बन्दोदस्त के समय उसी ग्राम में या उसकी निकटवर्ती उसी प्रकार की सिन्वित भूमियों के लिए नियत हो :

परन्तु यह भी कि शासन कुछ फसलों के लिए, जो शासन नियत करेगा, उक्त भूमियों पर ऐसे कर (rate) या करों (rates) के अनुमार निर्धारण जारी रखने की स्वीकृति दे सकेगा, जिस के अनुसार वे मींची जाने से टीक पूर्व निर्धारित की जाती थीं।

- (3) ऐसे जल के लिए जो प्राधिकार या प्राधिकृत रीति के बिना लिया गया हो या प्रयोग किया गया हो, शासन ऋधिसूचना द्वारा एक विशेष कर (special rate) भी लगा सकेगा।
- (4) जैसा कि शासन सामान्य या विशेष नियम द्वारा निरोशत करे उसके अनुसार उपधारा (1) या उपधारा (2) या उरधारा (3) के अधीन लगाए गए कर (rate or rates) उन व्यक्तियों पर आरोपणीय (leviable) होंगे, जो जल से लाभ उठा रहे हीं।
- (5) उपरोक्तानुसार निर्वन्ध (agreement) की शतों (terms) के प्रतिबन्धाधीन, इस धारा के ऋधीन ऋगोपित कर (rate) या करों (rates) की ऋगय उस रीति से व्यवस्थापित की जाएगी, जो शासन सामान्य या विशेष ऋदेश द्वारा निदेशित करे।
- (6) यदि ऐसे कारणों से जो कृपक के वश में न हों फसल नष्ट हो जाये तो उस वर्ष में लिए जाने ृ वाले जलकर की कृपक को छूट दी जाएगी ।
 - 42. अनिधकृत रूप से प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की पहचान न होने पर उत्तर-दाग्रित्व - यदि किसी जलमार्ग (water-course) से प्रदत्त जल अनिधकृत रूप में प्रयोग किया जाता है और यदि वह व्यक्ति, जिस के कार्य या प्रमाद से ऐसा प्रयोग हुआ हो, पहचाना न जा

सके तो वह व्यक्ति, जिस को भूमि पर ऐसा जल बहा हो, यदि उक्त भूमि को उस से लाभ पहुंचा हो, या यदि उक्त व्यक्ति की पहचान न हो सके, या यदि उक्त भूमि को उससे लाभ न पहुंचा हो तो वे समस्त व्यक्ति, जिन से उक्त जलमार्ग (water-course) से प्रदत्त जल के सम्बन्ध में वस्ती की जा सकती हो, संयुक्त रूप से या अन्यथा, जैसी परिस्थिति हो, उक्त प्रयोग का व्यय देने के उत्तरदायी होंगे।

- 43. जल के उपर्थ बहने पर शास्ति. यदि किसी जलमार्ग (water-course) मे प्रदत्त (supplied) जल को व्यर्थ बहने दिया जाता है स्त्रीर यदि कलेक्टर की परिपृच्छा से उम व्यक्ति की खोज न की जा सके, जिस के कार्य या प्रमाद से जल व्यर्थ बहा हो, तो वे समस्त ≯ व्यक्ति, जिन से ऐसे जलमार्ग (water-course) से प्रदत्त जल के सम्बन्ध में बस्ली की जा सकर्ता हो, संयुक्त रूप से इस प्रकार व्यर्थ बहे हुए जल का व्यय देने के लिए उत्तरदायी होंगे।
 - 44. शास्तियों के ऋतिरिक्त वसूली योग्य राशियां. अनिधक्रत प्रयोग या जल के व्यर्थ बहने के समस्त व्यय (charges) उक्त प्रयोग या हानि के कारण बहन की गई (incurred) शास्तियों के ऋतिरिक्त वसूल किए जा सकेंगे।

धारा 42 त्रीर धारा 43 के ऋधीन समस्त प्रश्नीं का निश्चय कलेक्टर करेगा ।

ऋध्याय 5

श्चनुसूची 2 में समाविष्ट नहरों पर प्रयुक्त हो सकने वाले उपबन्ध

45. यह अभ्याय अनुसूची 2 में समाविष्ट नहरों पर ही प्रवर्त नीय होगा.— (1) उस दशा को छोड़ कर जब शासन धारा 80 के अधीन अन्यथा निदेश दे इस अध्याय के उपबन्ध केवल उन्हीं नहरों पर प्रवृत्त होंगे, जो अनुसूची 2 में तत्कालार्थ समाविष्ट हों।

मैनेजर की नियुक्ति (2).—जब किसी नहर के स्वामित्व में कई भागीदार (share-holders) हों या जहां यह निश्चय करना कठिन हो कि कौन कौन से व्यक्ति भागीदार (share-holder) हैं या भागीदारों (share-holders) या उन में से किसी के स्वत्व की सीमा क्या है तो कलेंक्टर, यदि वहां कोई उपयुक्त मैनेजर या प्रतिनिधि न हो, एक लिखित उद्घोषणा या सूचना द्वारा भागीदारों (share-holders) से यह अपेदा कर सकेगा कि भागीदार (share-holders) एक नियत अवधि में किसी योग्य व्यक्ति को नहर का मैनेजर और अपना प्रतिनिधि नामांकित करें और उन के ऐसा न कर सकने पर वह स्वयं किसी व्यक्ति को उक्त नहर का मैनेजर और भागीदारों (share-holders) का प्रतिनिधि नियुक्त करेगा और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति तदुपरान्त वे समस्त कार्य और कार्यवाहियां कर सकेगा, जिन्हें भागीदार (share-holders) या उनमें से कोई भी व्यक्ति उक्त नहर के प्रवन्ध के सम्बन्ध में विधिपूर्वक करने के योग्य हो, और इस प्रकार उस ने, जो भी कार्य और कार्यवाहियां की हों, वे उक्त नहर के स्वामित्व में भाग रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर बाध्य होंगी।

46. राज्यशासन की धारा 40 के उपबन्धों को किसी भी नहर पर प्रयुक्त करने की शक्ति.—राज्य शासन अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि अभिलेखों की तैयारी और

पुनरावृत्ति से सम्बद्ध धारा 40 के समस्त या कोई भी उपवन्ध किसी भी नहर पर प्रयुक्त हो सकेंगे श्रीर उक्त घोषणा हो जाने पर उक्त उपवन्ध, जहां तक हो सके, तदानुसार प्रयुक्त होंगे।

- 47. नहर का नियंत्रण या प्रबन्ध, या दोनों श्रपने हाथ में ले लेने की शिक्त -(1) शासन के लिए अधिसूचना द्वारा किसी नहर का नियंत्रण या प्रबन्ध या दोनों निम्नलिखित
 के प्रविक्षिति अपने हाथ में ले लेना विधिवत् होगा--
 - (क) उक्त नहर के स्वामी द्वारा ऐसा करने की अनुमति दे देने पर ऋौर ऐसी शतों के (यदि कोई हों) अतिबन्धाधीन, जिन पर किसी भी दशा में उक्त ऋनुमित दी गई हो;
 - (ख) यदि परिष्टच्छा (enquiry) करने के पश्चात् शासन का यह समाधान हो जाता है कि स्वामी द्वारा या उसकी स्रोर से किए गए नियंत्रण या प्रबन्ध से उन व्यक्तियों की सम्पत्ति या स्वास्थ्य को द्रात्यंत हानि (grave injury) पहुं चती है, जिनके स्रासपड़ोस में भूमि है;
 - (ग) इस अधिनियम की धारा 50 के अधीन दिए गए आदेशों का जान बूक्त कर उल्लंघन करने या उल्लंघन करते रहने के परिणाम स्वरूप।
- (2) जब उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन किसी नहर का नियंत्रण या प्रबन्ध या टोनों अपने हाथ में ले लिए जाते हैं तो शासन उसके सम्बन्ध में समस्त या किसो भी ऐसे अधिकार और शिक्त का प्रयोग कर सकेगा, जिस का प्रयोग स्वामी उक्त रूप से नियन्त्रण या प्रबन्ध या टोनों को अपने हाथ में लेने की दशा में विधिवन् रूप से कर सकता था और उक्त शिक्तयां या उन में से कोई सी शिक्त किसी भी व्यक्ति को दे सकेगा, किन्तु कोई प्रतिकृत्न डिकी या निर्वन्ध न होने की दशा में शासन के लिए नहर से प्राप्त आय और व्यय का लेखा समय समय पर उक्त स्वामी को देना अनिवार्य होगा और शासन किसी भी समय स्वामी को नहर वापस कर सकेगा।
- 48. उक्त रूप से नियंत्रण या प्रबन्ध या दोनों शासन द्वारा ऋपने हाथ में ले लिये जाने के पश्चात् स्वामी का यह मांग करने का ऋधिकार कि नहर शासन द्वारा ऋर्जित (acquire) कर ली जाए. जब धारा 47 की उपधारा (1) के खन्ड (ख) या खन्ड (ग) के ऋधीन शासन द्वारा नहर का नियंत्रण या प्रबन्ध या दोनों ऋपने हाथ में ले लिया जाए ऋरेर उक्त नियंत्रण या प्रबन्ध छ: वर्षों से ऋधिक ऋबीध के लिए जारी रहे तो नहर का स्वामी लिखित सूचना दे कर कलेक्टर से यह ऋषेद्वा कर सकेगा कि उक्त नहर शासन ऋजित (acquire) कर ले।
- 49. स्वामी की मांग पर नहर श्राजित करने की शक्ति धारा 48 के श्रधीन सूचना मिलने पर राज्यशासन श्रधिसूचना द्वारा यह घोषित करेगा कि उक्त श्रधिसूचना में बतलाए गए दिनांक के पश्चात, जो श्रिधसूचना के दिनांक से तीन महीने बाद का होगा, उक्त नहर श्रजित (acquire) कर ली जाएगी श्रौर उक्त श्रिधसूचना देने के उपरान्त कलेक्टर धारा 57 श्रौर 58 में दी गई व्यवस्था के श्रगुसार कार्यवाही करेगा।
 - 50 सिंचाई और जल कर की सीमाएं नियत करने और जल विनंश्ए का श्रानियमन

करने की शक्ति.—राज्यशासन कलेक्टर से किसी नहर के सम्बन्ध में परिपृच्छा (enquiry) कराने के पश्चान्, निम्नालिखित समस्त या किसी विषय के सम्बन्ध में आदेश दे सकेगा, अर्थान्:—

- (क) वे सीमाएं नियत करना, जिन के भीतर भूमि उक्त नहर से सिंन्तित होगी;
- (ल) जैसा उचित समभा जाए उसके ऋनुसार स्वामी द्वारा ऋरोपण योग्य जलकरीं (water-rates) का परिमाण ऋरेर प्रकार ऋरेर वे शतें, जिन पर उक्त कर चुकाए जाए गे, निलम्बित, परिहृत या वापस किए जाएं;
- (ग) उक्त नहर में या उक्त नहर से जल प्रदाय और जल वितरण करने का श्रानियमन :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई ऐसी भृमि सिचाई में वंचित कर दी जाए, जिस की पिछलों लगातार तीन वर्ष से नहर से सिचाई की जा रही हो, या यदि इस धारा के अधीन कोई आदेश देने के कारण उक्त नहर से नहर के स्वामी की आय सारत: कम हो जाती हैं तो उक्त भूमि के स्वामियों या नहर के स्वामी को शासन द्वारा या इसके द्वारा निश्चित किए व्यक्तियों द्वारा ऐसा प्रतिधन दिया जाएगा जो कलेक्टर उचित समभे :

परन्तु यह भी कि यदि नहर के स्वामी ने शासन की सम्मति में अपनी शक्तियों का मनमाने या अनुचित (inequitable) ढंग से प्रयोग किया हो तो इस घारा के अधीन यह प्रतिधन का अधिकारी नहीं होगा।

- 51. कुछ दशाओं में नहर के जल-करों (water rates) का राज्य शासन द्वारा संप्रहण.—(1) राज्य शासन स्वामी की प्रार्थ ना पर नहर के सम्बन्ध में आरोपण यांग्य जलकरों (water-rates) का संप्रहण ऐसी अविध के लिए अपने हाथ में ले सकेगा, जिस से स्वामी सहमत हो, और तदुपरान्त—
 - (क) उक्त संग्रहण का श्रानियमन कर सकेगा ग्रीर उन व्यक्तियों का निश्चय कर सकेगा। जो संग्रहण का कार्य करेंगे;
 - (ख) यह निदेश दे सकेगा कि उक्त संग्रहण करने में की गई सेवा का भुगतान करने के लिए तीन प्रतिशत से अपनिधक राशि संग्रहीत राशि में से काट ली जाए।
 - (2) जिस अविध के लिए नहर के सम्बन्ध में आरोपण-योग्य जलकरों (water-rates) का संग्रहण शासन अपने हाथ में लेता है, उस अविध के लिए उक्त कोई भी कर वसल करने के हेतु कोई भी बाद दायर नहीं किया जाएगा।

अध्याय 6

समस्त नहरों के सम्बन्ध में प्रवर्तनीय उपकथ

52. यह ऋध्याय समन्त नहरों के सम्बन्ध में प्रवर्तनीय होगा.— सिवाए उसके, जिसकी आगे स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गई है, इस ऋध्याय के उपबन्ध समस्त नहरों के सम्बन्ध में प्रवर्तनीय होंगे चाहे वे नहरों ऋतुमूची 1 में समाविष्ट हो या ऋतुमूची 2 में।

53. स्वामी की सहमित या निर्णय का निश्चय कैसे किया जाएगा. —जब किसी नहर के सम्बन्ध में कोई ऐसा प्रश्न उठे, जिस का निश्चय इस श्रिधिनियम या इस के श्रन्तर्गत बनाए गए नियमों के श्रिधीन स्वामी की प्रार्थना, सहमित या निर्णय द्वारा किया जाना है श्रीर उक्त नहर का स्वामित्व एक से श्रिधिक व्यक्तियों में निहित हो श्रीर वे उस प्रार्थना, सहमित या निर्णय के सम्बन्ध में सहमत नहीं होते तो ऐसे किसी विषय में स्वामियों को श्रीर से कलेक्टर के लिए कार्यवाही करना विधियत होगा श्रीर उक्त किसी भी परिस्थित में कलेक्टर की प्रार्थना, सहमित या निर्णय हेसे प्रत्येक व्यक्ति पर बाध्य (binding) होगा, जो उक्त नहर के स्वामित्व में कोई भी भाग रखता हो।

उक्त प्रत्येक परिस्थिति में कलेक्टर ऐसे भागीदार या भागीदारों की इच्छाग्रों का उचित ध्यान रग्वेगा, जिनका स्वत्व श्राधिक हो श्रीर जब प्रश्न इस प्रकार का हो, जिसमें शासन को कोई कार्यवाही करनी पड़े तो उक्त भागीदार या भागीदारों की इच्छाएं मान्य होंगी श्रीर कलेक्टर द्वारा स्वीकार कर ली जाएंगी।

- 54. विवादों का निपटारा. पूर्ववर्ती धारा में दी गई व्यवस्था को छोड़ कर नहर या जलमार्ग (water-course) के स्वामित्व, निर्माण, प्रयोग या संधारण के सम्बन्ध में दो या ऋधिक व्यक्तियों के मध्य पारस्पिक ऋधिकारों ऋौर टायित्वों के बारे में जब कोई विवाद उठे ऋौर उक्त कोई भी व्यक्ति विवाद के विषय का विवरण देते हुए कलेक्टर को लिखित रूप में प्रार्थनापत्र दे तो कलेक्टर स्वन्त रावने वाले ऋन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को यह सूचना देगा कि वह उक्त सूचना में नामांकित दिन या ऐसे दिन, जिस तक कार्यवाहियां स्थागत की जाएं, विवाद के विषय में परिपृच्छा करने के लिए कार्यवाही करेगा।
- (2) इस प्रकार से नामांकित दिन या पूर्वोक्त ऋनुवर्ती दिन कलेक्टर विवाद की सुनवाई ऋौर निश्चय करने के लिए निम्नलिखित रीति से कार्यवाही करेगा, ऋर्यात—
 - (क) यदि विवाद का सम्बन्ध नहर के स्वामित्व या उक्त नहर के जल प्रयोग में स्वामियों के पारस्परिक अधिकार या नहर के निर्माण या संधारण या उक्त रूप से निर्माण या संधारण के व्ययों के किसी भाग की जुकती या नहर के जल-प्रदाय के बटवारे से हो तो कलेक्टर हिमाचल प्रदेश बड़ी जमीन्दारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1953 के उपवन्धों के अधीन माल न्यायालय के रूप में कार्यवाही करंगा और उस अधिनियम के उपबन्ध अपीलों, पुनरावृत्तियों और पुनरीचणों के सम्बन्ध में प्रवर्तनीय होंगे;
 - (ख) यदि विवाद का सम्बन्ध जल मार्ग (water-course) से हो तो कलेक्टर माल अधिकारों के क्य में मुक्रहमें की मुनवाई और निश्चय करेगा और उस पर ऐसा आदेश देगा, जो उसे उचित प्रतीत हो और उक्त आदेश दिए जाने के दिनांक से कोई गई या उगाई हुई किसी फसल के लिए जल-प्रयोग या जल-वितरण के सम्बन्ध में तब तक निर्णायक रहेगा जब तक फाइनैन्शियल कमिश्नर के पास अपील किए जाने पर उसे रह नहीं किया जाता। ऐसे प्रत्येक मुक्रहमें में अपील किए जाने पर फाइनैन्शियल कमिश्नर का आदेश आन्तिम होगा।

- 55. नहरों के लिए भूमि का अर्जन —(1) जिस व्यक्ति ने शासन से नहर बनाने की अनुमित ले ली हो या जो व्यक्ति नहर का स्वामो हो वह उक्त नहर के प्रयोजनार्थ आवश्यक भूमि लेने के लिए कलेक्टर को लिखित प्रार्थना पत्र दे सकेगा।
- (2) यदि कलेक्टर की यह सम्मति हो कि प्रार्थ नापत्र स्वीकार कर लिया जाए तो वह उसे अपनी सिफारिश के साथ शासन के आदेशार्थ भेज देगा।
- (3) यदि शासन की सम्मित में प्रार्थ ना पत्र चाहे पूर्ण रूपेण या अश्रारूपेण स्वीकार कर लिया जाना चाहिए ता वह यह घोपणा कर मकेगा कि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (Land Acquisition Act, 1894) के अर्थान्तर्ग त सार्व जिनक प्रयोजन (public purpose) के लिए भूमि की आवश्यकता है और उसके अर्थान आवश्यक कार्यवाही करने का निदेश देगा।
 - 56. सहमित लेकर या अन्यथा नहर अर्जित करने की शक्ति.—जब किसी नहर की सार्वजिनक हित (public interest) में अर्जित करना शासन को उचित तथा आवश्यक जान पड़े तो राज्यशासन अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि उक्त अधिसूचना में नामांकित दिन के पश्चात, जो अधिसूचना के दिनांक से छ: महीने के पूर्व का नहीं होगा, उक्त नहर अर्जित कर ली जाएगी।
 - 57. प्रतिधन की मांग करने के जिए सूचना.— उक्त ऋधियुचना जारी होने के पश्चात यथासम्भवशीघ, कलेक्टर सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक सूचना दिलवाएगा जिस में यह बतलाया जाएगा कि राज्यशाकन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उक्त नहरें ऋजिंत करना चाहता है ऋगैर उसके ऋजिं के सम्बन्ध में प्रतिधन की मांगें उसके सन्तुख प्रस्तुत की जाएं।
 - 58. मांगों के सम्बन्ध में परिष्टच्छा (inquiry)—(1) कलेक्टर उक्त मांगों के सम्बन्ध में परिष्टच्छा करने और वह प्रतिधन राशि निश्चित करने के लिए, जो मांगकर्ता (claimant) को दी जानी चाहिए, कार्य वाही करेगा। ऐसा प्रतिधन निर्धारित करते समय कलेक्टर धारा 66 में दी गई व्यवस्था के श्रवसार कार्य वाही करेगा, किन्तु इस धारा के प्रयोजनार्य वह नहर के इतिहास, उस पर किए गए व्यय श्रीर स्वामियों के लामों का भी ध्यान रखेगा।
 - (2) मांगों की परिसीमा धारा 57 के ऋधीन सूचना के दिनांक से एक वर्ष समाप्त हो जाने पर प्रतिधन के लिये कोई भी मांग तब तक प्रवर्तनीय नहीं होगी जब तक कलेक्टर का यह समाधान न हो जाए कि उकत ऋवीध के भीतर मांग न करने के लिए मांगकर्ता (claimant) के पास पर्याप्त कारण थे।
 - 59. नहर का शासन में निहित होना.—(1) शासन ऋधिस्चना द्वारा वह दिन घोषित करेगा, जिस दिन से नहर उसके द्वारा ऋर्जित कर ली गई हो।
 - (2) उक्त नहर के स्वामी के पन्न में प्रतिधन के परिनिर्ण्य (award of compensation) के अधीन रहते हुए, जब शासन नहर अर्जित कर लेता है तो—
 - (क) उस में उसके स्वामी के अधिकार, आगम और स्वत्व तुरन्त अन्त तथा समाप्त हो जाएंगे;

- (ख) ऐसे ऋधिकारों के ऋधीन रहते हुए, जिन के ऋन्तर्गत को व्यक्ति नहर से मिंचाई करने के लिए जल ले सकता हो, उक्त नहर शासन में तुरन्त निहित हो जाएगी और उसको निरपेन्त सम्पत्ति (absolute property) होगी।
- 60. नदी, उपनदी, प्राकृतिक कूल या प्राकृतिक जलोत्सार्ण (lines of natural drainage) में जल प्रवाह का ज्यानियमन करने ज्यार उन में बाधा डालने से मना करने या उनकी बाधा हटाने का ज्यादेश देने की शिक्ति.—शासन राजपत्र में प्रवाशित ग्राधिस्त्रना द्वारा किसो नदी, उपनदी, प्राकृतिक कुल या प्राकृतिक जलात्सारण के जल प्रवाह की, कमों का निर्माण करके या उनको हटा कर या अन्यथा आनियमित करने की शक्ति स्थयं धारण कर मकेगा और जब कमी शासन को कलेक्टर द्वारा परिष्टच्छा करने के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि किसी नहर के जल प्रदाय या किसी सूमि की कृषि या सार्वजिनक स्वास्थ्य या लोक सुविधा (public convenience) पर किसी नदी, उपनदी, प्राकृतिक कुल या जलोत्सारण की बाधा से चृतिपूर्ण प्रभाव पड़ने की सम्भावना है तो वह उपरोक्त रूप से प्रकाशित अधिस्चना द्वारा ऐसी अधिस्चना में परिभाषित सीमाओं के भीतर ऐसी बाधा उपस्थित करना प्रतिषद्ध कर सकेगा या यह आदेश दे सकेगा कि उक्त सीमाओं के भीतर ऐसी बाधा इटा दी जाए या उसे रूपान्तिरत कर दिया जाए।
- 61. अधिसूचना के प्रकाशन के परचात् वार्या (obstruction) हटाने की शक्ति और भ्रितिधन की चुकती (!) कलेक्टर उक्त प्रकाशन के परचात् उक्त वाचा (obstruction) डालने वाले या इस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को एक आदेश, उस मैं नियत समय के भीतर, बाधा (obstruction) हटाने या उसमें रूपान्तर करने के लिए दे सकेगा।
 - (2) कलेक्टर बाधा (obstruction) को स्वयं हटा सकेगा या उसको रूपान्तरित कर सकेगा
 - (क) यदि वह व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के ऋषीन ऋषिश दिया गया हो, उक्त रूप से नियत समय के भीतर उस ऋषिश का पालन न करे; ऋषेर
 - (ख) उस दशा में जब कि बाधा (obstruction) किसी व्यक्ति ने उपस्थित न की हो या उस पर किसी का नियन्त्रण न हो।
- (3) कलेक्टर यह निश्चय करेगा कि बाधा (obstruction) हटाने या उसको रूपान्तरित करने का व्यय किस व्यक्ति से वसूल किया जाएगा, और वह प्रतिधन राशि निश्चय करेगा, जो बाधा (obstruction) हटाने या उस में रूपान्तर करने से हातिग्रस्त किसी व्यक्तिको देय हो ग्रौर उस व्यक्ति का निश्चय करेगा जिमके द्वारा उक्त प्रतिधन देय होगा:

परन्तु मनमानी या ऋनुचित (inequitable) कार्यवाही द्वारा प्राप्त किसी लाभ के लिए कोई भी प्रतिधन नहीं दिया जायगा।

62. जल-प्रवाह का आनियमन करने खोर बाधाएं (obstructions) रोकने या हटाने की कलकटर की शक्ति — जब शांसन धारा 60 में दी गई व्यवस्था के अनुसार अधिसूचना द्वारा किसी नदी, उपनदी या प्राकृतिक कूल या प्राकृतिक जलोत्सारण में जलप्रवाह का आनियमन करने की

शक्ति अपने हाथ में ले लेता है तो वह उकत शिक्त विहित नियमों के अनुसार अपनी ओर से पालन करने के लिए कलेक्टर को प्राधिकृत कर सकेगा। उक्त रूप से प्राधिकृत कलेक्टर उक्त नियमों का निष्पादन करने समय थारा 61 द्वारा प्राप्त समस्त शिक्तयों का प्रयोग कर सकेगा और उसके प्राधिकार के अन्तर्गत ऐसी कायवाही करने की शिक्त भी होगी, जिसे करने के लिए शासन कलेक्टर से परिष्टच्छा करवाने के पश्चात् धारा 60 द्वारा अधिकृत हो। उक्त प्राधिकार राजपत्र में फिर से अधिसूचना का प्रकाशन किए बिना प्रत्येक अवसर पर प्रयोग में लाया जा सकेगा।

- 63 अनुमूर्ची 2 के अन्तरात नहरों के सम्बन्ध में कर्मों के निर्माण और संघरण में सम्बद्ध शक्तियां —(1) कलेक्टर किसी भी समय अनुमूर्ची 2 के अन्तर्गत किसी नहर के लाभधारी को
 - (क) नहर से सम्बन्धित किन्हीं तटबन्टों, रज्ञा कमीं, जलाशयों, क्लों, जलमागों, जल द्वारों, मोरियों (embankments, protective works, reservoirs, channels, water-courses, sluices, outlets) श्रौर श्रम्य कमों की उचित रीति से मरम्मत करने श्रौर उनके संधारण का श्रादेश दे सकेगा;
 - (ख) किसी ऐसी सार्वजिनक सड़क या आम रास्ते पर यातायात की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ, जो नहर बनाने ते पहले प्रयोग में लाया जाता था, नहर पर कहीं भी आरपार, बीच में से या ऊपर उपयुक्त पुल, पुलिया, या इसी प्रकार के कर्म का उचित रीति से निर्माख करने, उनकी मरम्मत करने और उनके संधारण का आदेश दे सकेगा;
 - (ग) किसी ऐसी सार्वजनिक सड़क या त्राम रास्ते या किसी नहर, जलोत्सारण या जलमार्ग, जो नहर बनाने से पहले प्रयोग में लाए जाते थे, के ब्रारपार, नीचे या ऊपर, नहर के जल-निर्मामन के लिए उचित रीति से उपयुक्त कमीं का निर्माण करने, उनकी मरम्मत करने ब्रीर उनके संधारण का ब्राटेश दे सकेगा;
 - (घ) नहर के उद्गम स्थान (head of the canal) या उसके समीप उपयुक्त र गुलेटर उचित रीति से निर्माण करने, उसकी मरम्मन करने और उसके संधारण का आदेश दे सकेगा, जहां ऐसे र गुलेटर की अनुपस्थित में नहर में अधिक जल आ जाने या इसे या आसपड़ोस में फसलों, भूमियों, सड़क या सम्पत्ति को हानि पहुंचने की आशंका हो।
- (2) कलेक्टर, किसी भी समय, इस अधिनियम की धारा 37 में विशिष्ट प्रयोजनों में से एक अथवा अधिक प्रयोजन के लिए श्रकुशल अम (unskilled labour) मुफ्त में प्रदान करने के लिए लाभधारी (beneficiary) को आदेश दे सकेगा ।
- (3) उपधारा (1) और (2) के अन्तर्गत प्रत्येक आदेश लिखित रूप में दिया जाएगा और उस में वह समुचित समय निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसके भीतर उस में वर्णित कर्म या मरम्मतें पूर्ण रूपेश निष्पादित की जाए गी।
- (4) यदि इस धारा के अधीन दिए गए किसी आदेश का उस में विशिष्ट समस्र के भीतर कलेक्टर के समाधानानुसार पालन नहीं किया जाता तो कलेक्टर आदेश में विशिष्ट समस्त कमीं या मरम्मतों को

स्वयं निष्पादित करेगा या उनका निष्पादन पूरा करेगा या उक्त रूप से निष्पादित करवाएगा या पूरा करवाएगा।

- 64. अनुसूची 1 में समाविष्ट नहरों के सम्बन्ध में कर्मों के निर्माण श्रीर उनके संधारण से सम्बद्ध शक्तियां.—अनुसूची 1 में समाविष्ट नहरों की दशा में कलेक्टर—
 - (क) लाभधारी से यह मांग कर सकेगा कि वे धारा 63 की उपधारा (1) में विशिष्ट ऐसे किसी टायित्व का सम्पादन करें, जा शासन उक्त नहर या नहर समूह के लाभधारी के प्रति घोषित करें; या
 - (न्व) उक्त कार्यों के सम्पादन का स्वयं प्रबन्ध कर सकेगा ख्रौर वारा 68 में दी गई व्यवस्था के ख्रनुसार व्यय वसूल कर सकेगा।
- 65 त्राकरिमक परिश्वित की दशा में कर्म निर्माण करने त्रीर कर्मों पर कब्ज़ा करने की शक्ति.—(1) यदि किसी ऐसे नए कर्म को तुरन्त रोकने की त्रावश्यकता हो, जो किसी नहर की उपयोगिता के लिए घोर हानिकर हो, तो कलेक्टर लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (Land Acquisition Act, 1894) में किसी बात के होते हुए भी ऐसी किसी भी भूमि पर तुरन्त कब्ज़ा कर लेगा, जिसकी कर्म-निर्माण के लिए त्रावश्यकता हो।
- (2) जब कलेक्टर ने उपधारा (1) के ऋधीन किसी भूमि पर कब्जा कर लिया हो तो वह इस कम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर धारा 66 के ऋधीन प्रतिधन का निर्धारण करेगा तथा प्रतिधन देगा !
- (3) नहर या उसके बिल्कुल आसपड़ोस में स्थित रूम्पित या उस से की जाने वाली सिंचाई या सार्वजनिक यातायात को आकरिमक और घोर हानि पहुंचने या शीघ खतरा होने की दशा में कलेक्टर पूर्व मूचना देने के पश्चात्, उक्त हानि का उपाय करने या खतरा रोकने के लिए उक्त कर्मी को, जैसा वह आवश्यक समभ्मे, उसके अनुसार पूरा कर सकेगा या पूरा करना सकेगा और किसी भी सेचक से यह अपेना कर सकेगा कि वह इतना श्रम प्रदान करे, जितना उक्त कलेक्टर को कर्म शीघ पूरा करने के लिए समुचित और आवश्यक प्रतीत हो।
 - (4) इस धारा के श्रश्रीन दिए गए अम के लिए स्थानीय बाजार की दर पर मजदूरी दी जाएगी ।
 - (5) उपधारा (3) ऋौर (4) के ऋषीन दिया गया ऋादेश ऋन्तिम होगा ।
- 66 प्रनिधन निर्धारण.—इस ऋधिनियम की धारात्रों 23, 25, 32, 50 और 61 को छोड़ कर अपन किसी भी धारा के अधीन दी जाने वाली प्रतिधन-राशि निर्धारित करते समय कलेक्टर लैंड एक-विजीशन एक्ट, 1894 (Land Acquisition Act, 1894) के उपवन्धार्धन कार्यवाही करेगा और उस अधिनियम के समस्त उपवन्ध इस धारा के अधीन समस्त कार्यवाहियों में, जहां तक हो सके, कलेक्टर द्वारा परिष्टिश्वा करने तथा परिनिश्चय देने, दीवानी न्यायालयों को निर्देशन करने और तदुपरान्त प्रक्रिया, प्रतिधन विभाजन, जुकती और अपीलों के सम्बन्ध में प्रवर्तनीय होंगे।
- 67. प्रयोग-कर्ना के अधिकार के लिये जलप्रदान के रूप में प्रतिधन. चन कलेक्टर देय प्रतिधन राशि का निर्धारण कर रहा हो तो वह पन्तों की सहमित से किसी शूमि का श्रर्जन करने

की दशा में यह निदेश दे सकेगा कि जब तक नहर या जल मार्ग के प्रयोजनार्थ भूमि की आवश्यकता है तब तक उक्त भूमि का स्वामित्य (property in such land) प्रयोग कर्ता के आधिकार के प्रतिबन्धावीन स्वामी के पाम रहेगा, और प्रतिधन केवल प्रयोग-कर्ता के अधिकार के लिए दिया जाएगा, या किसी नहर के अर्ज न या किसी नहर के प्रयोजनार्थ भूमि के अर्ज न की दशा में प्रतिधन पृर्णातया या अंशतया उस नहर से, जो अर्जित की गई हो या जिसके प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित की गई हो, प्रदत्त जल का प्रयोग करने के अधिकार के रूप में दिया जाएगा।

- 68. ऋजित भूमि के न्यय या निष्पादित कर्मों के न्यय का निर्श्चय और वामुली.—(1) जब धारा 55 के उपबन्धांचीन कोई भूमि ऋजित कर ली जाती है या जब धारा 61, धारा 63, धारा 64 या धारा 65 के उपबन्धों के अन्तर्गत कलेक्टर के आदेशाधीन या आदेश द्वारा कोई कर्म निष्पादित किया जाता है तो, यथास्थित, उक्त भूमि के अर्जन का या उक्त कर्म के निष्पादन का व्यय: -
 - (क) यदि नहर ऋनुमूची 2 में समाविष्ट हो तो उसके स्वामी से वम्ल किया जा सकेगा, या
 - (ल) यदि नहर त्रानुष् ची 1 में समाविष्ट हो तो सेचकों से या उन में मे ऐसे व्यक्तियों से, जिन्हें कलेक्टर की राय में त्रार्ज न द्वारा लाभ पहुँ चा हो या लाभ पहुँ चने की सम्भावना हो या जो न्यायोचित रूप से कर्म निष्पादन के समस्त व्यय या उसके किसी द्रांश के लिए उत्तरदायी हों या धारा 41 के अधीन आरोपित किसी जलकर की आय में से वस्त किया जा सकेगा, और
 - (ग) यदि उक्त विनियोग ऋधिनियम की धारा 40 में विशिष्ट ऋधिकार ऋभिलेख के उपबन्धों के विपरीत न हो तो इस ऋधिनियम की धारा 39 में निर्दिष्ट निधि में से वमूल किया का सकेगा।
- (2) जब उपधारा (1) के उपबन्धाधीन किसी भूमि के ऋर्जन या कर्म के निष्पादन का व्यय किमी नहर के स्वामियों या उस के सेनकों या उनमें से किसी से भी प्राप्य हो तो कलेक्टर के लिए, जैसा वह न्यायोचित समक्त उसके ऋनुसार उक्त व्यय ऐसे समस्त व्यक्तियों में या उन में से किन्हीं व्यक्तियों में, जो उक्त समस्त व्यय या उसके किसी भाग के लिए उत्तरदायी हों, ऋभिभाजित करना विधिवत् होगा और उक्त ऋभिभाजन ऋन्तिम होगा ।
- (3) जब उक्त भूमि के ऋर्जन का व्यय चुका दिया गया हो तो उक्त भूमि, यदि पूर्ण स्वामित्व के ऋधिकारों सहित ऋर्जित की गई हो, नहर के स्वामी की सम्पत्ति बन जाएगी।
- 69. चिक्कियों का त्रानियमन करने की शिक्त शासन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, नहरों पर नई चिक्कियों का निर्माण रोक सकेगा या उनका आनियमन कर सकेगा और नहरों पर विद्यमान चिक्कियों के प्रयोग का आनियमन कर सकेगा और चातू चिक्कियों के लिए नहर के जल प्रयोग का आनियमन वर सकेगा।
- 70. 1953 ई॰ के भूराजस्व अधिनियम की धारा 14 से ले कर धारा 17 तक की धाराओं की प्रयुक्ति.—सिवाए इसके जब कि प्रतिकृत अभिप्राय अभिन्यक्त हो, हिमाचल प्रदेश भूराजस्व अधिनियम

1953 की धारा 14 से लेकर धारा 17 तक की धाराएं (दोनों समाविष्ट) इस ऋधिनियम के ऋधीन समस्त कार्यवाहियों में प्रयुक्त होंगी।

- 71. लैंड एक्बी गीरान ऐक्ट के अंतर्गत दशा को छोड़ कर दीवानी न्यायालय के अधिकार त्रेत्र का अपवर्जन. धारा 66 में टी गई व्यवस्था को छोड़ कर विसी भी टीवानी न्यायालय को किसी ऐसे विषय पर अधिकारक्षेत्र प्राप्त नहीं होगा, जिसका निर्णय करने के लिए कोई माल अधिकारी या माल न्यायालय इस अधिनियम द्वारा अधिकृत हो या वह किसी ऐसे विषय का संज्ञान नहीं करेगा, जिमके सम्बन्ध में शासन या कोई माल अधिकारी या माल न्यायालय इस अधिनियम के अधीन या द्वारा स्वनिहित शक्तियों का प्रयोग करता हो।
- 72. इस अधिनियम के अधीन कार्य सम्पादन करने के लिए पदाधिकारी नियुक्त करने की शिक्ति—(1) शासन किसी व्यक्ति को या पदाधिकारियों की किसी श्रेणी को, ऐसे कार्य सम्पादन करने या ऐसी शिक्तियां प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकेगा, जो क्लेक्टर या किश्चिर, यदि कोई हो, फाइनैंशियल किम्श्नर या उक्त शासन में इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निहित हों या उन्हें प्रदान को गई हों।
- (2) उक्त नियुक्ति किसी नहर या किसी विशिष्ट स्थानीय च्रेत्र के भीतर स्थित समस्त नहरों या उनमें से किसी नहर के सम्बन्ध मैं की जा सकेगी।
- (3) इस ऋधिनियम से सम्बन्धित समस्त विश्वयों में शासन फाइनेन्शियल कामश्नर, कामिश्नर, यदि कोई हो, ऋौर कनेक्टर पर ऋौर फाइनेशियल कामिश्नर, कामिश्नर, यदि कोई हो ऋौर कलेक्टर पर ऋौर कामिश्नर, यदि कोई हो, कलेक्टर पर वही प्राधिकार प्रयोग करंगा ऋौर उन पर वही नियंत्रण करेगा, जो प्राधिकार ऋौर नियंत्रण सामान्य ऋौर माल प्रशासन (general and revenue administration) में क्रमशः वह या वे उन पर प्रयोग कर सकता या कर सकते हों।
- 73. ऋधिनियम के ऋधीन कुछ कार्यवाहियों में कलेक्टर की शिक्तयां इस ऋधिनियम के ऋधीन की गई प्रत्येक परिषृच्छा (enquiry) और कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ कलेक्टर की, या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी ऋन्य माल ऋधिकारों को, या शासन द्वारा प्राधिकृत किसी ऋन्य पराधिकारी को पन्नों और गवाहों को समन देने और उनकी उपस्थित बाध्य करने, उनकी जांच करने और प्रलेखों की प्रस्तुति बाध्य करने की शिक्त होगी और इन समस्त प्रयोजनों या इन में से किसी एक के लिए वह कोड आफ सिविल प्रौसीजर 1908 (Code of Civil Procedure 1908) द्वारा टीवानी न्यायालय को प्रदत्त समस्त शिक्तयों या किसी का भी प्रयोग कर सकेगा और उक्त प्रत्येक परिष्टच्छा (enquiry) इन्डियन पीनल कोड (Indian Penal Code) के प्रमोजनार्थ न्यायिक कार्यवाही (judicial proceedings) समस्ती जाएगी।
- 74. म्बामियों श्रीर किसी नहर में स्वत्व रखने वाले पत्तों को कुछ विषयों में श्रापित करने की श्रनुमित --- इस श्रिविनयम की धाराश्रों 6, 22, 32, 34, 36, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 58, 60, 61, 63, 64 श्रीर 63 के श्रिवीन समस्त विषयों में, स्वामियों श्रीर नहर में स्वत्व रखने वाले प्रन्य पत्नों को कनेक्टर के सन्मुख उपस्थित होने श्रीर प्रतिकृल कारण

वतलाने के लिए अवसर दिया जाएगा।

- 75. उद्घापणा करने श्रीर नेटिस की तामील करने की रीति. इस श्रिधनियम के श्रधीन जारी किए गये प्रत्येक समन, नोटिस उद्घाषणा श्रीर श्रन्य प्रसर की तामील, जहां तक हो सके, ऐसी रीति से की जाएगी, जैसी हिमाचल प्रदेश भूराजस्य श्रीधिनयम, 1953 की धारा 21,22 श्रीर 23 में इस हेतु उपविश्वत है।
- 76. प्रतिधन पर रुकावट, जब उसकी स्पष्ट रूप से अनुमित न दी गई हो.—उस दशा का छोड़ कर जब इस अधिनियम में स्वष्ट रूप से व्यवस्था की गई हो, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा पदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते समय, किसी भी ममय की गई या सद्भावनापूर्वक की जाने वाली किसी भी कार्यवाही के लिए प्रतिधन वसूल करने का कोई भी व्यक्ति अधिकारी नहीं होगा।
- 77. ऋधिनियम के ऋधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों का बचाव इस ऋधिनयम या इसके श्रंतर्गत बनाए गए नियमों के ऋधीन की गई या सदमावना पूर्वक की जाने वाली किसी बात के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, ऋभियोग या श्रन्य वैधानिक कार्य-वाई। नहीं चलाई जाएगी।
- 78. बुछ मुकद्दमों ऋोर कार्यवाहियों में राज्य शासन पत्त के रूप में होगा.—
 (1) ऐसे किसी भी बाद या कार्यवाही में, जिस में धारा 40 या धारा 46 के अन्तर्गत तयार किए गए किसी भी अभिलेख में की गई किसी प्रविध्य पर प्रत्यत्त या अप्रत्यत्त रूप से आपित की जाती हो, न्यायालय बाद-विषय का अन्तिम रूप से निपटारा करने से पहले बाद या कार्यवाहों की सूचना कलेक्टर को देगा और यदि कलेक्टर ऐसा करना चाहे तो शासन को उस के सम्बन्ध में पत्त बना लेगा।
- (2) शासन के विरुद्ध अन्य वादों की रुकावट.—उपधारा (1) में दी गई व्यवस्था को छोड़ कर इस अधिनियम द्वारा उक्त कलेक्टर या शासन को प्रदत्त किसी शिक्त का प्रयोग करते समय कलेक्टर या राज्यशासन के आदेशाधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के किसी भी कार्य के सम्बन्ध में शासन के विरुद्ध कोई भी वाद नहीं चलाया जाएगा।
- 79. माल-प्रसर (Revenue process) द्वारा जल के लिए देय राशियां (waterdues) ग्रौर ग्रन्थ राशियां वसूल करने की शक्ति.— इस ग्रधिनियम के उपबन्धाधोन या नहर के स्वामियों या नहर के सेचकों के बीच किए गए किसी निर्वन्थ के ग्रधीन किसी भी व्यक्ति से किसी भी समय प्राप्य या किसी भी व्यक्ति से एकत्रित की जाने वाली जल के लिए देय समस्त राशियां, जलकर ग्रौर ग्रन्थ चुकतियां ग्रौर उनके समस्त बकाया भ्राजस्व के बकाया की भान्ति वस्ल किए जा सकेंगे।
- 80. हिमाचल प्रदेश की सीमाओं के अंशतः बाहिर स्थित नहरों, खोर उपनिदयों के सम्बन्ध में शिक्तयां किसी नहर, नदी या उपनदी के सम्बन्ध में शासन द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रयोग में लाई जा सकने वाली समस्त या कोई सी शिक्तयां, ऐसी नहर, नदी या उपनदी, जो किसी भी समय अंशत: हिमाचल प्रदेश की सीमाओं के भीतर और अंशतः बाहिर स्थित हां या अंशतः

. t*

मीतर त्रीर त्र शातः बाहिर स्थित हो जाएं, की दशा में, त्रीर उक्त नहर, नदी या उपनदी के उतने भाग के सम्बन्ध में, जितना उन सीमात्रों के भीतर स्थित हो, उक्त शासन द्वारा प्रयोग में लाई जाएंगी, त्रीर उक्त किसी नहर नदी या उपनदी के सम्बन्ध में राज्यशासन धारा 2 के उपबन्धों में किसी बात के होने हुए भो, त्राधिस्चना द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि इस त्राधिनियम के कीन कीन से उपबन्ध उन के सम्बन्ध में प्रवर्तनीय होंगे।

- 81. हिमाचल प्रदेश स्व बाहिर स्थित नहरों के सम्बन्ध में ऋत्यावश्यकता होने की दशा में प्रयोग में लाई जा सकने वाली शिक्तयां,—हिमाचल प्रदेश की सीमाश्रों से बाहिर स्थित किसी भी नहर के सम्बन्ध में शासन राजपत्र में ऋषिम्चना प्रकाशित वरके यह घोषणा कर सिकेगा कि धारा 65 के अधीन कलेक्टर द्वारा प्रयोज्य शक्तियां, उस में विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन कलेक्टर या अन्य प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा उक्त नहर के समस्त या किमी भी प्रयोजनार्थ हिमाचल प्रदेश की सीमाश्रों के भीतर प्रयोग में लाई जाएंगी।
- 82. श्रिधिनियम के अन्तर्गत अपराध जो कोई भी उचित प्राधिकार के बिना श्रीर स्वेच्छा पृत्रिक निम्नलिखित कोई सा कार्य करता है, श्रिथीत्
 - (1) किसी नहर को हानि पहुँचाता है, उस में आपरिवर्तन करता है उसे बढ़ाता है, या उस में बाधा डालता है;
 - (2) किसी नहर के जल-प्रदाय या किसी नहर से, नहर में, नहर पर या नहर के नीचे, जल √ प्रवाह में इस्तक्तेप करता है, उसे बढ़ाता है या कम करता है;
 - (3) किसी नदी, उपनदी या जलधारा के जल प्रवाह में इस प्रकार हस्तच्चेप करता है या उस में इस प्रकार आपरिवर्तन करता है, जिस से किसी नहर को हानि पहुंचने का डर हो या उस की उपयोगिता कम हो जाए;
 - (4) किसी जल मार्ग के संधारण या जल मार्ग के प्रयोग के लिए उत्तरदायी होते हुए उस से जल नष्ट होने की रोक थाम के लिए उपयुक्त पूर्वापाय करने में प्रमाद करता है या उस से जल के प्राधिकृत वितरण में हस्तचेप करता है या अप्राधिकृत रीति से उक्त जल का प्रयोग करता है;
 - (5) किसी नहर के जल को इस प्रकार दूषित करता है या इस में इस प्रकार कपट करता . है, जिस से उन प्रयोजनों की उपयोगिता कम हो जाए, जिस के लिए साधारणतया वह उपयोग में लाया जाता है;
 - (6) इसे अधिनियम के अधीन अम प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होते हुए, उचित कारमें के बिना ऐसा अम प्रदान नहीं करता, जो उस से अपेद्धित हो या अम प्रदान करने में सहायता नहीं करता;
 - (7) इस अधिनियम के अधीन अम प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होते हुए, उजित कारण के किना, उक्त रूप से अम प्रदान करने में और अम प्रदान करते रहने में प्रमाद करता है;

- (8) विसी लोक सेवक के प्राधिकार से नियत जलमापन यंत्र के तल चिन्ह को नष्ट करता है या हटाता है;
- (9) इस ऋधिनियम के ऋधीन बनाए गए नियमों के प्रतिकृत किसी भी नहर के कमों (works) से या नहर के किनारों से या नहर की कृतों से पशुऋों या गड़ियों को ले जाता है या स्वयं जाता है, जब कि वहां पर उसको ऐसा करने की मनाही की गई हो:
- (10) इस ऋधिनियम के ऋधीन जारी किए गए ऋदिश या उद्घीपणा की अवज्ञा करता हैं या उसके ऋधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है;

ऐसी श्रेणी के मैजिस्ट्रेट द्वारा दोपी टहराए जाने पर, जो राज्य शासन द्वारा इस सम्बन्ध में निदेशित किया जाए, पचास रुपए तक के अर्थदन्ड या एक महीने तक के कारावास या दोनों का भागी होगा

- 83. बिना वारन्ट के गिरफ्तार करने की शक्ति.—लोक-सेवकों या पंचायत सहित किसी स्थानीय संस्था द्वारा प्रबन्धित नहर की देख रेख करने वाला व्यक्ति या उस पर दृत्ति युक्त व्यक्ति नहर की भूमियों या भवन से ऐसे व्यक्ति को हटा सकेगा या वारन्ट के विना हिरास्त में ले सकेगा और तुरन्त किसी मैजिस्ट्रेट या सब से समीप की पुलिम चौकी में उस व्यक्ति के सम्बन्ध में विधि अनुसार संव्यवहार करने के लिए ले जाएगा, जिस ने उस के विचार में निम्न लिखित अपराधों में से कोई अपराध किया हो:—
 - (1) किसी नहर को जान बूभ्र कर हानि पहुंचाई हो या उस में बाधा डाली हो;
 - (2) उपयुक्त प्राधिकार के बिना किसी नहर, नदी या जलधारा, के. जल प्रदायया जल प्रवाह में इस प्रकार इस्त लेप किया हो, जिस से किसी नहर की खतरा या हानि पहुंचने का भय हो या उसकी उपयोगिता कम हो गई हो।
- 84. धारा 82 और 83 के प्रयोजनार्थ नहरों की परिभागा.—धारा 82 ब्रौर 83 में शब्द "नहर" (जब कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकृल नहों) के ब्रन्तग त समका जाएगा—नहरों के प्रयोजनार्थ कब्जे में ली गई समस्त भूमि ब्रौर उक्त भूमियों पर स्थित समस्त भवन, भशीनें, जंगले, दरवाजे ब्रौर ब्रन्य रचनाएं (erections), बृच्च, फसलें, पौदे या ब्रन्य उपज।
- 85. नियम बन ने की शिक्ति.—(1) इस अधिनियम द्वारा शासन या शासन के िकसी पदाधिकारी को प्रदत्त किसी शिक्त से सम्बद्ध किसी विषय का आनियमन करने के लिए और सामान्यत: इस अधिनियम के प्रयोजन पूरे करने के लिए, शासन इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगा।
- (2) उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्ति की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में, रेत या बाह से भूमि का बचाव करने के विचार के प्रतिफल रूप उक्त भूमि पर एक कर लगाने की ब्यवस्था की जा सकेगी।

- (3) उपधारा (1) के ऋधीन बनाए गए समस्त नियम उक्त रूप से तब ही बनाए जाएंगे जब उनका राजपत्र में पूर्व प्रकाशन हो चुका हो।
- (4) इस त्र्राधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए समस्त नियम बनाए जाने के पश्चात् यथासंभव शीव्र विधान सभा के सन्मुख रखे जाएंगे।

अनुसूची 1

अनुसूची 2

B. D. SHARMA,
Assistant Secretary (Judicial).

शिमला-4, दिनांक 2 दिसम्बर, 1955

सं० बी० ऐस-210/55.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 102 के श्रधीन निम्निलिखित विधेयक जैसा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में 30 नवम्बर, 1955 को पुर: स्थापित हुआ एतद्दारा सर्व सामान्य की स्चनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक सं 29, 1955

दी वैक्सीनेशन (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1955

(जैसा कि विश्वान सभा द्वारा पुरः स्थापित किया गया)

वैक्सीनेशन ऐक्ट, 1880 की हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रयुक्ति के लिये उसमें संशोधन करने का

विधेयक

यह भारतीय गरातन्त्र के छठे वर्ष में हिमाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में श्रिधिनियमित किया जाए:—

1. सं चिप्त नाम तथा प्रसार, (1) इस अधिनियम का नाम व क्सीने रान (हिमानल प्रदेश

- मंशोधन) अधिनियम, 1955 होगा।
 - (2) इसका प्रसार हिमान्तल प्रदेश के समस्त राज्य में होगा।
- 2. 1880 की ऋधिनियम सं ॰ 13 में सम्पूर्ण नाम और प्रस्तावना का संशोधन.— वैक्शीनेशन ऐस्ट 1880 (जिसे यहां से आगे मूल ऋधिनियम बहा गया है) के सम्पूर्ण नाम ग्रोर उसकी प्रस्तावना में शब्दों "and cantonments" के स्थान पर शब्द "cantonments and notified areas" रख दिए जाएं।
- 3. 1880 की ऋधिनियम सं० 13 में धारा । का संशोधन मूल ऋधिनियम की धारा । में शब्दों "such municipalities" से आरम्भ होने वाले और शब्दों "hereinafter provided" पर समाप्त होने वाले बाक्यांश के स्थान पर निम्निलिखित रखा जाए, अर्थात.—
 - "such municipalities, cantonments and notified areas in the State of Himachal Pradesh, as it may be extended in manner hereinafter provided."
- 4. 1880 की अधिनियम संख्या 13 में धारा 2 का संशोधन .— मृल अधिनियम की धारा 2 में—
 - (क) खंड (6) में शब्द ''cantonment'' के पश्चात् शब्द ''or notified area'' जोड़े जाएं।
 - (ख) खन्ड (8) के पश्चान् निम्नलिखित खन्ड जोड़े जाएं, अर्थोत्—
 - "(9) 'notified area' means any area notified under subsection (2) of section 4-A;
 - (10) 'State Government' means the Lieutenant Governor of the State of Himachal Pradesh;"
- 5. 1880 की स्प्रधिनियम संख्या 13 में एक नई धारा 4-A बढ़ाया जाना.—मूल स्प्रधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित् धारा बढ़ा दी जाए, स्रर्थात,—
 - "4-A. Extension of Act to notified areas.—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to extend the provisions of this Act to any area not falling within a municipality or cantonment.
 - (2) Any inhabitant of such area who desires to object to such extension may, within sixty days from the date of such notification, send his objection in writing to the State Government; and the State Government shall take such objection into consideration. When sixty days from the said date have expired, the State Government, if no such objections have been sent as aforesaid, or when such objections have been so sent, if in its

opinion they are insufficient, may by like notification effect the proposed extension."

- 6. 1880 की अधिनियम संख्या 13 में धारा 5 का संशोधन.— मूल अधिनियम की धारा 5 में शब्दों "or any local area in a cantonment" के स्थान पर शब्द "cantonment or notified area" रख दिए जाएं।
- 7. 1880 की ऋधिनियम नं 0 13 की धारा 8 का संशोधन.—मूल ऋधिनियम की धारा 8 में शब्द "Commissionar" के स्थान पर शब्द "State Government" रखे जाएं।
- 8. 1880 को ऋधिनियम सं० 13 में धारा 18 का संशोधन मूल ऋधिनियम की धारा 18 में से द्यांतिम वाक्य हटा दिया जाए।
- 9. 1880 की ऋधिनियम सं॰ 13 में धारा 19 का संशोधन.—मूल ऋधिनियम की धारा 19 में जिन दोनों स्थानों में शब्द "the Commissioner" ऋाते हैं वहां उन के स्थान पर शब्द "the State Government" रखे जाएं।
- 10. 1880 की ऋधिनियम सं 0 13 में धारा 20 का संशोधन. मूल ऋधिनियम की धारा 20 को उसी धारा की उपधारा (1) के रूप में इनः संख्यांकित किया जाए ऋरे इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा बढ़ाई जाए, ऋर्थात्
 - "(2) When this Act has been extended to any notified area, the State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules consistent with this Act for its proper enforcement within the said area."

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

वैक्सीनेशन ऐक्ट, 1880, ऐप्लीकेशन ग्राफ लाज ग्रार्डर के ग्राधीन 25 दिसम्बर सन् 1948 को कुछ संपरिवर्तनों के साथ हिमाचल प्रदेश में प्रयुक्त किया गया था, जिनका मरज् इस्टेटस (लाज) एक्ट, 1949 में कहीं भी वर्णन नहीं हुआ है । केवन वैक्सीनेशन ऐक्ट 1880 ही प्रयुक्त किया गया था। कोर्ट फीज ऐक्ट के सम्बन्ध में जुिहिशियल कमिश्नर के न्यायालय के निर्णयानुसार पंजाब द्वारा या ऐप्लीकेशन ग्राफ लाज ग्रार्डर द्वारा वैक्सीनेशन ऐक्ट, 1880 में, जैसा कि वह मरजड स्टेटस लाज ऐक्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश में प्रयुक्त हुआ है, कोई भी संशोधन किए गए हुए नहीं ममफे जाएंगे। परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश में प्रयुक्त वैक्सीनेशन ऐक्ट ग्राफ 1880 में कुछ संशोधन करना ग्रावश्यक हो गया है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कोई भी श्रवैतिक मैजिस्ट्रेट नहीं है इसलिए घारा 18 की ग्रान्तिम कंडिका (paragraph) हटाई जा रही है।

शिमला-4, दिनांक 2 दिसम्बर, 1955

सं वी० एस-208/55.—िहमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 102 के ऋबीन निम्निलिखित विधेयक जैसा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में 30 नवम्बर, 1955 की पुर: स्थापित हुआ एतद्द्वारा सर्व सामान्य की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक सं॰ 30, 1955

हिमाचल प्रदेश संविलीन राज्य (विधियों की प्रयुक्ति) (संशोधन) विधेयक, 1955

(जैसा कि विधान सभा में परः स्थापित हुन्ना)

हिमाचल प्रदेश संविलीन राज्य (विधियों की प्रयुक्ति) ऋधिनियम, 1954 में संशोधन करने का

विधेयक

यह भारतीय गण्यतन्त्र के छुटे वर्ष में हिमाचल प्रदेश की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में श्रिधिनियमित किया जाए:—

- ।. संचित्त नाम.—(1) इस श्रधिनियम का नाम हिमाचल प्रदेश संविलीन राष्य (विधियों की प्रयुक्ति) (संशोधन) श्रधिनियम, 1955 होगा।
- 2. हिमाचल प्रदेश संविलीन राज्य (विधियों की प्रयुक्ति) अधिनियम, 1954 की धारा 3 में संशोधन —हिमाचल प्रदेश संविलीन राज्य (विधियों की प्रयुक्ति) अधिनियम, 1954 की धारा 3 की उपधारा (1) में उपखंड (अ) के पश्चात निम्नलिखित व्याख्या बढ़ा दी जाए:—

"न्याख्या—इस श्रिधिनियम के प्रयोजनार्थ 30 जून, 1954 को या इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश की विधान सभा द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कोई विधेयक यद्यपि उम दिनांक तक प्रचित्त न किया गया हो तदिप वह 30 जून, 1954 को हिमाचल प्रदेश में प्रवर्तनीय विधान हो जायेगा और सर्वदा उस के सम्बन्ध में यह माना जाएगा कि वह हिमाचल प्रदेश में प्रवर्तनीय विधान रहा है।"

उइ श्यों ऋौर कारणों का विवरण

इस विधेयक द्वारा धारा 3 में शब्द "प्रवर्तनीय" के निर्वचन (interpretation) के सम्बन्ध में सम्भावित संदेह का निवारण करना वांछित है और इसमें यह व्यवस्था की गई है कि 30 जून, 1954 को या इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश की विधान सभा द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत समस्त विधेयक यद्यपि उस दिनांक तक प्रचलित न किए गए हों तदिष वे 30 जून, 1955 को हिमाचल प्रदेश में प्रवर्तनीय विधान हो जाएं गे और सर्वदा उनके सम्बन्ध में यह माना जाएगा कि वे हिमाचल प्रदेश में प्रवर्तनीय विधान रहे हैं।

यशवन्त सिंह परमार ।

शिमला-4, दिनांक 26 नवम्बर, 1955

सं वी ऐसा -209/55. हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रिक्तिया नियमों के नियम 102 के अधीन निम्नलिखित विधेयक जैंसा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में 30 नवम्बर, 1955 को पुर: स्थापित हुआ एतद्द्वारा सर्वसामान्य को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक सं० 31, 1955

हिमाचल प्रदेश सहकारी-सभा विधेयक, 1955

(जैसा कि विधान सभा में पुर: स्थापित हुन्त्रा)

हिमाचल प्रदेश में सहकारी-सभात्रों से सम्बन्धित विधि का संकलन तथा संशोधन करने का विधेयक

यह भारतीय गण्तन्त्र के छठे वर्ष में हिमाचल प्रदेश की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जावे:—

ऋध्याय ।

प्रारम्भिक *

- 1. संचित्त नाम, प्रसार ऋौर प्रारम्भ.—(1) इस ऋधिनियम का नाम हिमाचल प्रदेश सहकारी-सभा विधेयक, 1955 होगा।
 - (2) इसका प्रसार समस्त हिमान्नल प्रदेश में होगा।
- (3) यह उस दिनांक से प्रचिलत होगा, जिसे राज्यशासन इस हेतु राजपत्र में ऋधिसूचना द्वारा नियत करे।
- 2. परिभाषाएं .— जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकृत न हो, इस अधिनियम में—
 - (1) 'विवाचक (arbitrator)' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो धारा 88 की उपधारा (1) के खराड (ख) के ऋधीन ऐसे विवाद (dispute) का निश्चय करने के लिए नियुक्त हो, जो उसे निर्दिध्ट किया गया हो;
 - (2) 'लेखा-परीच्चक (auditor)' का तात्पर्य धारा 71 के अधीन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सहकारी-सभा का लेखा-परीच्चण (audit) करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति से हैं;
 - (3) 'पर्ष द् (बोर्ड)' का तात्पर्य धारा 82 की उपधारा (3) के अप्रधीन निर्मित पर्ष द् (बोर्ड) से है;
 - (4) 'उपविधि (by-law)' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत (रिजस्टर्ड) उपिविधि या ऐसी उपविधि से हैं, जो इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत (रिजस्टर्ड) समर्का गई हो और उपविधि का पंजीकृत (रिजस्टर्ड) संशोधन इसके अन्तर्गत हैं;

- (5) 'केन्द्रीय सभा (central society)' का तात्पर्य ऐसी सभा है से हैं, जिसकी सदस्यता में कम से कम एक सदस्य कोई सहकारी-सभा हो ; ा
- (6) 'समिति (committee)' का तात्पर्य प्रवन्धक-समिति (committee of management) से या ऐसी अन्य निर्देशन-समिति (directing body) से हैं, जिसे सभा के कार्यों का प्रवन्ध सौंपा जाए, और ऐसी समिति इसमें सम्मिलित है, जिसका निर्वाचन पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) से पूर्व सभा बनाते समय हुआ हो;
- (7) 'उपमोक्ता-सभा (consumers' society)' का तात्पर्य उस सभा से है, जो अपने सदस्यों तथा साथ ही साथ अन्य उपभोक्ताओं के लिए वस्तुए, उपलब्ध तथा वितरित करने या उनके लिए सेवा प्रदान करने और वस्तुओं के प्रदाय तथा वितरित (supply and distribution) मे प्राप्त लाभ को उक्त सभा के नियमों या उपविधियों द्वारा विहित अनुपात से अपने सदस्यों तथा उपभोक्ताओं में बांटने के उद्देश्य से बनाई गई हो;
- (8) 'सहकारी सभा (co-operative society)' का तात्पर्य ऐसी सभा से है, जो इम अधिनियम के अधीन पंजीकृत (रिजस्टर्ड) हो या पंजीकृत (रिजस्टड) समर्भी गई हो;
- (9) 'सीमित दायित्व वाली सहकारी-सभा (co-operative society with limited liability)' का तात्पर्य उस सहकारी-सभा से हैं, जिसके सदस्यों का दायित्व उसकी उपविधियों द्वारा उस राशि तक सीमित हो, जो उनके द्वारा कमशः अपने हिस्सों (शेयरों) पर जुकानी शेष रही हो अथवा ऐसी राशि तक सीमित हो, जो व उसकी उपविधियों द्वारा सभा का समापन होने की दशा में (in the event of its being wound up) उसकी सकलसम्पत्ति (assets) में देना स्वीकार करें (undertake to contribute);
- (10) 'त्रासीमित दायित्व वाली सहकारी-सभा (co-operative society with unlimited liability)' का तात्पर्य उस सहकारी-सभा से है, जिसका विगणन (liquidation) होने पर उसकी सकलसम्पत्ति में हुई किसी प्रकार को कमी के लिए संयुक्त या पृथक् रूप से ऋंशदान देने का उसके सदस्यों का दायित्व सभा की उपविधियों के ऋघीन रहते हुए असीमित हो;
 - (11) 'सहकारी-वर्ष' (co-operative year)' का तात्पर्य प्रथम जुलाई से प्रारम्भ हो कर तीस जूम को समाप्त होने वाले वर्ष से है या ऐसे वर्ष से है, जो शासन द्वारा सहकारी सभात्रों के लेखे (accounts) रखने के लिए विहित किया जाय;
- (12) 'कृषि-संचालक (Director of Agriculture)' का तात्पर्य तत्समय नियुक्त कृषि-संचालक से है और इसके अर्जात राज्यशासन द्वारा इस अधिनियम के अधीन कृषि-संचालक के कर्जब्य सम्पादन के लिए नियुक्त कोई भी पदाधिकारी है;

- (13) 'विवाद (dispute)' का तांत्पर्य ऐसे विषय से है, जो दीवानी , ाववाद (civil litigation) का विषय हो सकता हो और सहकारी-सभा को देय या सहकारी-सभा द्वारा देय किसी भी राशि से सम्बन्धिन मांग (claim) इसके अपनार्णन है चाहे वह मांग (claim) स्वीकार की जाए या न की जाए;
- (14) 'कृषि-सभा (farming society)' का तात्पर्य ऐसी सभा से है, जो भूमि-विकास तथा कृषि करने के उत्तम उपायों का प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से बनाई गई हो;
- (15) 'संबीय-सभा (federal society)' का तात्पर्य ऐसी सभा से है, जिस की सदस्यता में कम से कम तीन चौथाई सदस्य सभाएं हों;
- (16) 'वित-प्रबन्धक ऋधिकोष (financing bank)' का तात्पर्थ ऐसी सहकारी-मभा से है, जिस के उद्देश्यों में ऋन्य सहकारी-सभा ऋगे को ऋगा देने के लिए धन जुटाने का उद्देश्य सिमालित हो;
- (17) 'विगणिक (liquidator)', का तात्पर्य सहकारी-सभा के कार्यों का ममापन करने के लिए (to wind up the affairs of) धारा 104 के अधीन नियुक्त व्यक्ति से है ;
- (18) 'सदस्य (member)' के ऋर्न्तगत ऐसा व्यक्ति है, जो किसी सभा का पंजीयन (रिज़स्ट्रेशन) करने के प्रार्थनापत्र में सम्मिलित हो तथा जिसे पंजीयन (रिज़स्ट्रेशन) के पश्चात् नियम तथा उपविधि के ऋनुसार सदस्य बना लिया गया हो;
- (19) 'शुद्ध लाभों (net profits)' का तात्पर्य ऐसे लाभों से हैं, जो स्थापन-व्यय (establishment charges), आक्रिमक व्यय (contingent charges), उधार तथा नित्तेप (loans and deposits) पर देय ब्याज, लेखा-परीत्त्या की भीस (audit fees) तथा अन्य विहित राशियां निकाल कर शेष रहे;
- (20) 'पटाधिकारी (officer)' के अन्तर्गत हैं,—प्रधान (president), उपप्रधान (vice president), सभापति (chairman), उपसभापति (vice chairman), सचित्र (secretary), सहसचित्र (assistant secretary), प्रबन्धक (manager), कोषाध्यत् (treasurer), प्रबन्धक-समिति का सदस्य, सदस्यों में में निवाचित लेखा-परीत्तक (auditor) तथा नियम या उपविधि के अधीन सहकारी-सभा के काम के सम्बन्ध में निदेश देने के लिए अन्य कोई प्राधिकृत व्यक्ति;
- (21) 'राजपत्र (official gazette)' का तात्पर्य हिमाचल प्रदेश के राजपत्र से हैं;
- (22) घारा 84 के प्रयोजनार्थ 'स्वामी' के ब्रान्तर्गत है-पृथक् पृथक् रूप में स्वामी, सांभोदार स्वामी या संयुक्त स्वामी (owner in severalty, in common or joint) श्रीर करूजा रखने वाला बन्धक गरहीता (mortgagee in possession);

- (23) 'विहित (prescribed)' का ताल्पर्य इस अविनियम के प्रधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से हैं;
- (24) 'उत्पादक-सभा (producer's society)' का तात्वर्य ऐसी सभा से है, जो वस्तुश्रां का उत्पादन तथा व्यवस्थापन अपने सदस्यों की सामृद्धिक सम्पत्ति के रूप में करने के उद्देश्य से बनाई गई हो आर ऐसी सभा इसमें सम्मिलित है, जो उस सभा के सदस्यों का अम सामृद्धिक रूप से व्यवस्थापन करने के उद्दश्य से बनाई गई हो;
- (25) 'रजिस्ट्रार (Registrar)' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन सहकारी सभाओं के रिजस्ट्रार के कर्तव्य सम्पादन करने के लिए नियुक्त व्यक्ति से है ख्रार इसके ख्रन्तिगत हैं संयुक्त रिजस्ट्रार, उपरिजस्ट्रार, सहरिजस्ट्रार तथा रिजस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त ऐसा व्यक्ति, जिम को इस अधिनियम के ख्रधीन रिजस्ट्रार की समस्त या कोई सी शक्तियां दी गई हों या समस्त ख्रथवा कोई से कर्तव्य सींपे गए हों;
- (26) 'नियमों (rules)' का तात्पर्य ऐसे नियमों से है, जो इस अधिनियम के अधीन वनएए गए हों या बनाए गए हुए समसे गए हों ;
- (27) 'सभा या पंजीकृत सभा (society or registered society)' का तात्वर्य इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत (रिजस्टर्ड) सभा में है या ऐसी सहकारी-सभा से हैं, जिसके सम्बन्ध में यह समका गया हो कि वह इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत (रिजस्टर्ड) है;
- (28) 'राज्यशासन (State Government)' का तात्पर्य हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल से हैं;
- (29) 'न्यासधारी (trustee)' का तात्पर्य न्यासधारी के रूप में धारा 58 की उपधार (1) के ब्राधीन नियुक्त व्यक्ति से हैं।

अध्याय 2

पंजीयन (रजिस्ट्रेशन)

- 3. रजिस्ट्रार.—राज्यशासन राज्य या उस के किसी भाग के लिए किसी व्यक्ति को सहकारी-समाश्चों का रिजस्ट्रार नियुक्त कर सकेगा, श्रीर उस रिजस्ट्रार की सहायता के लिए श्रन्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा तथा सामान्य या निरोष श्रादेश से ऐसे व्यक्तियों को इस श्रिधिनियम के ऋषीन रिजस्ट्रार की समस्त शिक्तियां या उन में से कोई सी शिक्ति दे सकेगा।
- 4. वे सभाएं, जिनका पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) हो सकेगा.—(1) इस अधिनयम तथा इस के अन्तर्गत बनाए गए किन्हीं भी नियमों के प्रतिबन्धाधीन ऐसी सभा, जिस का उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों के अनुसार अपने सदस्यों के समान हिस (common interest) की वृद्धि करना हो, या ऐसी सभा, जो उक्त सभा के काम को मुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से बनाई गई हो, तथा किसी विद्यमान सहकारी सभा के विभाजन (division) या विद्यमान सहकारी-सभाओं के एकीकरण (amalgamation) से बनी हुई सभाएं सीमित दायित्व (limited liability) के साथ या इस के बिना इस अधिनयम के अधीन पंजीकृत (रजिस्टर्ड) हो सकेंगी।

- (2) इस अधिनियम के अधीन, जो सभा सीमित दायित्व (limited liability) के साथ पंजी-कृत (रजिस्टर्ड) हो उस के नाम का अस्तिम शब्द ''सीमित (limited)'' होगा।
- (3) इस अधिनियम और नियमों के प्रतिबन्धाधीन कोई सहकारी-सभा रिजस्ट्रार के पूर्वानुमोदन से और एक सामान्य-बैठक में प्रस्ताव पारित करके अपने दायित्व (liability) का रूप बदल स्केगी।
- (4) जब उक्त प्रस्ताव पारित हो जाए तब सभा विहित रीति से उसकी लिखित सूचना (नोटिस) अपने समस्त सदस्यों और ऋगा-दाताओं (creditors) को देगी और किसी भी उपविधि (by-law) या संविदा (contract) में किसी विषय के प्रतिकृत्त होते हुए भी कोई भी सदस्य या ऋगाराता (creditor) उस पर सूचना की तामील हो जाने से छः मास के भीतर, अपने हिस्से (शेयर), अपना निल्पे (deposit) या अपना ऋगा वापस लेने के लिए विकल्प (option) प्रयोग कर सकेगा। ऐसा सदस्य या ऋगाराता (creditor), जो उपरोक्त अवधि में अपना विकल्प का प्रयोग न करे, उस के सम्बन्ध में दह समभा जायगा कि वह परिवर्तन से सहमत है।
 - (5) उक्त परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक या तो-
 - (क) समस्त सदस्य त्र्यौर ऋग्रहाता (creditors) उस से सहमत न हो गए हो या
 - (ख) ऐसे सदस्यों और ऋणदाताओं (creditors) की समस्त मांगें (claims) सम्पूर्ण रूप से पूरी न कर दी गई हों,. जो उपधारा (4) में निर्धिट विवल्प (option) का प्रयोग करते हैं।
- 5. सीमित दायित्व वाली संस्थात्रों के सदस्यों के स्वत्व (interest) ऋौर हिस्सों की पूंजी (share capital) पर आयं त्राग .— जहां किसी सभा के सदस्यों का दायित्व हिस्सों (शेयगें) द्वारा सीमित (limited) हो उस दशा में सभा से अन्य कोई भी सदस्य:—
 - (क) सभा के हिस्सों की पूंजी (share capital) के ऐसे भाग से ऋषिक अपने पास नहीं रख सकेगा, जो नियमीं द्वारा विहित हो और यह सभा के हिस्सों की पूंजी (share capital) के पांचवें भाग से ऋषिक नहीं होगा, या
 - (ख) सभा के ऐसे हिस्सों (शेयरों) में, जो दस हजार रूपये से या विहित राशि से अधिक हों, कोई स्वत्व, (interest) नहीं रखेगा या उस की मांग (claim) नहीं करेगा।
- 6. पंजीयन (रिजिस्ट्रेशन) की शर्ते जिस सभा की सदस्यता में कोई अन्य सभा सदस्य हो, उस में अन्य कोई भी ऐसी सभा इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत (रिजिस्टर्ड) नहीं की जायगी, जिस में 18 वर्ष में अधिक आयु वाले कम से कम दस सदस्य न हों, तथा जहां सभा का उद्देश्य अपने सदस्यों को उधार देने के लिए धन जुग्रना हो, उस दशा में यदि वे ब्यक्ति एक ही शहर या गांव या एक ही ग्रामसमूह में न रहते हों।
- 7. कुछ प्रश्नों का निरचय करने, में रिजस्ट्रार की शक्ति जब इस अधिनियम के अधीन या तो किसी सभा को संरचना, या उस के पंजीयन (रिजस्ट्रेशन) या उसे जारी रखने या उसके व्यवसाय के प्रयोजनार्थ या किसी व्यक्ति को सभा का सदस्य बनाने के प्रयोजनार्थ को प्रश्न चंदे या ऐसा को प्रश्न उटे आयािक कोई व्यक्ति शहर या ग्राम या ग्रामसमूह का निवासी है या नहीं या दो अप्रथन अधिक

प्रामों को ग्रामसपूद माना जाय या नहीं या कोई व्यक्ति सभा का सदस्य है या नहीं तो उसका निश्चय रिजस्ट्रार करेगा और यह निश्चय अन्तिम होगा।

- (2) प्रत्येक वयस्क व्यक्ति सहकारी-समा का सदस्य वनने के योग्य होगा, यदि वह ऋधिनियम, नियमों ऋोर उपविधियों की शर्तों (conditions) को पूरा करता हो।
- 8. पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिए प्रार्थनापत्र. पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रार के नाम से उसे एक प्रार्थनापत्र दिया जायगा।
 - (2) प्रार्थनापत्र पर "
 - (क) ऐसी सभा की दशा में, जिस की सदस्यता में कोई सभा सदस्य न हो, धारा 6 के उपबन्धों. के अनुसार योग्यता प्राप्त कम से कम दस व्यक्तियों के इस्ताहर होंगे, अप्रैर
 - (ख) ऐसी सभा की दशा में, जिस की सदस्यता में कोई सभा सदस्य हो उक्त प्रत्येक सभा की श्रीर से उचित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति श्रीर जहां सभा के समस्त सदस्य सभाएं न हों, दस श्रन्य सदस्य, या जहां श्रन्य सदस्य दस से कम हों, उस दशा में वे समस्त सदस्य हस्तान्तर करोंगे।
- (3) प्रार्थनापत्र के साथ सभा की प्रस्तावित उपिविधियों की टो प्रतिलिपियां साथ होंगी श्रीर जिन व्यक्तियों द्वारा या जिन की श्रोर से उक्त प्रार्थनापत्र दिया जाय वे सभा के सम्बन्ध में ऐसी मृजना (information) प्रदान करेंगे, जो रिजस्ट्रार मांगे।
- 9. इस अधिनियम के उपबन्धों से सहकारी सभाश्रों को विमुक्त (exempt) करने की शक्ति.—(1) राज्यशासन नियमों द्वारा
 - (क) किसी भी सभा या सभा श्रोणी को इस ऋधिनियम या इस के ऋधीन बनाए गरे नियमों के उपबन्धों की प्रयुक्ति से विभुक्त कर सकेगा, या
 - (ख) यह निदेश दे सकेगा कि उक्त सभा या सभा-श्रेणी पर ऐसे कोई भी उपबन्ध उस क्षीमा तक प्रयुक्त होंगे, जो नियमों में विधिष्ट की जाए।
- (2) इस श्रिघिनियम में किसी बात के होते हुए भी राज्यशासन प्रत्येक दशा में श्रीर एसी शर्ती (conditions) यदि कोई हों, के प्रतिबन्धाधीन, जो वह लगाना चाहे, विशेष श्रादेश द्वारा पंजीयन (रिजिस्ट्रेशन) के सम्बन्ध में किसी भी सभा या सभा-श्रेणी को इस श्रिधिनियम के किन्हों भी उपबन्धों से विमक्त कर सकेगा।
- (3) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्तियां इन शतों (conditions) के प्रतिब-धाधीन होंगी कि कोई भी नियम किसी भी सभा के प्रतिकृत उस सभा को अपनी स्थिति निवेदन करने का अवसर दिए बिना नहीं बनाया जाए।
- 10. पंजीयन (रिजिस्ट्रेशन). —यदि रिजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाए कि किसी सभा ने इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों का पालन किया है और इस की प्रस्तावित उपिधियों इस अधिनियम या नियमों के प्रतिकृल नहीं है तो वह सभा तथा उसकी उपविधियों का पंजीयन (राजस्ट्रेशन) कर सकेगा।

- 11. पंत्रायन (रिजिस्ट्रेशन) का साद्यः रिजिस्ट्रार द्वारा हस्तात्तरित पंजीयन प्रमाणपत्र (रिजिस्ट्रेशन सार्टीफिकट) इस बात का निर्णायक साद्य होगा कि उस में वर्णित सभा उचित रूप से पंजीकृत (रिजिस्टर्ड) है, यादे यह प्रमाणित न हो जाए कि सभा का पंजीयन (रिजिस्ट्रेशन) रद्ध कर दिया गया है।
- 12. सभा की उपविधियों का संशोधन —(1) किसी सभा की उपविधियों का कोई भी संशोधन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक सामान्य बैठक के प्रस्ताव द्वारा उसका अनुमोदन न हुआ हो और इस अधिनियम के अधीन उसका पंजीयन (राजस्ट्रेशन) न हो गया हो। इस हेतु संशोधन की दो प्रतिलिपियां विहित रूप से राजिस्ट्रार को मेजी जायेंगी।
- (2) यदि रजिस्ट्रार को यह समाधान हो जाता है कि उपविधियों का कोई संशोधन इस ऋधिनियम या नियमों के प्रतिकृत नहीं है तो वह संशोधन का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) कर लेगा।
- (3) जब रिजस्ट्रार किसो समा को उपविधियों के किसी मंशोधन का पंजीयन (रिजस्ट्रेशन) करता है तो वह समा को संशोधन की एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि दे देगा, जो उसके उचित रूप से पंजीकृत (रिजस्टर्ड) होने का निर्णायक साद्य होगी।
- 13. नाम में परिवर्तन श्रीर इसका प्रभाव कोई सभा सामान्य बैठक के प्रस्ताव द्वारा श्रीर रिजस्प्रार का श्रनुमोदन लेकर श्रपना नाम बढल सकेगी; किन्तु नाम परिवर्तन से सभा वा उसके किसी भी सदस्य या उसके भूतपूर्व श्रथवा मृत सदस्य के किसी श्रधिकार या श्राभार (obligation) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा श्रीर कोई भी विचाराधीन वैधानिक कार्यवाहियां (legal proceedings) सभा द्वारा या उसके विरुद्ध उसके नये नाम से जारी रखी जा सकेंगी।
- 14. सभा का एकीकरण और हस्तांतरण (amalgamation and transfer of societies).—कोई सी दो या अधिक सभाए रिजस्ट्रार के अनुनोदन से उक्त प्रत्येक सभा की तन्त्रयोजनार्थ निरोप सामान्य-बैठक में उपस्थित सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से पारित प्रस्ताय द्वारा एक ही सभा में एकीकृत (amalgamate) हो सकेगी: परन्तु प्रत्येक सदस्य की प्रस्ताय तथा बैठक के दिनांक की लिखित सूचना (नोटिस) ठीक 15 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए। उक्त एकीकरण (amalgamation) एकीकृत सभाओं (amalgamating societies) की निषि (funds) के विघटन या विभाजन (dissolution or division) के बिना किया जा सकेगा।
- (2) उक्त एकीकरण (amalgamation) हो जाने पर सम्बद्ध सभाश्रों का प्रस्ताव एकीकृत-सभाश्रों (amalgamating societies) की सकल-सम्पत्ति श्रौर दातव्यों (assets and liabilities) को एकीकृत-सभा (amalgamated societies) में निहित करने के लिये पर्याप्त हस्तांतरपत्र (conveyance) होगा।
- (3) कोई भी सभा उपवारा (1) श्रीर (2) में वर्णित प्रिक्रिया के श्रानुसार प्रस्ताव द्वारा श्रपनी सकल-सम्पत्ति श्रीर दातन्थों (assets and liabilities) को किसी भी ऐसी सभा को इस्तांतरित कर सकेगी, जो उन्हें लेने के लिए तैयार हो :

परन्तु जब उक्त किसी एकीकरण (amalgamation) या सकल-सम्पत्ति और दातव्यों (assets and liabilities) के इस्तांतरण में किसी सभा द्वारा अपने दायित्वों का किसी अन्य सभा को इस्तांतरण करना भी समिनांतत हो तो इन दोनों या इन समस्त सभाओं के ऋण्यदाताओं (creditors) को तीन महीने. की सूचना दिए बिना यह नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह भी कि यदि किसी भी सम्बद्ध सभा का या के कोई ऋग्णदाता (creditor or creditors) उनत एकीकरण (amalgamation) या सकल-सम्पत्ति ग्रौर दातन्त्रों (assets and liabilities) के हस्तांतरण पर श्रापत्ति करे या करें ग्रौर सम्बन्धितस भा या सभाग्रों को उनत एकीकरण (amalgamation) या हस्तांतरण के लिए नियत दिनांक से एक मास पूर्व इस निमित्त लिखित सूचना (नोटिस) दें ता एकीकरण (amalgamation) या हस्तांतरण तब तक नहीं किया जायगा जब तक उनत ऋगणदाता या ऋगणदातान्रों (creditor or creditors) को देय राशियां (dues) न चुका दी गई हों।

- 15. सभात्रों का विभाजन (division).—(1) कोई भी सभा रिजस्ट्रार के त्रान्मीटन से, तत्प्रयोजनार्थ सभा की विशेष सामान्य-बैटक में उपस्थित मदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ग्रापनी सभा को टो या ग्राधिक सभात्रों में विभक्त करने का निश्चय कर सकेगी, परन्तु प्रस्ताव ग्रार बैटक के दिनांक की लिखित मूचना (नीटिस) प्रत्येक सहस्य को ठीक 15 दिन पूर्व मिल जानी चाहिए। ऐसे प्रस्ताव में (जिसे यहां से ग्रारो इम धारा में प्रारम्भिक प्रस्ताव कहा गया है) सभा की सकल-सम्पत्ति ग्रार दातव्य (assets and liabilities) उन नई सभात्रों में, जिनमें उसे बांटने का विचार हो, विभाजित करने का सुभाव होगा श्रीर नई सभात्रों का कार्यचेत्र तथा नई सभा के सदस्यों की सख्या विशिष्ट हो सकेगी।
 - (2) प्रारम्भिक प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि सभा के समस्त सदस्यों श्रौर ऋग्यदाताश्रों (creditors) को भेजी जाएगी। प्रस्ताव की सूचना (नोटिस) विहित रीति से श्रन्य समस्त ऐसे व्यक्तियों को भी दी जाएगी, जिनके स्वत्वों (interests) पर सभा के विभाजन से प्रभाव पड़िगा।
 - (3) सभा का कोई भी सदस्य किसी उपिवधि के प्रतिकृत होते हुए भी प्रस्ताव मिलने के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर सभा को स्चना (नोटिस) दे कर नई सभाओं में में किसी का भी सदस्य न होने के लिए श्रापनी इच्छा प्रदर्शित कर सकेगा।
 - (4) सभा का कोई भी ऋगादाता (creditor) किसी भी निवन्ध (agreement) के प्रतिकूल होते हुए भी, उपरोक्त अवधि में सभा को सूचना (नोटिस) दे कर वह राशि, जो सभा ने उसे देनी हो, वापस लेने के लिए अपनी इच्छा प्रदर्शित कर सकेगा।
 - (5) अन्य कोई भी व्यक्ति, जिसके स्वत्यों पर विभाजन (division) से प्रभाव पड़े, सभा को स्चना (नोटिस) देकर तबतक विभाजन (division) पर आपित कर सकेगा जबतक उसकी माँग (claim) पूरी न हो जाए।
 - (6) उपधारा (2) के अधीन प्रारम्भिक प्रस्ताव की प्रतिलिपि सभा के समस्त सदस्यों और अधुण्याताओं (creditors) को भेज दिए जाने या प्रदान कर दिए जाने तथा सूचना (नोटिस) की प्रतिलिपि अपन्य व्यक्तियों को दे दिए जाने के पश्चात् तीन मास समाप्त हो जाने पर, प्रारम्भिक प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक दूसरी विशेष सामान्य-बैठक की जाएगी, जिसके लिए सदस्यों को कम से कम ठीक 15 दिन की सूचना (नोटिस) दी जाएगी यदि ऐसी बैठक

में उपांस्थत सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से या तो परिवर्त नों सहित या परिवर्त नों के बिना, जो रिजस्ट्रार की राय में सारभूत (material) न हों, प्रारम्भिक प्रस्ताव की पुष्टि कर दी जाए तो वह उपधारा (9) श्रीर उपधारा (10) के उपबन्धों के प्रतिबन्धाधों नर्ज सभाश्रों श्रीर उनकी उपविधियों का पंजीयन (रिजस्ट्रेशन) कर सकेगा। ऐसा पंजीयन (रिजस्ट्रेशन) हो जाने पर पुरानो सभा के पंजीयन (रिजस्ट्रेशन) के बारे में यह समभा जायगा कि वह रद्द कर दिया गया है श्रीर सभाइस प्रकार रद्द होने के दिनांक से विचिटित (dissolved) समभी जाएगी।

- (7) इस विषय का निर्णय करने के लिए रिजस्ट्रार की राय अपनितम होगी श्रायािक प्रारम्भिक प्रस्ताव में किए गए परिवर्तन सारभूत (material) हैं या नहीं श्रीर उस पर कोई श्रयील नहीं हो सकेगी।
- (8) उपधारा (6) में निर्दिष्ट विशेष सामान्य-बैठक में अन्य प्रस्ताव द्वारा निम्नलिखित विषयों की व्यवस्था की जाएगी:—
 - (त्र) उन समस्त सदस्यों के हिस्सों की पूंजी (share capital) की वापसी, जिन्हों ने उपधारा (3) के त्राधीन सूचना (नोटिस) दी हो,
 - (त्रा) उन समस्त ऋणदातात्रों (creditors) की मांगों (claims) की पूर्ति, जिन्होंने उपधारा (4) के ब्रधीन सूचना (नीटिस) दो हो,
 - (इ) जिन अन्य व्यक्तियों ने उपधारा (5) के अधीन सूचना (नोटिस) दी हो उनकी मांगों (claims) की रिजिस्ट्रार के निश्चय के अनुसार पूर्ति या जैसा रिजिस्ट्रार निर्देश दे उसके अनुसार, उनकी मांगों (claims) की सुरक्ता:
 - परन्तु कोई भी सदस्य या ऋगादाता (creditor) या ऋग्य व्यक्ति उक्त वापसी या मांग पृतिं का तब तक श्रिकारी नहीं होगा, जबतक प्रारम्भिक प्रस्ताव की उपधारा (6) के उपबन्धानुसार पुष्टि नहीं हो जाती।
- (9) यदि उस अवधि में, जो रिजस्ट्रार उचित समभे, उपधारा (8) में निर्दिष्ट सदस्यों के हिस्सों की पूंजी (share capital) वापम नहीं दी जाती या उसी उपधारा में निर्दिष्ट सम्पादाताओं (creditors) की मांगें पूरी नहीं की जातीं या उपधारा (8) के खन्ड (इ) में दी गई व्यवस्था के अनुसार अन्य व्यक्तियों की मांगें पूरी या सुरिचित नहीं की जातीं तो रिजस्ट्रार नई सभा को पंजीकृत (रिजस्ट्रार) करना अस्वीकार कर सकेगा।
- (10) ट्रांन्कर आफ प्रापरटी ऐक्ट, 1882 या इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 में किसी यत के होते हुए भी नई समाओं का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) मूल सभा को सकलसम्पत्ति और टातव्यों (assests and liabilities) को नई समाओं में उपधारा (6) के अधीन पुष्ट प्रारम्भिक टम्नाव में विशिष्ट रोति के अनुसार निहित करने के जिए पर्याप्त हम्तांतरपत्र (conveyance) होगा।

अध्याय 3

श्रिधिकार और दायित्व

- 16. जब तक देय राशियां ने चुका दी जाएं तब तक सदस्य अधिकार-प्रयोग नहीं करें तो. कोई भी व्यक्ति सभा के सदस्य के नाते तब तक अधिकार प्रयोग नहीं करेगा, जब तक सदस्यता के सम्बन्ध में उसने सभा को ऐसी चुकती न कर दी हो या सभा में ऐसा स्वत्व (interest) प्राप्त न कर लिया हो, जो उक्त सभा के नियमों या उपविधियों द्वारा विहित हो।
- 17. सद्स्यों का सत. —(1) किसी भी सभा के किसी सदस्य को उस के मामलों में एक में अधिक मताधिकार प्राप्त नहीं होगा, परन्तु समान मत होने पर सभापति एक निर्णायक मत दे सकेगा।
- (2) जहां सभा का कोई हिस्सा (शेयर) संयुक्त रूप में एक से आधिक व्यक्तियों के पास हो उस दशा में केवल वही व्यक्ति मताधिकारी होगा जिसका नाम हिस्से के प्रमाणपत्र (शेयर मर्टीफिकेट) में पहले लिखा हो।
- (3) कोई सभा, जिसने ऋपनी निधि का कोई ऋंश किसी अन्य सभा के हिस्मों (शेयरों) में विनियोजित (invest) किया हो, उस ऋन्य सभा के मामलों में रत देने के लिए विहित संख्या में ऋपने सदस्य नियुक्त कर सकेगी।
- 18. हिम्से (शेयर) या म्वत्व (interest) के हस्तांतरण पर आयरण.—(1) सभा की मृं जी में किसी सदस्य के हिस्से या स्वत्व (share or interest) का हस्तांतरण या प्रभार अधिकतम भारण (maximum holding) के सम्बन्ध में ऐसी शतों के प्रतिबन्धाधीन होगा, जो इस अधिनियम या नियमों द्वारा विहित हों।
- (2) कोई सदस्य किसी सभा की पूंजी या सम्पत्ति का या उनके किसी भाग का अपना हिस्सा (शेयर) या अपना स्वत्व (interest) तब तक हस्तांतरित नहीं करेगा, जब तक---
 - (क) उक्त हिस्सा (शेयरों) या स्वत्व (interest) उनके पास कम से कम एक वर्ष तक न रहा हो ;
 - (ख) सभा या सभा के किसी सदस्य या ऐसे व्यक्ति को, जिसका प्रार्थनपत्र सभा द्वारा स्वीकार हो गया है, इस्तांतरित न कर दिया हो या उसका प्रभार न दे दिया हो; श्रीर
 - (ग) सिमात ने उन्त इस्तांतरण अनुमोदित न कर दिया हो।
- 19. सदस्यों का दायित्व सभा का समापन (winding-up) होने पर सभा के सदस्य मं युक्त रूप से ब्रीर पृथक रूप से ऐसी किसी भी कभी को, जो सभा की सकलसम्पत्ति (assets) में हुई हो, पूरा करने के लिए
 - (क) ऐसी सभा की दशा में, जिसका दायित्व असीमित हो, बिना किसी सीमा के उत्तर-दायी होंगे, और
 - (ख) सीमित दायित्व वाली सभा की दशा में उस सीमित राशि तक उत्तरदाई होंगे, जो उपविधियों में ब्यवस्थित हो।

- 20. भूतपूर्व सहस्यों का दायित्व.—भूतपूर्व सदस्य की सदस्यका समाप्त होने के ममय सभा के उधार (debt) की जो स्थिति हो उसके लिए भूतपूर्व सदस्य उत्तरदायी रहेगा, यदि धारा 103 के अधीन समापन का आदेश (order of winding up) उस दिनांक से दो वर्ष के मध्य प्रभावी हो जाए, जिस दिनांक से उसकी सदस्यता समाप्त हुई हो।
- 21. मृत सदस्य की सम्पदा पर दायित्व. मृत सदस्य की मृत्यु के समय सभा के उधार (debt) की जो स्थिति हो उसके लिए मृत सदस्य की सम्पदा (estates) पर दायित्व रहेगा, यदि धारा 103 के अधीन समापन का आदेश उसकी मृत्यु के दिनांक से दो वर्ष के मध्य प्रभावी हो नाए।
- 22. सदस्यों द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति और अपनी सकलसम्पत्ति के अन्याप ता (alienation) की सूचना (information) प्रदान किया जाना (1) अपनी सकलसम्पत्ति और दानव्यों (assets and liabilites) का एक पूरा, मत्य और ठीक व्योरा—
 - (क) श्रसीमित दायित्व वाली सभा की सदस्यता के प्रार्थी द्वारा श्रपने प्रार्थ नापत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा,
 - (ख) ब्रासीमित दायित्व वाली सभा के सदस्य द्वारा उस समय प्रस्तुत किया जायगा जब र्राजस्ट्रार या उसके सामान्य या विशेष ब्रादेश द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या वित्त प्रबन्धक ब्राधिकोष (financing bank) ऐसी ब्रापेत्ता करे, श्रीर
 - (ग) किसी भी श्रन्य सभा के रूदस्य द्वारा उधार (loan) लेने के लिए या प्रतिभू (surety) के रूप में स्वीकार कर लिए जाने के लिए दिए गए प्राथ⁹नापत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
- (2) सभा का कोई सदस्य प्रत्येक व्यवहार (transaction) पूरा होने से पहले उस सभा को. जिसका वह सदस्य हो, ग्रपनी अचल सम्पत्ति (immovable property) या उसके किसी भाग या हिस्से (portion or share) की विकी, बन्धक या हस्तांतरण, चाहे वह किसी भी रूप में हो, श्रीर ऐसे किसी उधार (debt) के सम्बन्ध में, जिसे उक्त सम्पत्ति की प्रतिभूति (security) पर लेने का विचार हो, पूरी, सत्य श्रीर ठीक सूचना (information) देगा

ग्रध्याय

सहकारी सभात्रों की संस्थिति (status) त्रौर प्रबन्ध

23. मभाएं निगम निकाय (bodies corporate) होंगी. — किसी सभा का पंजीयन (रिजिस्ट्रेशन) होने से वह उस नाम से एक निगम निकाय (body corporate) बन जाएगी, जिस नाम से वह मंजीकृत हुई हो। इस का शाश्वत उत्तराधिकार होगा नथा एक सामान्य मुहर होगी और इसे सम्पत्ति रखने, सं विदा करने, बाद चलाने तथा बाद से प्रतिरचा करने और अन्य वैधानिक कार्यवाहियां चलाने और उन में प्रतिरचा करने तथा अपनी संरचना (constitution) के प्रयोजनार्थ समस्त आवश्यक कार्य करने का आविकार प्राप्त होगा।

- 24. सहकारी सभा का चांतिम प्राचिकार.—(1) प्रत्येक शहकारी सभा का घ्रांतिम प्राधिकार सामान्य-बैंटक में उपस्थित शदस्यों की सामान्य सभा को प्राप्त होगा:
- परन्तुं विहित परिस्थितियों में स्रांतिम प्राधिकार उन स्दस्यों के विहित रीति से चुने हुए स्रौर सामान्य बैटक में एकत्रित प्रतिनिधियों में निहित हो स्केगा।
 - (2) सामान्य बैठक बुलाई जाएगी ऋौर विहित रीति से वह श्रपना प्राधिकार प्रयोग करेगी।
- 25. वार्षिक सामान्य-वैठक.—(1) प्रत्येक सभा की सामान्य-वैठक प्रत्येक सहकारिता-वर्ष में निम्निलिखित प्रश्लोजनों के लिए कम से कम एक बार होगी:—
 - (क) प्रवन्धक समिति के सदस्यों और अन्य ऐसे पदाधिकारियों का चुनाव, जिनकी व्यवस्था उप-विधियों में की जाए.
 - (অ) धारा 74 में निर्दिष्ट लेखा परीचा प्रतिबेदन (श्रीडिट रिपोर्ट) पर विचार, श्रीर
 - (ग) अन्य ऐसे किसी भी विषय पर विचार, जो उपविधियों के अनुसार प्रस्तुत किया जाए।
- (2) उक्त बैं डकें अंतिम पूर्व वर्ती बैं ठक के दिनांक के पश्चात् कम से कम 15 मास के भीतर की जाएगी और यदि रिजिस्ट्रार विशेष कारणों के आधार पर अवधि न बढ़ा दे तो धारा 74 में निर्दिष्ट लेखा-परीचा प्रतिवेदन (औडिट रिपोर्ट) की सभा द्वारा प्राप्ति के लिए विहित दिनांक से तीन मास के भीतर की जाएगी:
- परन्तु रिजस्ट्रार उन कारणों के आधार पर, जो वह लेखबद्ध करेगा, उपधारा (1) और उपधारा (2) में विहित अविध समाप्त हो जाने के पश्चात भी ऐसी बैठक करने की अनुमित दे सकेगा।
- 26. विशेष सामान्य-बैठक.—(1) प्रबन्धक-समिति के सदस्यों के बहुमत से किसी भी समय एक विशेष सामान्य-बैठक बुलाई जा सकेगी,
 - (क) किसी भी ऐसी सहकारी सभा, जिस में पांच सी से श्रिधिक सदस्य न हों, के एक चौथाई सदस्यों या किसी भी श्रन्य सभा के 1/5 सदस्यों की लिखित मांग पर विशेष सामान्य बैंटक बुलाई जाएगी, या
 - (ख) रजिस्ट्रार के निदेश से विशेष सामान्य-बैठक बुलाई जाएगी:
- परन्तु ऐसी सभा की दशा में, जिस में टो हजार पांच सौ से ऋधिक सदस्य हों, खंड (क) के ऋधीन मांग-पत्र विहित रीति से चुने हुए प्रतिनिधियों (delegates) द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- (2) रिजस्ट्रार या लिखित रूप में उस के विशेष आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत व्यक्ति किसी भी समय सभा की सामान्य बैठक बुला सकेगा और उपधारा (1) के अधीन सदस्यों की मांग पर या गिजस्ट्रार के निदेशानुसार सभा के बैठक न बुला सकने पर उक्त बैठक बुला सकेगा।
- (3) ऐसे किसी नियम या उपविधि के होते हुए भी, जिस में सामान्य-बैठक की सूचना की अवधि श्रीर जुलाने का ढंग विहित किया गया हो, उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार के निदेशानुसार

बुलाई गई बैठक की दशा में रिजस्ट्रार या उपधारा (2) के ऋघीन बुलाई गई बैठक की दशा उक्त व्यक्ति बैठक का समय ऋौर स्थान, बैठक बुलाने का ढंग ऋौर वे विषय, जिन पर उस में विचार किया जाएगा, विशिष्ट कर सकेगा।

- . 27. प्रवन्धक समिति प्रत्येक सहकारी सभा का प्रबन्ध नियमों ऋौर उपविधियों के ऋतुसार निर्मित प्रबन्धक समिति में निहित होगा, जो ऐसी शक्तियां प्रयोग करेगी, ऋौर ऐसे कर्त व्य सम्पादन करेगी, को इस ऋधिनियम, नियमों ऋौर उपविधियों द्वारा क्रमशः उसे प्रदत्त या उस पर ऋारोपित हो।
- 28. सहकारी सभा के मामलों का प्रबन्ध करने के लिए सरकारी कर्मचारी प्रनियुक्त (depute) करने की शिक्ति.— राज्यशासन सहकारी सभा के प्रार्थ नापत्र देने पर श्रीर ऐसी शर्तों पर, जो विहित की जाएं, सभा के मामलों का प्रबन्ध करने के लिए किसी सरकारी कर्म चारी को सभा की सेवा में प्रनियुक्त कर सकेगा श्रीर इस प्रकार प्रनियुक्त सरकारी कर्म चारी विहित शिक्तयां प्रयोग करेगा श्रीर विहिन कर्त व्य सम्पादन करेगा।
- 29. प्रयन्धक समिति का विघटन (dissolution) तथा पुनः संरचनाः—(1) यदि धारा 76 के ऋधीन निरीक्षण के पश्चात्या धारा 77 के ऋधीन परिष्रच्छा पर रिजस्ट्रार का ऐसे कारणों में, जो वह लेखबद्ध करेगा, यह समाधान हो जाए कि सहकारी सभा की प्रबन्धक समिति सभा के कार्यों का अने प्रवन्ध नहीं कर रही है, तो वह धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ख) के ऋधीन यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे समय में, जो वह निश्चित करे, प्रबन्धक समिति के विघटन तथा, उसकी पुनः संरचना करने र्के लिए सभा की विशेष सामान्य-बैठक की जाए।
- (2) उपधास (1) के श्रधीन दए गए निदेश में र्राजिस्ट्रिंस ऐसे कारणों के श्राधार पर, जो वह लेखबद्ध करेगा, यह श्रादेश दे सकेगा कि विघटित होने वाली प्रवन्धक समिति के समस्त या कोई भी सदस्य ऐसी तीन वर्ष से श्रानधिक श्रावधि के लिए, जो वह निश्चित करेगा, सभा के पदाधिकारी के रूप में चुने जाने या नियुदित के लिए श्रादीग्य होंगे।
- (3) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाये कि पूर्ववर्ती श्रन्तिम उपधारा के श्रधीन प्रवन्धक मिर्मित के परिवर्तन या निल बन में किसी भी प्रकार का बिलम्ब करने से सभा को ऐसी हानि हो जाएगी, जिसकी पूर्ति न हो सके, तो वह प्रवन्धक समिति या संचालक पर्वद् (Board of Directors) का अधातया या पूर्णत्या तुरन्त निलम्बन करने का आदेश दे सकेगा और उक्त सहकारी सभा के मामलों का आवश्यक अवधि तक प्रबन्ध करने के लिये एक प्रशासक की नियुक्ति ऐसी शर्तों पर कर सकेगा, को वह विहित करे, किन्तु यह अवधि धारा 30 की उपधारा (1) और उसके परादिक में व्यवस्थित अवधि में अधिक नहीं होगी।
- 30. प्रवन्धक समिति का विघटन तथा सहकारी सभा के कार्यों का प्रवन्ध करने के लियं व्यक्ति की नियुक्ति—(1) यदि ऐसी अविध में तथा ऐसी रीति के अनुसार, जो धारा 29 के अधीन रिजस्ट्रार निर्देशित करे, प्रवन्धक समिति का विघटन तथा उसकी पुनः संरचना नहीं की जाती तो वह बादेश द्वारा प्रवन्धक समिति का विघटन करेगा, जिसकें सदस्य तुरन्त ही अपना पद खाली कर देगें और

तदुपरान्त रजिस्ट्रार एक या ऋधिक उपयुक्त व्यक्तियों को ऐसी शर्तों पर जो विहित की जार्ये, सहकारी सभा के मामलों का एक वर्ष से ऋनधिक ऋवधि के लिये प्रबन्ध करने के हेतु और ऐसे दिनांक तक, जो र्राजस्ट्रार नियत करे, नई श्रबन्धक समिति बनाने का प्रबन्ध करने के लिये नियुक्त करेगा :

परन्तु राज्यशासन एक वर्ष की अविध् को पुनः दो वर्ष से अनिधिक ऐसी अविधि तक बढ़ा सकेगा, जो वह उचित समभे ।

- (2) उपधारा (1) के ऋधीन आदेश लिख कर दिया जायगा। उसमें वे कारण दिये जाये में जिनके आधार पर वह दिया गया हो और यह उसी समय दिया जायेगा जब प्रबन्धक समिति को तत्सम्बन्धी ऋपनी आपत्तियां निवेदन करने का ऋवसर दिया जा चुका हो।
- 31. धारा 30 के ऋधीन नियुक्त व्यक्ति की पदावधि धारा 29 या 30 के ऋधीन नियुक्त व्यक्ति तब तक पदासीन रहेगा, जब तक प्रबन्धक समिति का धुन: निर्माण नहीं हो जाता या उसकी नियुक्ति रिजस्ट्रार ने रह न कर दी हो।
- 32. समिति के विघटन पर सहकारी सभा का प्रबन्ध.—धारा 29 या 30 के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्ति की पदाविध के मध्य—
 - (क) सहकारी सभा की समस्त रूम्पति रिजन्ट्रार में निहित होगी;
 - (ख) इस बात के होते हुए भी कि धारा 113 के अन्तर्गत, अपिल की गई है रिजस्ट्रार के नियंत्रणाधीन उक्त व्यक्ति उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा आरे व समस्त कर्तव्य सम्पादन करेगा, जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अधीन प्रबन्धक सिमिति द्वारा या सभा के किसी पदाधिकारी द्वारा प्रयोग की जायें सा सम्पादित किये जायें।

श्रध्याय 5

सहकारी सभात्रों के कर्तव्य तथा श्राभार

- 33. सभात्रों का पता नियमों के त्रानुसार प्रत्येक सभा का एक पंजीकृत पता (registered address) होगा, जिस पते पर समस्त सूचनाएं (नोटिस) तथा पत्रादि भेजे जा सकें त्रौर वह उक्त पते में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने के 30 दिन के भीतर इस परिवर्तन की लिखित सूचना (नोटिस) रिजस्ट्रार को भेजेगी।
- 34. ऋधिनियम, नियमों तथा उपविधियों की प्रतिलिप का निरीच्च हो सकेगा.— प्रत्येक सभा अपने पंजीकृत (रिजस्टर्ड) पते पर हर उचित समय में निरीच्च के लिये निम्नलिखित क्लुएं तैयार रखेगी—
 - (क) इस अधिनियम की एक प्रतिलिपि,
 - (ख) उक्त सभा में प्रयुक्त होने वाले नियमों की प्रतिलिकि,
 - (ग) उक्त सभा की उपविधियों की एक प्रतिलिपि, और

- (ध) इसके सदस्यों की एक पंजी (रिजस्टर)।
- 35. वार्षिक सन्तुत्तन पत्र (balance sheet) का प्रकाशन प्रत्येक सहकारी सभा लेखा बरीतक (ऋौडियर) द्वारा प्रमाणित सन्तुत्तन पत्र (balance sheet) विद्ति रीति से प्रत्येक वर्ष प्रकाशित करेगी।
- 36. सूचना (information) प्रस्तुन करने का दायित्व. सहकारी सभा का प्रत्येक पदाधिकारी नथा प्रत्येक सदस्य सभा के व्यवहारों (transactions) में या कार्य-संचालन के सम्बन्ध में ऐसी सूचना प्रदान करेगा, जो रजिस्ट्रार या लेखा परीच्चक (श्री डिटर), विवाचक (arbitrator), विगणिक (liquidator) या निरीच्चण अथवा परिपृच्छा करने वाला कोई भी व्यक्ति उनसे मांगे।

ऋध्याय ह

सहकारी सभाक्षों की सम्पत्ति तथा निधि

- 37. निधि का विनियोजन (investment of funds).— (1) पंजीकृत (र जस्टर्ड) सभा अपनी निधि का विनियोजन (investment) निम्निलिखित में कर सकेगी या निम्निलिखित के पास जमा करा सकेगी
 - (क) पोस्ट आफिस सेविग बैंक मे, या
 - (ख) इंडियन ट्रस्ट ऐक्ट, 1882 (Indian Trust Act, 1882) की घारा 20 में विशिष्ट किन्हीं भी प्रतिभृतियों (securities) मैं, या
 - (ग) किसी अन्य पंजीकृत (राजिस्टर्ड) सभा के हिस्सों (शेयरों) मैं या प्रतिभृति में, या
 - (घ) किसी बैंक के पास या रजिस्ट्रार द्वारा उस कार्य के लिये अनुमोदित वैंकिंग का कार्य करने बाले ब्यक्ति के पास, या
 - (च) नियमों द्वारा अनुमती किसी अन्य रीति से।
- (2) इस अधिनियम का प्रारम्भ होने से पूर्व लगाई गई राशियां या जमा की गई राशियां, यि वे इस अधिनियम का प्रचलन होने की दशा में वैध हों तो एतत् द्वारा वे मान्य होंगी और उन्हें पुष्ट किया जाता है।
- 38. लाभों का वितरण.—(1) तिहित दशा को छोड़ कर अशीमित दायित्व वाली सभा के सम्बन्ध में लाभ का वितरण नहीं किया जायेगा, और इस धारा में दी गई व्यवस्था को छोड़ कर सभा की निधि का कोई भी भाग उसके सदस्यों को लाभांश (dividend) या अर्थितिरक्त लाभांश (bonus) या किभी अन्य रूप में नहीं बांदा जायेगा।
 - (2) कोई भी लामांश (dividend) या ऋतिरिक्त लामांश (bonus)--
 - (क) केवल उन्हीं लामों में से बांटा जायगा, जिन्हें लेखा-परीक्तक ने वास्तव में प्राप्त लाम प्रमाणित किया हो, या
 - (स) र्राजस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं बांटा जायेगा, यांद लेखा-परीक्क बह प्रांतवेदन (रिपोर्ट) दे कि कोई सकत-कम्पत्त (assets) ठाक नहीं है या संद्रश्य है

श्रीर यह सिकारिश भी कर कि उक्त स्वीकृति श्रावश्यक है:

परन्तु लेखा-परीद्धक ऐसी सिफारिश तब तक नहीं करेगा, जब तक उक्त सकलसम्पनि पृग्ततं:
पर्याप्त न हो।

- (ग) किसी वर्ष के शुद्ध लाभों में से धारा 39 की उपधारा (2) द्वारा श्रिपेत्ति अनुपात निकाल कर आर्रात्तित निधि में जमा कराने के पश्चात् उपधारा (2) के प्रतिबन्धाधीन, उक्त लाभों का क्काया गत वर्षों के अविनिहित लाभों सिंहत, यदि कोई हों, विहित मात्रा में और विहित शतों के अधीन सदस्यों में लाभांश (dividend) के रूप में वितरित किया जा सकेगः या किसी सदस्य या कर्मचारी को ऐसी विशिष्ट सेवा के लिये, जो उसने सभा को प्रदान की हो, अतिरिक्त लाभ (bonus) या परिलाभ (remuneration) के रूप में दिया जा सकेगा।
- (?) धारा 40 के अधीन कोई भी ऋ शदान (contribution) केवल वास्तव में प्राप्त लाभों में से ही दिया जा सकेगा, ऋन्यथा नहीं।
- 39. त्रारित्त निधि (reserve fund).—(1) प्रत्येक सभा अपने व्यवहार से प्राप्त लामी, यदि कोई हों, के सम्बन्ध में एक आरित्तत-निधि रखेगी।
- (2) प्रत्येक वर्ष में सभा के शुद्ध लाभों (net profits) का कम से कम पञ्चीस प्रतिशत या इससे अधिक ऐसा अनुपात, जो उक्त सभा या सभा-श्रोणी के लिये विहित किया जाए, आरिच्त निधि में जमा कर दिया जाएगा।
- (3) उस मात्रा श्रीर रीति को छोड़ कर, जो विहित की जाए, सभा के व्यवसाय में उसकी श्रार्याज्ञत-निश्च (reserve fund) का कोई भी भाग प्रयोग में नहीं लाया जाएगा।
- (4) ब्रारिक्त निधि का ऐसा भाग, जो सभा के व्यवसाय में प्रयोग न हुन्ना हो निम्निलिखित में विनियोजित (invest) कर दिया जाएगा या निम्निलिखित के पास जमा करा दिया जाएगा।
 - (क) पोस्ट आफिस सेविंग बैंक में, या
 - (ख) इंडियन ट्रस्ट ऐक्ट, 1882 (Indian Trust Act, 1882) की धारा 20 में विशिष्ट प्रतिभूतियों में से, उस धारा के खंड (e) में विशिष्ट प्रतिभृतियों को छोड़ कर, किसी भी प्रतिभृति में, या
 - (ग) रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किसी श्रन्य बैंक में ।
- 40. परोपकार सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए श्रंशदान (contribution) विसी वर्ष के शुद्ध लामों का, धारा 39 की उपधारा (2) द्वारा अपोद्धित अनुपात आरिद्धित निधि में डालने के पश्चात् कोई सभा नियमानुसार चैरिटेबल ऐंडोमैंट्स ऐक्ट, 1890 (Charitable Endowments Act, 1890) की धारा 2 में परिभाषित किसी भी परोपकार सम्बन्धी प्रयोजन के लिए उक्त बकाया के दस प्रतिशत तक अंश्रदान दे सकेगी।

- 41. मिविष्य-निधि (प्रोविडेंन्ट फड).— (1) कोई भी सभा, स्थितिश्र तुसार, श्रपने सदस्यों, पटाधिकारियों या कर्मचारियों के लिए एक भविष्य निधि (प्रोविडेंन्ट फंड) स्थापित कर सकेगी श्रीर जब धारा 39 की उपधारा (2) द्वारा श्रपेदित किसी वर्ष के शुद्ध लामों का श्रनुपात श्रारित्त-निधि में जमा करा दिया गया हो श्रीर जब धारा 40 द्वारा श्रपेदित श्रंशदान दे दिया गया हो तो सभा भविष्य-निधि (प्रोविडेंन्ट पंड) में ऐसा श्रंशटान दे सकेगी, जिसकी नियमों या उपविधियों में व्यवस्था की जाए।
- (2) उक्त भविष्य-निधि (प्रोविडेन्ट फंड) का प्रयोग सभा के व्यवसाय में नहीं किया जाएगा, किन्तु वह धारा 39 की उपधारा (4) में विशिष्ट एक या श्रिधिक रीतियों में विनियोजित (intvest) कर दी जाएगी या जमा कर दी जाएगी।
- 42. उधार (loans) पर ऋायंत्रण.—(1) कोई भी पंजीकृत (र्श्वस्टर्ड) सभा स्टर्य के अ तिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को उधार नहीं देगी:

परन्तु रिजस्ट्रार की सामान्य या विशेष स्वीकृति लेकर कोई पंजीकृत (रिजस्टर्ड) सभा अन्य पंजीकृत (रिजस्टर्ड) सभा को या ऐसे व्यक्ति को, जो सदस्य न हो, ऐसी शतों के अधीन रहते हुए उधार (loan) है सकेगी, जो विहित की जाएं।

- (2) उस दशा को छोड़ कर जब रिजस्ट्रार की स्वीकृति ले ली गई हो, असीमित दायित्व (unlimited liability) वाली कोई सभा चल-सम्पत्ति (moveable property) की प्रतिभृति (security) पर धन उधार नहीं देगी।
- (3) राज्यशासन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा को या पंजीकृत (र्गजिस्टर्ड) सभा-श्रे ग्री को अचल-सम्पत्ति (immovable property) के बन्धक (mortgage) पर अन उधार देना मना कर सकेगी या उस पर आयन्त्रग्रा लगा सकेगी।
- 43. उधार तोने (borrowing) पर आयन्त्रण.—कोई पंजीकृत (रिजस्टर्ड) सभा उन व्यक्तियों में, जो सदस्य न हो, केवल उसी सीमा तक और उन्हीं शतों पर, जो नियमों या उपविधियों द्वारा विहित की जाएं, निचेप (deposits) या उधार प्राप्त करेगी।
- 44. ऐसे व्यक्तियों से, जो सदस्य न हो, अन्य व्यवहार करने पर आयं त्रणः —धारा 42 स्त्रीर 43 में व्यवस्थित दशा को छोड़ कर पंजीकृत (रिजस्टर्ड) सभा का सदस्यों के सिनाए अन्य व्यक्तियों से व्यवहार ऐसे निपेधों (prohibitions) और आयंत्रणों, यदि कोई हों, के अभीन रहते हुए होगा, जैमा राज्य शासन नियमों द्वारा विक्ति करे।
- 45 किसी सहकरी प्रयोजन कें लिये अश्वान यदि रिजस्ट्रार ऐसा करने का निर्देश दे तो कोई भी समा किसी वर्ष में शुद्ध लाभों (net profits) का एक चौथाई आरिचत निधि में जमा कराने के पश्चात् शेष शुद्ध लाभों के पांच प्रतिशत से अनिधक राशि ऐसे सहकारी प्रयोजन के लिये अश्वान के रूप में दे सकेगी, जो निहित किया जाए।
 - 16. सहकारी शिचा-निधि में अ शद्। न . प्रत्येक सभा जो, अपने सदस्यों को 4 प्रतिशत पर

या श्रिषिक मान (rate) पर लाभांश (dividend) देती हो, विहित सहकारी शिक् ।- निधि में श्रीर विहित मान (rate) से श्रंशटान देगी।

अध्याय 7

महकारी सभात्रों के विशेषाधिकार श्रीर शिक्तियां

- 47. सहकारी सभात्रों की लगान सम्बन्धी बाद (rent suit) की सूचना (नोटिस) मंगवाने की शक्ति. ऐसी सभा जिस के उद्देश्यों के अन्तर्गत अपने सदस्यों, को उधार (loan) देना भी समितित हो और ऐसे वित्त प्रबन्धक अधिकीष, यदि कोई हो, जिनकी उक्त सभा सदस्य हो, उक्त सभा के किसी भी सदस्य के भूमिपति पर विहित रीति से सूचना (नोटिस) की तामील कराके भूमिपति से यह अपेद्धा कर सके में कि वह उक्त सदस्य के विरुद्ध उसके द्वारा दायर किये गये किसी लगान सम्बन्धी बाद (rent suit) की सूचना (नोटिस) उक्त सभा या वित्त प्रबन्धक अधिकोष या इन दोनों को प्रदान करे।
- 48. सदस्यों के हिस्सों (शेयरों) के सम्बन्ध में प्रभार और प्रतिसादन (set off). पूंजी के हिस्से या स्वत्व (share or interest) और किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के निचेप (deposit) और उकत किसी सदस्य या भृतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा सभा को देय किसी उधार (debt) के सम्बन्ध में किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य को देय किसी भी लाभांश, अतिरिक्त लाभ या लाभों पर, पंजीकृत सभा का प्रभार होगा, और वह किसी सदस्य, या भृतपूर्व या मृत सदस्य के नाम पर जमा या उस को देय राशि उक्त किसी उधार (debt) की खुकती करने में प्रतिसादित (set off) कर सकेगी।
- 49. हिस्से (शेयर) या स्वत्व (interest) की कुर्की नहीं हो सकेगी.— धारा 18 के उपवन्धाधीन किमी पंज कृत (रिजस्टर्ड) सभा की पूंजी में किसी सदस्य के हिस्से (शेयर) या स्वत्व (interest) की, उक्त मदस्य द्वारा लिये गये किसी उधार या उठाये गये किमी दायित्व के सम्बन्ध में किसी न्यायालय की किसी डिक्री या ब्रादेश के अधीन कुर्की या बिक्री नहीं हो सकेगी, ख्रीर न ही प्रोविंशियल इन्सीलवेंसी ऐक्ट, 1920 (Provincial Insolvency Act, 1920) के अधीन कोई भी ख्रादाता (receiver) उक्त हिस्से (शेयर) या स्वत्व (interest) की मांग करने या उस पर मांग रखने का अधिकारी होगा।
- 50. सदस्यों की पंजी (रिजिस्टर).—िकसी पंजीकृत (रिजिस्टर्ड) सभा द्वारा सदस्यों या हिस्सों (शेयरें) की पंजी (रिजिस्टर) या सूची उनमें लिखे हुए निम्निलिखित विषयों में से किसी के लिये भी प्रत्यच माद्य (prima facie evidence) मानी जायेगी:—
 - (क) वह दिनांक जिसको उक्त पंजी (रिजिस्टर) या सूची में किसी व्यक्तिका नाम सदस्य के रूप में लिखा गया हो ;
 - (ख) वह दिनांक जिस ने उक्त कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रहता ।
- 51. सभात्रों की पुस्तकों की प्रवि ब्टयों का प्रमाण.— किसी पंजीकृत (रिजस्टर्ड) सभा की किसी पुस्तक में किसी भी प्रविष्ट विषय की, व्यवसाय-मध्य नियमित रूप से रखी गई कोई प्रतिलिपि, यदि नियमों द्वारा विहित रीति मैं प्रमाणित कर दी जाये तो वह किसी भी वाद या वैधानिक कार्यवाहियों में उक्त प्रविध्टि की विद्यमानता के प्रत्यन्न सान्य (prima facie evidence) के रूप में ग्रहण की जायेगी,

शौर प्रत्येक दशा में, उसमें ब्राभिलिखित विषयों, व्यवहारों ब्रौर लेखों के साच्य के रूप में उसी मात्रा तक तथा उसी दशा में मान्य होगी जहां तक ब्रौर जिस दशा में मूल प्रविध्ट स्वतः मान्य हो।

52. सदस्य की मृत्यु हो जाने पर स्वत्य का हस्तांतरण.—,।) किजी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, कोई पंजीकृत (रिजस्टर्ड) सभा मृत व्यक्ति का हिस्सा (शेयर) या स्वत्य (interest) इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अनुसार नामांकित व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरित कर सकेगी या यदि, इस प्रकार काई भी व्यक्ति नामांकित न हो तो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरित कर सकेगी जो समिति को मृत सबस्य का उत्तराधि गरी (heir) या वैधानिक प्रतिनिधि जान पड़े या स्थितिश्रनुसार उक्त नामांकित व्यक्ति, उत्तराधिकारी (heir) या वैधानिक प्रतिनिधि को उत्तनी राशि दे देगी जो नियमों या उपविधियों के प्रतुत्तर उक्त सदस्य के हिस्ते (शेयर) या स्वत्व के निश्चित मृत्य की प्रतिनिधाई हो:

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि --

- (त्र) त्रसीमित दायित्व वाली सभा की दशा में स्थितिनुत्रमार कोई भी नामांकित व्यक्ति, उत्तराधिकारी (heir) या वैधानिक प्रतिनिधि मृत सदस्य के हिस्से (शेयर) या स्वत्य (interest) के पृत्रोक्तानुंसार निश्चित मूल्य की सभा द्वारा चुकती किए जाने की मांग कर सकेगा;
- (आ) सीमित टायित्व वाली सभा की टशा में सभा मृत सदस्य का हिस्सा (शेयर) या स्वत्व, स्थितिश्रमुसार, ऐसे नामांक्ति व्यक्ति, उत्तराधिकारी (heir) या वैधानिक प्रतिनिधि के नाम
 पर हस्तान्तरित कर देंगी जो सभा की सदस्यता के लिये नियमों और उपविधियों
 के अनुसार योग्य हो, या मृत सदस्य की मृत्यु होने से एक मास के भीतर उसके
 प्रार्थनापत्र में निर्दृष्ट किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरित कर देगी जो उक्त
 रूप से योग्य हो।
- (2) कोई पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा ऐसा समस्त देय धन, जो उस सभा ने, स्थितिश्रनुसार, उक्त नामांकित व्यक्ति, उत्तराधिकारी (heir) या वैधानिक प्रतिनिधि को देना हो उसे चुका सकेगी।
- (3) इस धारा के उपबन्धानुसार पंजीकृत (रिजस्टर्ड) सभा द्वारा किए गए समस्त हस्तांतरण और की गई समस्त चुकितयां, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सभा पर की गई किसी मांग के विरुद्ध मान्य और प्रभावपृत्य होंगी।
- 53. पंजिक्त (रजिस्टर्ड) सभा के हिस्सों (शेयरों) श्रीर ऋगपत्रों से सम्बद्ध विले बें (instruments) को श्रानित्रार्थ रूप से पंजीकृत (रजिस्टर्ड) करवाने से विमुक्ति.— इंडियन र्गजस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 (Indian Registration Act, 1908) की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (b) श्रीर (c) का कोई भी उपकथ:—
 - (1) पंजीकृत (गंजिस्टर्ड) सभा के हिस्सों (शेयरों) से सम्बद्ध किसी विलेख (instrument) पर प्रयुक्त नहीं होगा, चाहे उक्त सभा की सकलसम्पत्ति (assets) पूर्णरूपेण या ग्रंशरूपेण श्रचल सम्पत्ति हो, या
 - (2) बढ़ां तक कि को शिराणपत्र किसी ऋगणपत्रधारी को ऐसे पंजीकृत विलेख (registered instrument) द्वारा प्रदत्त प्रतिभूमि का श्रिधिकारी बनाता है, जिस के द्वारा समा

ने अपनी सम्पूर्ण अन्तल समाति या उसका भाग या स्वत्व ऋग्णपत्रधारियों के लाभार्थ न्यास के न्यासधारियों के पास बन्धक या गिरवी रखा हो या अन्यथा हस्तांतरित किया हो, उसे छोड़ कर, ऐसे किसी भी ऋगणपत्र पर प्रयुक्त नहीं होगा जो किसी भी उक्त सभा ने जारी किया हो और अन्तल सम्पत्ति पर या उस में कोई अधिकार, आगम या स्वत्व, उत्पन्न, धोषित, अभिहस्तांकित, सीमित या समाप्त न करता हो, या

- (3) उक्त सभा द्वारा दिए गए किसी ऋग्गपत्र के किसी पृष्ठलेख या ऋग्गपत्र के किसी हस्तांतरम् पर प्रयुक्त नहीं होगा।
- 54. सहकारी सभात्रों को देय धन सदस्यों के वेतन में से काटना.—यदि सभा के ऐसे मदस्य ने, जो भारत संघ या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति की सेव। में हो सभा से कोई उधार (loan) लिये हुआ हो और किन्तों में उकत उधार वापस करने के लिये लिखित संविदा किया हुआ हो तथा उक्त किस्तें, उसके बेतन में से काट कर वस्त्ल करने का सभा को लिखित रूप में प्राधिकार दिया हो, तो वह व्यक्ति जो उक्त सेवा के सम्बन्ध में उक्त सदस्य को बेतन के रूप में देय कोई राशि बांटता है, सभा की मांग पर उक्त सदस्य को बेतन के रूप में दी जाने वाली राशि में से उक्त किन्त को राशि काट लेगा और इस प्रकार काटी गई राशि सभा के पास अविलम्ब जमा करा देगा।
- 55. राज्य शासन की श्रार्थिक सहायता देन की शिकत.—तत्काल प्रचलित किसी भी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, राज्य शासन नियमों के अधीन रहते हुए किसी भी सभा को उधार दें सकेगा, उसके हिस्से ले सकेगा या किसी अन्य रूप में उसे आर्थिक सहायता दें सकेगा।
 - 56. कुछ सभात्रों से उधार लेने वाले सद्स्यों की अनल सम्पत्ति पर प्रभार इस अधिनियम या तत्काल प्रचलित अन्य किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी —
 - (अ) यदि ऐसे किसी व्यक्ति के पास कोई भूमि हो जिसने उस सभा से उधार लेने के लिए प्राथिनापत्र दिया हो जिसका वह सदस्य हो, वह व्यंक्ति नियमों द्वारा विहित प्रपत्र में एक घोषणा करेगा। उक्त घोषणा में यह विवरण दिया जाएगा कि इस के द्वारा प्रार्थी पार्थनापत्र के अनुपालन में सभा द्वारा निश्चित अधिकतम राशि के अधीन रहते हुए सदस्य को दिए जाने वाले अगुण और उसके द्वारा अपेदित सभा द्वारा उसको भविष्य में दिए जाने वाले समस्त अग्रिम धन, यदि काई हो, की उक्त अगुण और अग्रिम धन की राशि के व्याज सहित चुकती करने के लिए घोषणा में विशिष्ट अपनी भूमि और फसलों पर एक भार उत्पन्न करता है;
 - (त्रा) हिमाचल प्रदेश सहकारी सभा श्रिधिनियम, 1955 के प्रचलन के दिनांक से पूर्व जिस किसी व्यक्ति ने ऐसी सभा से उधार लिया हो, जिसका वह सदस्य हां श्रीर उसके पास कोई भूमि या फसलें हों; खरड (त्रा) में निर्दिध्ट श्रिभिप्राय की तथा निर्दिध्ट प्रपत्र में यथासम्भवशीघ एक घोषणा करेगा। जब तक वह उक्त घोषणा नहीं करता तब तक उसे सभा के सदस्य के रूप में किसा भी श्रिधिकार का प्रयोग करने का हक नहीं होगा;
 - (इ) खएड (श्र) श्रीर (त्रा) के श्रघीन की गई घोषणा, सदस्य द्वारा उस समा की

स्हमित से जिसके पत्त् में उका प्रभार उत्पन्न किया गया हो, किसी भी समय संपरवर्तित की जा सकेगी;

- (ई) को से सदस्य खएड (अ) या (आ) के अधीन की गई घोषणा में विशिष्ट भूमि या फसलों
- (३) कार सा सदस्य खण्ड (अ) या (आ) पर अयान का नार नार के नार करेगा जब तक या उनके किसी भाग को तब तक अन्यार्पण (alienate) नहीं करेगा जब तक सदस्य द्वारा लिए गए उधार की समस्त राशि ब्याज शहित पृण् हिपेण नहीं चुकाई जाती:

परन्तु उक्त किसी भूमि पर खड़ी फसलों सभा की पूर्वानुमित लेकर स्रम्यार्पित की जा सकेंगी;

- (उ) खरड (ई) के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया कोई भी अन्यार्पण (alienation), शून्य होगा ;
 - (क) किसी उधार के कारण देयधन के लिए तथा उतनी राशि तक जो उसने देनी हो, खराड (ग्र) या (ग्रा) के ग्राधीन की गई घोषणा में ऋगा के सम्बन्ध में विशिष्ट भूमि पर भूगजस्य या भूराजस्य के रूप में वसूल किए जा सकने वाले किसी धन के सम्बन्ध में शासन को पूर्वता (prior claims) देने के पश्चात् सभा को प्रथम प्रभार प्राप्त होगा;
 - (দ) ऋधिकार ऋभिलेख में, खएड (ऋ) या (ऋा) के ऋधीन किसी घोषणा के ऋग्तर्गत किसी भूमि पर उत्पत्न प्रत्येक प्रभार का व्योश ऋग्तराविष्ट होगा।
 - (ऐ) सभा का ऐसा प्रत्येक सदस्य जो सभा से उधार लेता है, विहित प्रपत्र में इस ग्रामिप्राय की एक घोषणा निष्पादित करेगा कि जब तक ऋगा वापस नहीं विया जाना तब तक घोषणा में विशिष्ट भृमि पर उसके द्वारा उगाई गई फसलों के सम्बन्ध में सभा का प्रथम प्रभार होगा।
- 57. ऋगणत्रों के सूल छोर ट्याज का प्रतिरत्त्रण (guarantee) करने की राज्य रामन की शक्ति-—(1) इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी ऋगात्र या ऋगणत्रों की किसी श्रीणी या ऋगणत्र के कम या ऋगणत्रों के किसी विवाद के सम्बन्ध में राज्यसासन—
 - (क) मृत्तधन की ऐसी अधिकतम राशि या ब्याज के ऐसे मान (rate) और ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित हीं ऋगात्र के मृत्तधन तथा उसके ब्याज का प्रतिरत्तण (guarantee) करेगा, और
 - (ख) इन्डियन ट्रस्ट ऐक्ट, 1882 (Indian Trust Act, 1882) में किसी बात के होते हुए भी यह घोषणा कर सकेगा कि उक्त ऋणपत्र कथित ऐक्ट की धारा 20 में परिगणित (enumerated) प्रतिभृतियों में सम्मिलित समभे जारेंगे।
 - (2) राज्यशासन के स्पष्ट प्राधिकार के बिना उक्त ऋगापत्र जारी नहीं किए जाएं मे ।
- 58. प्रतिर्चित (guaranteed) ऋगापत्र जारी करना (1) जब ऋगापत्र जारी करके किसी सभा को ऋगा (loan) प्राप्त करने का धारा 57 की उपधारा (2) के उपबन्धाधीन ऋधिकार दिया गया हो भीर उन ऋगापत्रों का मूलधन और ब्याज उक्त एप से प्रतिरचित (guaranteed) हो तो

भ्रमुग्पत्रधारियों के प्रति सभा के आभार पूरे करने के सुनिश्चयन हेतु राज्यशासन न्यासधारी (trustee) का कार्य करने के लिए रजिस्ट्रार या किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करेगा।

- (2) न्यासधारी (trustee) की पूर्वातुमित लेकर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह आनोपित करे कोई सभा एक या अधिक नामों (denominations) के ऋग्गपत्र ऐसी अविध के लिए जो वह उन्तित सममें, सभा की सकलसम्पत्ति (assets) की प्रतिभूति पर जारी कर मकेगी जिसमें ऐसे बन्धक (mortgages) भी सम्मिलित होंगे जो स्वीकृति, असिहस्तांकन या हस्तांतरण द्वारा उसके पास हों।
- (3) उक्त ऋगापत्र निम्निलिखित एक या दोनों रुतों के ऋधीन २हते हुए जारी किए जा मकोंगे, ऋथीत्:—
 - (क) जारी करने के दिनांक से तीस वर्षों से अवधिक ऐसी अवधि नियत की जाएगी जिसके मध्य वे अमोचनीय होंगे;
 - (ख) सभा के लिए यह अधिकार रित्तित किया जाएगा कि वह जारी किए जा चुके कोई भी अध्यापत्र मोचन (redemption) के लिए नियत दिनांक से पूर्व किसी भी समय सम्बन्धित अध्यापत्रधारी को लिखित रूप में कम से कम तीन मास की सूचना देने के परचात् और अन्य किसी ऐसी रातों के अधीन रहते हुए भी जो न्यासधारी (trustee) अतरेपित करे, बायस मांग सकेगी।
- (4) ऐसी समस्त गिरा, जो किसी सभा द्वारा जारी किए गए ऋगापत्रों (जिन में इस ऋषिनियम का प्रारम्भ होने से पूर्व जारो किए गए ऋगापत्र भी किम्मिलित हैं) के सम्बन्ध में देय ही तथा जो किसी भी क्षमय चुकाने से शेष रह गई हो, बन्धकों पर देय समस्त राशि, ऐसी राशि जो उक्के अन्तर्गत चुका दी गई हो और सना या न्याक्ष्यारी के पास उक्त समय हो तथा सभा की तत्समय विद्यमान अन्य क्षणक्ष्मपत्ति (assets) जो हस्तांतरण्या अभिहरतांकन द्वारा सभा के कब्जे में हो, के मूल्य के योग स अधिक नहीं बढ़गी।
- (5) जब मोचन (redemption) के लिए नियत दिनांक से पूर्व सभा ने कोई ऋणपत्र मांगा हो तो सभा को न्यास्थारी (tristee) की पूर्वातुमित ले कर ऋगणपत्र को रद करने और चुकाए गए या अन्य प्रकार से पूर्व या समाप्त किए गए ऋगणत्र के स्थान पर कोई नया ऋगणपत्र जारी करने, या तो उसी ऋगणपत्र को फिर से जारो करने या उसके स्थान पर एक अन्य ऋगणपत्र जारी करके, ऋगणपत्र पुनः जारी करने की शक्ति होगी और इस प्रकार पुनः जारी किए गए ऋगणपत्र के आधार पर उक्त ऋगणपत्र के आधिकारों को वही अधिकार और पूर्वाधिकार यदि कोई हों, प्राप्त होंगे तथा सर्व था प्राप्त समभे जायेंगे मानो कि ऋगणपत्र पहले जारी नहीं किया गया था।
- 59. न्यासधारी (trustee) एकाकी निगम (corporation sole) होगा. धारा 58 के अधीन नियुक्त न्यासधारी (trustee) उन ऋणपत्रों के लिए जिन के सम्बन्ध में उसकी नियुक्ति हुई हो, न्यासधारी (trustee) के नाम से एक एकाकी निगम (corporation sole) होगा और

इस रुप में उसे शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होगा ख्रौर उस की एक सामान्य मुहर होगी तथा वह इस नाम में वाद चलाएगी ख्रौर इस नाम से उस पर बाद चलाया जायगा।

- 60. न्यासधारी (trustee) की शक्तियाँ तथा कर्तव्यः—(1) न्यासधारी (trustee) की शिक्तियां ग्रीर कर्तव्य इम अधिनियम के उपबन्धों द्वारा तथा सभा और न्यासधारी (trustee) के मध्य निष्पादित न्यास के विलेख (instrument) द्वारा प्रशास्तित होंगे।
- (2) उक्त विलेख (instrument) का प्रारूप ग्रारे ऐसा कोई संपरिवर्तन, जो उसके निष्पादन के पश्चात् पारस्परिक सहमित से उसके पन्न, उसके किसी निबन्ध (terms) में रखना चाहें, राज्यशासन की पूर्वानुमित के प्रतिबन्धाधीन होगा।
- 61. सकलसम्पत्ति (assets) पर ऋग्णपत्रधारियों का प्रभार धारा 58 की उपधान (2) के उपबन्धाधीन ऋगात्र जारी कर दिए ज ने पर, सभा की सकलकंपत्ति (assets) जिसमें एसं कोई बन्धक भी समिनित हैं, जो स्वीकृति, श्रमिहस्तांकन या हस्तांतरण द्वारा सभा के पास हों, न्यासधारो (trustee) में निहित होगी श्रौर ऋगात्रधारियों को उक्त समस्त सकलनम्पति (assets) जिस में वह राशि भी सम्मिनित है, जो उक्त बन्धकों के अन्तर्गत चुकाई गई हो श्रौर न्यासधारो (trustee) या सभा के पास शेष हो तथा सभा की सम्पत्ति पर चल प्रभार (floating charge) प्राप्त होगा।
- 62. सहवारी सभा की मांगों (claims) का विवरणापत्र मंगवाने की शिक्त. (1) जब ऐसी सभा का सदस्य, जिनके उद्देश्यों में अपने सदस्यों को उधार देना सम्मिलित हो, उधार लेने के लिए प्राथनापत्र दे या जब कोई व्यक्ति उकत सभा का सदस्य बनन के लिए प्रार्थनापत्र दे तो सभा प्रार्थनापत्र में नामांकित ऋणदाता या अनुवर्ती पारपुच्छा के पश्चात् निश्चित किसी भरणदाता को, विहित गीति से सूचना (notice) दे सकेगी तथा समस्त ऋणदाताओं के लिए एक सामान्य सूचना (general no ice) भी प्रकाशित कर सकेगी जिसमें उस से या उनसे यह अपेना की जाएगी कि वह या वे विहित प्रतत्र में तथा सूचना में निर्दिष्ट अविध में अपनी मांग का लिखित विवरण प्रदान करें।
- (-) जब ऐसी सभा का सदस्य, जिसके उद्देश्यों में अपने सदस्यों को उधार देना सम्मि-लित हो, सभा से अन्य किसी व्यक्ति से उधार लेने का विचार करे तो उक्त सदस्य निम्नलिखित विवरण देने हुए सभा को एक लिखित सूचना (notice) भेजेगाः—
 - (क) उक्त उधार लेने की अपनी इच्छा,
 - (ख) उधार की वह राशि, जो वह लेना चाहता हो, श्रौर
 - (ग) उधार लेने का चइ्रथ।
- 63. परिसीमा .- (1) इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 (Indian Limitation Act, 1908) के उपवन्धों में किसी बात के होते हुए भी ऐसी किसी राशि, जो किसी सभा के सदस्य न

उसे देनी हो तथा उसके ब्याज की वस्ली के लिए वाद चलाने की परिसीमावधि उस दिनांक से गिनी जायगी जिसको उक्त सदस्य की मृत्यु हुई हो या जब से वह सभा का सदस्य न रहा हो।

- (2) इंग्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 (Indian Limitation Act, 1908) के उपबन्ध इस श्रिधिनियम की धारा 87 के अधीन की गई कायवाहियों पर प्रयुक्त नहीं होंगे।
- 64. ऐसे व्यक्तियों पर जलकर (water-rate) लगाना, जो सदस्य न हों .—(1) जिस सभा का उद्देश्य श्रपने सदस्यों की कृष्य भूमि को सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करना हो वह सभा किसी भी सिंचनस्रोत (source of irrigation) से सिंचनयोग्य देत्र को सीमांकित करने के लिए किसीक्टर से विहित प्रपत्र में प्रार्थना कर सकेगी।
 - (2) उक्त चेत्र ''संचनयोग्य चेत्र'' कहलायगा।
- (3) कलेक्टर उक्त प्रार्थनापत्र मिलने पर, विहित रीति से सूचना देने के पश्चात् अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी द्वारा सींचनयोग्य च्लेत्र का एक मानचित्र और उस में सम्मिलित कृष्य भूमिं का एक विवरण, विहित रीति से तैयार करवाएगा, और उक्त मानचित्र, तथा विवरणपत्र विहित रीति से प्रकाशित किए जाएंगे।
- (4) यदि उक्त सभा के सदस्यों की ऐसी भूमि, जिस पर सदस्यों का कन्जा हो, सिंचनयोग्य चेत्र में सिमिलित कृष्य भूमि के साठ प्रतिशत से श्रिषक हो तो उक्त सभा इस सम्बन्ध में बनाए एए नियमों के श्रिषीन रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति पर जल कर लगा सकेगी, जो सभा का सदस्य न हो तथा जिस के पास उक्त चेत्र में ऐसी कृष्य भूमि हो जिसे उपधारा (1) में निर्दिश्ट सिचन सुविधाओं से लाभ पहुँचता है।
- (5) उक्त जल कर, ऐसी रीति से वसूलीयोग्य होगा जो किसी सभा को उसके सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों ब्रौर मृत सदस्यों द्वारा देय किसी राशि की वसूली के लिए इस ब्रिधिनियम में व्यवस्थित है।

The second of the second

- 65. ऐसे व्यक्तियों पर तटबन्द रक्षा कर (embankment protection rate) लगाना जो सदस्य न हों.—(1) जिस सभा का उद्देश्य श्रापने सदस्यों की भूमि को, तटबन्दी-रक्षा की सुविधाएं प्रदान करना हो वह सभा किसी भी तटबन्द द्वारा रिक्षत क्षेत्र का सीमांकन करने के लिए क्लेक्टर से विहित अवत्र में प्रार्थना कर सकेगी।
 - (2) उक्त चेत्र ''रिचत चेत्र'' कहलाएगा।
- (3) क्लेक्टर उक्त प्रार्थ नापत्र मिलने पर, विहित रीति से सूचना देने के पश्चात् अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी द्वारा रिच्चत चेत्र का एक मानचित्र आहेर उस में सम्मिलित भूमि का एक विवररा, विहित रीति से तै आर करवाएगा और उक्त मानचित्र तथा विवररा विहित रीति से प्रकाशित किए चाएंगे।
 - (4) यदि उक्त सभा के सदस्यों की ऐसी भूमि 'जिस पर सदस्यों का कब्जा हो रिज्ञत द्वेत्र में

मिमलित भूमि के साठ प्रतिशत से आधिक हो तो उक्त सभा उस सम्बन्ध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति पर तटबन्द रहा कर (embankment protection rate)लगा सकेगी, जो सभा का सदस्य न हो तथा जिस के पास उक्त होत्र में भूमि हो।

(5) उक्त तटबन्द रत्ता कर (embankment protection rate), ऐसी रीति में वस्लीयोग्य हो।ग जो सभा को उसके सदस्यों, भृतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों द्वारा देय विसी राशि की वस्ली के लिए इस ग्राधिनियम में व्यवस्थित है।

66. ऋाय कर से विमुक्त करने की शिक्त - केन्द्रीय शासन भारतीय राजपत्र में ऋषियूचना द्वारा किसी प'जीकृत (रिजस्टर्ड) सभा या प'जीकृत (रिजस्टर्ड) सभा ऋषे किसी श्रेणी की दशा में सभा के लाभ पर देय या ऐसे लाभांशों (dividends) या ऐसी ऋन्य राशियों पर देय ऋष्य कर विमुक्त कर्ण सकेगा, जो सभा के सदस्यों ने लाभ होने की दशा में प्राप्त की हों।

67. बुछ शुल्कों (dutics), कीसों इत्यादि से विमृक्ति.— (1) राज्य शासन किसी सभा या सभाग्रों की श्रोणी की दशा में सामान्य या विशेष आदेश द्वीरा तत्काल प्रचलित किसी विधि या उसके अन्तर्गात बनाए गये नियमों के अधीन देय किसी भी ऐसे कर (tax), उपकर (cess) या फीस (fees) को विमुक्त कर सकेगा जिस के सम्बन्ध में राज्य शासन उक्त कर (tax), उपकर (cess), या फीस (fees) विमुक्त करने के लिये सन्तम हो।

(2) किसी भी सभा या सभाश्रों की श्रेणी के सम्बन्ध में राज्यशासन राजपत्र में श्रिधसूचना देकर:--

(क) विसी सभा द्वारा या उस की ख्रोर से, या उसके पत्त में अथवा उसके पदाधिकारी द्वारा ने या उसके सदस्य की ख्रोर से निष्पादित तथा उक्त सभा के व्यवसाय से सम्बन्धित किसी विलेख (instrument) का मुद्रांक शुल्क (stamp duty) उन अप्रवस्था ख्रों में विमुक्त कर सकेगा जहां उक्त विमुक्ति के ख्रभाव में, स्थिति ख्रमुसार, सभा, उस का पदाधिकारी या सदस्य उक्त विलेख (instrument) के सम्बन्ध में किसी भी तत्काल प्रचलित विधि के ख्रधीन प्राप्य मुद्रांक शुल्क (stamp duty) चुकाने का उत्तरदायी हो:

्र (ख़) तत्काल प्रचलित किसी विधि के ऋधीन सभा द्वारा प्रतेखों के पंजीयन के लिए देय फीस

68. सदस्यता से निकाले हुए, सदस्यता त्यागने वाले या विकृत मस्तिष्क वाले सदस्य के हिस्सों (shares) या स्वत्य की व्यवस्थापना.—जब सभा का कोई सदस्य नियमों या उपविधियों के ऋतुसार निकाल दिया जाए, सदस्यता त्याग दे या जब किसी सदस्य का म स्तष्क विकृत हो जाए तो:—

(क) उस का हिस्सा या स्वत्व धारा 18 के उपबन्धों के ऋनुसार हस्तांतरगृहीता होने के योग्य किसी किसी किस के किस क्रिक्ट के क्रिक्ट के क्रिक्ट के इस्तांतरित किया जाएगा और नियमानुसार निश्चित उस का मूल्य उक्त क्रिक्ट के इस्त चे चुका दिया जाएगा या यदि उसका मस्तिष्क विकृत हो गया हो तो इंडियन क्रिक्ट को ऐक्ट, 1912-(Indian Lunacy Act, 1912) के अधीन उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति को चुका दिया जाएगा, या

्रिं (ख) क्रिंसीमित दायित्व बाली सभा की दशा में, यदि उपविधिवों में ऐसी कोई व्यवस्था हो, तो नियमानुसार निश्चित उसके हिस्से या स्वत्व का मूल्य उसे चुका दिया जगरू। सा यदि उसका मस्तिष्क विकृत हो तो इंडियन लुनेसी ऐक्ट, 1912 (Indian Lunacy Act, 1912) के यथीन उस की सम्पत्ति का प्रवन्ध करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति को चुका दिया जाएगा।

- 69. मृत, सदस्यता से निकाल हुए, सदस्यता त्यागने वाले या विकृत मिनिष्क वाले सदस्य को देय धन की व्यवस्थापना.—ऐसी समस्त राशियां जो नियमों के खनुसार किसी सभा द्वारा किसी सदस्य को देय अन्गणित हों, उक्त सदस्य के हिस्सों या न्स्वत्व (shares or interest) के सम्बन्ध में सभा को देय ख्रान्य चुकतियों को छोड़ कर, धारा 48 के उपबन्धों के खर्चीन रहते हुए:—
 - (क) मृत सदस्य की दशा में उस व्यक्ति को दे दी जाएंगी जिमे थारा 52 के उपवन्धानुसार हिस्से (shares) छौर र त्व हस्तांतरित हुए हों या उनका मूल्य चुकाया गया हो ;
 - (न्त्र) ऐर्प सदस्य की दशा में, जिसे सभा में निकाल दिया गया हो या जिस्ते सभा से त्यागपत्र दे दिया हों, उसे दे दी जाएंगी; श्रीर
 - (ग) ऐसे सदस्य की दुशा में, जिस का मस्तिष्क विकृत हो गया हो, इंडियन लुनेसी ऐक्ट, विक्रित हो गया हो, इंडियन लुनेसी ऐक्ट, विक्रित हो प्रिति के लिए नियुक्त किसी भी व्यक्ति को दे दी जाएगी।
- 70. सह कारी सभा को देय उचार प्रथम प्रभार होंगे. क ड ग्राफ खिवल प्रोसीजर, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) की घारा 60 और 61 में किसी बात के होते हुए भी किन्तु भूगजस्व या भूगजस्व के रूप में वस्तीयोग्य राशि या सार्वजितक मांग (public demand) के रूप में वस्तीयोग्य राशि के सम्बन्ध में राज्यशासन की किसी मांग कि ग्राचन रहते हुए श्रथवा लगान (rent) या लगान के रूप में वस्तीयोग्य किसी राशि के सम्बन्ध में मूमिपति की मांग (claim) के ग्रधीन रहते हुए, किसी सदस्य, भृतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा सहकारी सभा को देय उधार (loan)या बकाया राशि (debt or outstanding demand)
 - (क) यदि उक्त उधार (debt) या बकाया राशि बीज, लाद, अम सहायता (labour subsistence), पशु के लिए चारे अथवा कृष्-कम करने से आनुपंगिक (incidental) अन्य वस्तुओं के प्रदाय या उनकी चुकती करने के हेतु लिए हुए किसी उधार (loan) के सम्बन्ध में देश हो, ते उक्त सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की सम्पदा की फरलों या कृषि-उपज पर उस दिनांक से दो वर्ष के भीतर किसी भी समय प्रथम प्रभार होगी, जैंब उक्त प्रदाय या उधार (loan) की पहली किस्त वापस चुकाई जानी चाहिए थी;
 - (ल) यदि उकत उधार (debt) या बकाया साशि सिचन-सुविधास्रों (irrigation facilities) के प्रदाय या उनकी चुकती करने के हेतु लिए हुए किसी उधार (loan) के सम्बन्ध में देय हों, तो उकत सदस्य, मूलपूर्व सहस्य या मृत सदस्य की सम्पदा की फसलों या कृषि-उपज पर या उस मूभ की कृषि-उपज पर, जिसे उक्त रूप से सिचन सुविधाएं की गई हों, उस दिनांक से दो वर्ष के भीतर किसी भी समय प्रथम प्रभार होगी, जब उक्त प्रदाय या उधार (loan) की पहली किस्त वापस चुकाई जानी चाहिए थी;
 - (ग) यदि उक्त उधार (debt) या बकाया राशि, उपरोक्त रीति में और मात्रा तक, पशु, कृषि-उपज के संग्रहण के लिए गोदाम के प्रदाय या उनकी खरीद करने के हेतु लिए

हुए किसी उधार (loan) के सम्बन्ध में देय हो तो उक्त सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की सम्पदा की फसलों या कृषि-उपज पर तथा उक्त उधार (loan) से पूर्णरूपेण या ऋ शरूपेण खरीदे हुए या प्रदत्त पशु, कृषि-उपकरणों या गोदाम पर भी प्रथम प्रभार होगी;

- (घ) यदि उक्त उधार (debt) या बकाया राशि कच्चे माल (raw material), श्रीशोगिक उपकरणों, मशीनरी, वर्कशाप, गोदाम या व्यवसाय-स्थान (business premises) के प्रदाय या उनकी खरीद करने के हेतु लिए हुए किसी उधार (loan) के सम्बन्ध में देय हो तो उक्त सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा उक्त उधार (loan) से पूर्णारूपेण या अंशरूपेण प्रदत्त या खरीदे हुए कच्चे माल या अन्य वस्तुओं पर तथा उक्त उधार (loan) से पूर्णारूपेण या अंशरूपेण प्रदत्त या खरीदे हुये कच्चे माल या उपकरणों या मशीनरी द्वारा बबाई गई वस्तुओं पर भी प्रथम प्रभार होगी;
- (च) यदि उस्त उधार (debt) या बकाया राशि भूमि की खरीद या मोचन (redemption) के हेतु लिए हुए किसी उघार (loan) के सम्बन्ध में देय हो तो उक्त सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा उक्त उधार (loan) से खरीदी हुई या मोचित (redeemed) भूमि पर प्रथम प्रभार होगी; ऋौर
- (छ) यदि उक्त उधार (debt) या बकाया राशि किसी मकान या भवन या उन के किसी भाग की मरम्मत करने या उनकी खरीद करने या उक्त निर्माण के लिए सामग्री प्रदान करने के हेनु लिए हुए किसी उधार (loan) के सम्बन्ध में देय हो तो उक्त सदस्य, भृतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा उक्त उधार (lcan) या सामग्री से निर्मित या खरीदे हुए मकान या भवन पर प्रथम प्रभार होगी।

अध्याय 8 निरीच्च तथा लेखा परीच्चा

- 71. रजिस्ट्रार का लेखा-परीक्षण के लिए उत्तरदायी होना.— (1) प्रत्येक सहकारी सभा के लेखे की प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार श्रीर उस दिनांक तक जो विहित किया जाए रजिस्ट्रार द्वारा या उसके सामान्य या विशेष लिखित श्रादेश से इस हेतु प्राधिकृत किसी लेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षण किया जाएगा।
- (2) लेखा-परीच्या के सम्बन्ध में सहकारी सभा लेखा-परीच्या के लिए विश्ति फीस देगी, यदि कोई हो।
- 72. रजिस्ट्रार की लेखों को पूरा करवाने की शक्ति.—यदि लेखा-परीच्रण के समय सहकारी सभा के लेखे पूरे न हो-तो रिजस्ट्रार या लेखा-परीच्रक सभा के व्यय पर लेखों को पूरा करवा सकेगा।
- 73. लेखा परीचाग्र का प्रकार. (1) धारा 71 के श्राधीन लेखा-परीचाग्र के श्रान्तर्गत निम्नलिखित विषय होंगे -
 - (क) नवद बकाया श्रौर प्रतिभूतियों का सत्यापन (verification) ;

2

- (स्व) जमा कराने वाले व्यक्तियों (creditors) तथा ऋणदातात्रों के खाते में वकाया राशि का तथा सभा से उधार लेने वाले व्यक्तियों से प्राप्य राशि का सत्यापन ;
 - (ग) समयोत्तर ऋगों (overdue debts), यदि को हों, की जांच ;
 - (घ) सभा को सकलक्षम्पति श्रौर दायित्वों (assets and liabilities) का मूल्यांकन ;
 - (च) सभा के व्यवहारों, जिसमें धन सम्बन्धी व्यवहार समिनित हैं, की जांच ;
 - (छ) ऐसे प्रपन्न में जो विहित किया जाए, प्रवन्धक रूमिति द्वारा तैयार किए जाने वाले लेखा विवरण की जांच:
 - (ज) प्राप्त लामों का प्रमाणिकण ; श्रीर
 - (भः) श्रन्य ऐसा विषय जो विहित किया जाए।
- (2) इस प्रकार से परीचित लेखा-विवरण ऐसे संपरिवर्तन सहित, यदि कोई हो, जो रिजस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ने उसमें किया हो, अंतिम होगा और सहकारी सभा पर बाध्य होगा।
- 74. लेखा-परीक्षक का प्रतिदेदन.— लेखा-परीक्षक परीक्षित लेखा-विवरण सहित लेखा-परीक्षण का प्रतिवेदन (audit report), जिसमें निम्नलिखित विषयों के विवरण सम्मिलित होंगे, उस दिनांक तक सहकारी सभा तथा रिजस्ट्रार को भेजेगा जो विहित किया जाए:
 - (क) प्रत्येक ऐसा व्यवहार (transaction), जो उसे विधि या नियमों या उपविधियों के प्रतिकृत प्रतीत हो;
 - (स्त) प्रत्येक ऐसी राशि, जो लेखे में दिखाई जानी चा हए थी पर्नुत दिखाई न गई हो ;
 - (ग) किसी प्रकार की ऐसी कमी या हानि का परिसाद जिसके सम्बन्ध में यह प्रतीत हो कि वह स्त्रसावधानी या दुराचार के परिस्थामस्वरूप हुई है या जिसके सम्बन्ध में पुनः जांच करने की स्त्रावश्यकता प्रतीत हो ;
 - (घ) सभा की ऐसी धनराशि या सम्पत्ति, जिसके सम्बन्ध में यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति ने उसका दुरुपयोग किया है या उसे छलपूर्वक अपने पास रखा है;
 - (च) कोई भी सकलसम्पत्ति जो उसे ठीक प्रतीत न हो या संदिग्ध प्रतीत हो; स्त्रीर
 - (ন্তু) ऐसा अन्य कोई विषय, जो विहित किया जाए।
- 75. त्रुटियों का सुधार.— सहकारी सभा को रिजस्ट्रार, लेखा-परी त्रक द्वारा निकाली गई किन्हीं त्रुटियों या अनियमताओं को स्पष्ट करने का अवसर देगा और उसके पश्चात् सभा रिजस्ट्रार द्वारा निदेशित अवधि में तथा रीति से उकत त्रुटियों और अनियमताओं को ठीक करेगी और इस सम्बन्ध में वह जो कार्यवाही करे उसका प्रतिवेदन रिजस्ट्रार को देगी।
- 76. रजिस्ट्रार द्वारा निरीत्त् ग. रजिस्ट्रार समय समय पर किसी पंजीकृत (रजिस्टड) सभा का स्वयं निरीत्त् ग कर सकेगा, या इस हेतु अपने सामान्य या विशेष आदिश द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उक्त सभा का निरीत्त ग करवा सकेगा।

- 77. रजिस्ट्रार द्वारा परिष्टच्छा.—(1) रजिस्ट्रार स्वयं या इस हेतु लिखित रूप से उसके द्वीरा विधिपूर्वक प्राधिकृत व्यक्ति सभा के संविधानिक कार्यों (constitution working) और वित्तीय स्थिति की परिष्टच्छा कर सकेगा ।
 - (2) रजिस्ट्रार.--
 - (क) ऐसी सभा की मांग करने पर, जिसे इस हेतु बनाए गए नियमों द्वारा उक्त मांग करने का विधिपूर्वक प्राधिकार प्राप्त हो, उसके किसी एक सदस्य के सम्बन्ध में, यदि वह सदस्य कोई सभा हो,
 - (ख) सभा की समिति के बहुमत के प्रार्थनापत्र पर;
 - (ग) सभा के एक तिहाई सदस्यों के प्रार्थनापत्र पर,

ऐसी परिपृच्छा करेगा जो इस धारा की उपधारा (1) में ऋनुकल्पित है।

- (3) सभा के समस्त पदाधिकारी तथा सदस्य जिनके मामलों की जांच की गई हो, रजिस्ट्रार को या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की ऐसी सूचना देंगे, जो सभा के मामलों के सम्बन्ध में उनके कब्जे में हो श्रीर को रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ने मांगी हो।
- (4) इस धारा के अधीन की गई परिष्टच्छा का गरिस्साम उस सभा को भेजा जाएगा जिसके मामलों की जांच की जा चुकी हो।
- 78. निरीत्तरण या परिपृच्छा का व्यय रजिस्ट्रार पत्तों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अग्रैर लिखित आदेश द्वारा जिसमें वह आदेश देने के कारणों का चल्लेख करेगा धारा 79 के अधीन किए गए निरीत्त्रण या धारा 77 के अधीन की गई परिपृच्छा के व्यय का, या व्यय के ऐसे भाग का, जो वह उचित समस्ते, अभिभाजन सहकारी सभा, उसके सदस्यों या वित्त प्रबन्धक अधिकोष या अग्रुणदाताओं या, स्थितिअनुसार, उक्त निरीत्तरण या परिपृच्छा की प्रार्थना करने वाले अग्रुणदाता या अग्रुणदाता औं और सभा के पदाधिकारियों, भूतपूर्व पदाधिकारियों, सदस्यों श्रीर भूतपूर्व सदस्यों के मध्य कर सकेगा।
- (2) उपधारा (1) के ऋधीन दिए गए ऋदिश के विरुद्ध सभा से ऋन्य किसी व्यक्ति द्वारा की गई ऋपील का व्यय किसी भी सहकारी सभा की निधि में से वहन नहीं किया जाएगा।
- 79. ऋगाव्रस्त सहकारी सभा की पुस्तकों का निरीक्तगा.— (1) उपधारा (2) के उपबन्धा-धीन सहकारी सभा के ऋगादाता के प्रार्थनापत्र पर सभा की पुस्तकों का निरीक्तगा रिजिस्ट्रार द्वारा या इस हेतु उसके सामान्य या विशेष लिखित आदेश से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया उग्रगा।
 - (2) उक्त कोई भी निरीक्त ए नहीं किया जाएगा जब तक कि-
 - (क) सभा को सुनवाई का अवसर देने के बाद रिजस्ट्रार का समाधान न हो जाए कि कथित ऋग्य (debt) उस समय देय राशि हैं और ऋग्यदाता ने उसकी चुकती की मांग की है और उचित समय के अन्दर वह पूरी नहीं की गई है; और
 - (ख) ऋग्यदाता रिजस्ट्रार के पास निरीत्तगा के व्यय के लिए प्रतिभूति के रूप में रिजस्ट्रार द्वारा निदेशित शशि जमा न कर दे।

- (3) रजिस्ट्रार इस घारा के ब्राघीन किसी भी निरीच ए का परिगाम ऋग्यदाता, सभा ख्रौर ऐसे वित्त प्रकथक ऋधिकोष, यदि को हो, को मेजेगा जिसकी सदस्यता में वह सभा सदस्य हो।
- 80. ऐसी तुटियां जो परिष्टच्छा या निरीचाण से प्रकट हुई हों, र जिस्ट्रार द्वारा सभा के ध्यान में लाई जाएंगी.—(1) यदि धारा ?7 के छधीन की गई परिष्टच्छा या धारा 76 के अधीन किए गए निरीच्या से सभा के कारोबार में किसी प्रकार की तुटियां प्रकट होती हैं तो रिजर्ट्रार उक्त तुटियों को सभा के ध्यान में लाएगा और यदि सभा संचीय सभा (federal society) या वित्त प्रकट्छक संस्था (financing institution) को सदस्य हो तो संचीय सभा (federal society) या वित्त प्रक्षिकारी या संघीय सभा (federal society) या वित्त प्रक्षिकारी या संघीय सभा (federal society) या वित्त प्रक्षिक संस्था (financing institution) को भी निदेश देते हुए रिजस्ट्रार ब्रादेश में विशिष्ट ब्राविध में तुटियों को सुधारने के लिए ऐसी कार्यवाही करने का ब्रादेश देगा, जो उसमें विशिष्ट की जाए।
 - (2) रिजस्ट्रार द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश के विरुद्ध संघीय सभा (federal society) या वित्त प्रकथिक संस्था (financing institution) या सम्बद्ध सभा ऐसी अविधि में, जो आदेश में बुटियों को मुधारने के लिए विधिष्ट हो, उसमें विधिष्ट अविधि के भीतर अभील कर सकेगी।
 - (3) राज्यशासन ऋषील का निर्णाय करते हुए रिजस्ट्रार का ऋषिश शूर्य कर सकेगा, उसे उत्तर सकेगा, उसमें संपरिवर्तन कर सकेगा या इसकी पुष्टि कर सकेगा।
 - 81. रजिस्ट्रार का कर्तव्य भ्रष्ट प्रवर्तकों (deliquent promotors) के विरुद्ध ज्ञति निर्धारण करना.—(1) जहां धारा 71 के अधीन लेखा-परीच्चण करते समथ या धारा 77 के अधीन परिपृच्छा करते समय या धारा 76 के ऋधीन निरीक्त्गण करते समय या सभा का समापन करते समय यह प्रतीत हो कि ऐसे व्यक्ति ने, जिसने किसी सभा के संगटन या प्रकन्ध में भाग लिया हो या सभा के किसी भूतपूर्व श्रथवा वर्तमान सभापति, सचिव या उसकी प्रवन्धक समिति के सदस्य या पदाधिकारी ने सभा की किसी धनराशि या सम्पत्ति का दुरु तयोग किया है या उसे ऋपने पास रखा है या उसके लिए वह उत्तरदायी हो गया है या उसने उस का हिसाब देना है या अपकृति (misfeasance) का दोषी रहा है या सभा के साथ विश्वासघत करने का दोषी रहा है, लेखापरीवाग या परिपृच्छा या निरीवाग करने वाले पदाधिकारी, या विगणिक (liquidator) या किसी ऋगादाता, या अंरादाता (contributor) के प्रार्थनापत्र पर उक्त व्यक्तियों के स्नाचरण की जांच कर सकेगा श्रीर सम्बद्ध को श्रपनी सफाई प्रस्तुन करने का उचित श्रवसर देने के पश्चात् ग्रादेश द्वारा उससे यह श्रपेत्ना कर सकेगा कि वह क्रमश: धन या सम्पत्ति या उसके किसी भाग को ऐसे मान (rat) पर स्त्रागिएत ब्याज सहित, जो रजिस्ट्रार उचित समभे वापस चुकाए या उसकी पूर्ति करे या सभा की सकलसम्पत्ति (assets) मैं ऐसी राशि ऋंशदान के रूप में दे जो दुरुपयोग (mis-application), धन या सम्पत्ति ऋगने पास रखने, अपकृति (misfeasance) या विश्वासघात की च्रितपूर्ति के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार उचित समभः।
 - (2) यह धारा उस अवस्था में भी प्रयुक्त होगी जब कि अपराधी व्यक्ति कर्म के लिए दंड्य रूप से उत्तरदायी हो।

अध्याय

कृषि-सभाएं

- 82. प्रारम्भिक प्रक्रिया.—(1) कृषि की किसी योजना में श्रमिरुन्ति रखने वाले व्यक्ति एक कृषि-सभा का पंजीयन (रिजिस्ट्रेशन) करने के लिये रिजिस्ट्रार को प्रार्थनापत्र दे स्केंगे, यह प्राथनापत्र धाग 8 के उपबन्धों के श्रमुसार दिया जाएगा और इस में योजना से प्रभावित स्तेत्र विशिष्ट होगा । इसके साथ निम्नलिखित विवरण दिए जाएंगे:—
 - (क) उक्त योजना का विस्तृत वर्णन और उसके व्यय का ऋनुमान,
 - (ख) योजना में सम्मिलित की जाने वाली भूमियों के उन भूस्वामियों के नाम जिन्हों ने योजना बनाने में अपनी सहति (consent) दे दी हो, अर्ौर
 - (ग) ब्रन्य ऐसे व्योरे, जो नियमों द्वारा विहित हों।
- (2) प्रार्थनापत्र संलग्न पत्रों सहित उस ग्राम या उन ग्रामों में ग्रारे उस तहसील के मुख्यावास (headquarters) में प्राकाशित किया जाएगा, जिनकी सीमाओं में वे भूमियां स्थित हों जिन्हें थोजना में समाविष्ट करने का विचार हो।
- (3) उक्त सभान्त्रों के प्रयोजनार्थ राष्ट्रयशासन, रिजस्ट्रार और कृषि संचालक (डायरेक्टर ग्रौफ ऐग्रीकरूचर) को मिला कर एक पर्षद् (बोर्ड) बनाएगा। यह उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रार्थनापत्र पर विचार करेगी और उसका निश्चय करेगी। पर्षद् (बोर्ड) इस सम्बन्ध में निश्चयार्थ उत्पन्न विषयों के लिये एक परिपृच्छा ग्राधिकारी (enquiry officer, नियुक्त कर सकेगी ग्रौर उस से प्रतिवेदन (report) ले सकेगी। यदि इस अध्याय के उपबन्धों या तदर्थ बनाए गए नियमों के ग्राधीन किसी विषय के सम्बन्ध में पर्षद् (बोर्ड) के सदस्यों में मतभेद हो तो ऐसा विषय राज्यशासन को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- 83. पर्ष द् योजना में संपरिवर्तन करके या संपिध्वर्तन के बिना उसे स्वंकार कर सकेगी या स्वीकृति देने से इन्कार कर सकेगी—उक्त परिपृच्छा के उपरान्त और विहित रूप में पर्षद् (बोर्ड) कलेक्टर के परामर्श से, ऐसी परिपृच्छा करने के उपरान्त जो वह उचित समके, या तो योजना को संपरिवर्तन सहित या संपरिवर्तन के बिना स्वीकार कर सकेगी या स्वीकृति देने से इन्कार कर सकेगी।
- (2) यदि कोई अपील की गई हो तो उस पर दिये गए निर्ण्य के प्रतिबन्धाधीन, पर्धद् द्वारा स्वीकृत रूप में योजना राजपत्र में और अन्य ऐसी रीति से प्रकाशित की जाएगी जो विहित की जाए स्त्रीर उक्त प्रकाशन हो जाने पर वह अन्तिम हो जाएगी।
- 84. योजना का प्रभाव.—जिस दिन स्वीकृत रूप में घारा 83 के ऋघीन योजना प्रकाशित होती है उस दिन से वह प्रचलित हो जाएगी और उसमें समाविष्ट भूमियों के समस्त स्वामियों को चाहे वे कृषि-सभा के सदस्य हों या न हों, ऐसे ऋघिकार प्राप्त हो जायेंगे और वे ऐसे दायित्वों के ऋघीन हो जायेंगे जो योजना के ऋघीन उन्हें प्रदत्त या उन पर आरोपित हों।

The second second second

- 85. योजना प्रचित्तत करने की शांक्त.—उस दिन या उसके पश्चात् जब योजना प्रचित्तत होती है सम्बद्ध कृषि सभा विहित सम्बना (notice) देने के पश्चात् और योजना के उपबन्धों कं श्रमुसार ऐसे किसी भी कर्म को निष्पादित कर सकेगी जिसे योजना के अधीन निष्पादित करना किसी भी व्यक्ति का कर्तव्य हो। इस धाग के अधीन यदि सभा ने कोई व्यय वहन किया हो तो वह उस क्यक्ति से धारा 101 में विहित रीति से वसूल किया जाएगा, जिस ने व्यय न चुकाया हो।
- 86. योजना के व्यय में द्यंशदान.—(1) योजना ना व्ययपूर्णरूपेण या द्रांशरूपेण योजना में प्रभावित भूमि के प्रत्येक स्वाभी के द्र्यंशदान से पूरा किया जाएगा जिमका निश्चय सभा करेगी। इस मैं वह व्यक्ति भी सम्मिलित होगा, जिसने पर्षद् (बोर्ड) के निश्चय के द्यानुसार कृषि-सभा का सदस्य बनने से इंग्कार कर दिया हो।
 - (2) बोजना से प्रभावित भूमि का स्वामी उक्त भूमि के सम्बन्ध में ब्रारोप्य श्रंशदान की चुकती के लिये प्रथमरूपेण उत्तरदायी होगा।

अध्याय 10

विवादों का निश्चय

- 87. विवाद (dispute) रिजस्ट्रार को निर्दिष्ट किए जाएंगे.—समा के व्यवसाय (business) पर प्रमाव डालने या समा के विगणिक का कोई भी विवाद (dispute) सभा द्वारा या इस की प्रवन्थक समिति द्वारा सभा के वेतन पर काम करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध की गई अनुशासक कार्य वाही से सम्बन्धित विवाद से अन्य रिजस्ट्रार को निर्दिष्ट किया जाएगा यदि उसके पत्त में निम्नलिखित में से हीं, अर्थात्—
 - (क) सभा, उसकी प्रबन्धक-समिति (managing committee) सभा का भूतपूर्व या विद्यमान पदाधिकारी, श्रमिकर्ता (agent) या कर्मचारी या विगणिक (liquidator), या
 - (ख) सभा के सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा भांग करने वाला सदस्य, भूतपर्व सदस्य या वर्तभान सदस्य, या
 - (ग) सभा के सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य का प्रतिभू चाहे वह प्रतिभू (surety) सभा का सदस्य हो या न हो; या
 - (घ) ऋन्य कोई सभा या उक्त सभा का विगिष्कि (liquidator) !
 - 88. विवादों का निश्चयः (1) धारा 87 के श्रधीन कोई निर्दिष्ट विषय प्राप्त होने पर नियमों के प्रतिबन्धाधीन रिजस्ट्रार
 - (क) स्वयं विवाद का निर्णय करेगा, या
 - (ख) रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त एक या अधिक विवाचकों को निर्णाध निर्दिध्ट करेगा।

- (2) नियमों के प्रतिबन्धाधीन रिजस्ट्रार उपधारा (1) के ऋषीन निर्दिष्ट किसी भी निर्देशन (reference) को वापस ले रुकेगा श्लीर इसका निश्चय उक्त नियमों में व्यवस्थित रीति से स्वयं कर सकेगा।
- 89. कुछ परिनिर्ण्यों (awards) की शक्ति और प्रभाव .— जहां विवाद में सांपार्श्विक प्रतिभृति (collateral security) के रूप में गिरवी रखी हुई (pledged) सम्पति सन्निहित हो, उस दशा में विवाद का निश्चय करने वाला व्यक्ति एक परिनिर्ण्य दे सकेगा (may issue an award), जिस की शक्ति और प्रभाव ऐसे दीवानी न्यायालय की बन्धक सम्बन्धी अन्तिम डिकी (final mortgage decree) के समान होगा, जो ऐसी डिकी देने में चित्रा- धिकार सम्पन्न हो।
- 90. पिरिनिर्ण्य (award) से पूर्व कुर्की (attachment).— जहां कोई विवाद धारा 87 के अधीन रिजस्ट्रार को या धारा 88 के खण्ड (ख) के अधीन विवास्त्रनार्थ (for arbitration) निर्दिष्ट हुआ हो उस दशा में, स्थितिअनुसार, रिजस्ट्रार या उसके द्वारा नामांग्तित व्यक्ति (nominees) या विवास्त्रकगण, यदि परिपृच्छा करने पर या अन्यथा उनका यह समाधान हो जाए कि ऐसे विवासन (arbitration) का कोई पत्त किसी सम्भाव्य परिनिर्ण्य (award) के निष्पादन में देरी करने या बाधा डालने के अभिप्राय से
 - (क) यदि अपनी समस्त सम्पत्ति या उस का कोई भाग बेचने वाला हो, या
 - (ख) श्रपनी समस्त सम्पत्ति या उसका कोई भाग रिजस्ट्रार के श्रिधकार-च्लेत्र से हटाने वाला हो,
 - तो वह, जब तक पर्याप्त प्रतिभूति (security) न दे दी जाए, उक्त सम्पत्ति की सप्रतिबन्ध कुकीं (conditional attachment) का निदेश दे सकेगा और ऐसी कुकीं (attachment) उसी प्रकार प्रभावी होगी मानो वह सद्धम दीवानी न्यायालय द्वारा की गई हो।
- 91. श्रादेश का श्रन्तिम होना.—धारा 87 या 88 के श्रधीन विवासकों के परिनिर्णाय या रिजस्ट्रार या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति के निश्चय पर किसी भी दीवानी या माल न्यायालय में आपत्ति नहीं उठाई जा सकेगी।
- 92. सम्पत्ति क ऐसे बैयक्तिक हस्तांतरण, जो प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात् किए गए हों सभा के विरुद्ध शून्य होंगे धारों 100 के अधीन, यथास्थिति, रजिस्ट्रार या विगणिक (liquidator) का प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात सम्पत्ति का इस्तांतरण या सम्पत्ति-अर्थण (delivery of property) या उस पर किया गया या व्युतपन्न भाररोध या प्रभार उस सभा के विरुद्ध अभिश्रत्य (null and void) होगा, जिसके प्रार्थ नापत्र पर उक्त प्रमाणपत्र जारी हुआ हो।
- 93. ऐसी सम्पित का हस्तांतरण, जो वेची न जा सके —(1) जब धारा 100 के अधीन निष्पादित किए जाने वाले किसी आ्रोदेश के निष्पादन में खरीदारों के अभाव में सम्पित वेचीन जा सकती हो तो यदि उक्त सम्पित वाकीदार के कब्जे में हो या उसकी श्लोर से किसी व्यक्ति के कब्जे में हो या धारा 100 या 101 के अधीन रिजस्ट्रार या विगणिक (liquidator)

का प्रमाग्रपत्र जारो हाने के पश्चात् बाकीटार द्वारा नियत किसी आगम (title) के अधीन मांग करने वाले व्यक्ति के कब्जे में हो तो त्यायात्त्रय या, स्थितिअनुपार, क्लेकटर रिजस्ट्रार की पुर्वानुमित में यह निदेश दे सकेगा कि उक्त सम्पत्ति या उसका कोई भाग उस सभा को हस्तांतरित कर दिया जाए जिस ने उपरोक्त आदेश के निष्पादन की प्रार्थना की हो और यह निदेश दे सकेगा कि उक्त सम्पत्ति या भाग बिहित रीति से सभा को अधित कर दिया जाए।

- (2) ऐसे नियमों के ऋषीन रहते हुए जो इस निर्मित बनाए जाएं तथा ऐसे किन्हीं ऋषिकारों, भाररोधों, प्रभारों या समन्याः को ऋषीन रहते हुए जो किसी अन्य व्यक्ति के पन्न में वैध रूप में विद्यमान हों, उक्त सम्पत्ति या उसका भाग ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन उक्त सभा द्वारा अपने पास रखा जाएगा जो न्यायालय या, स्थितिअनुसार, कलेक्टर तथा उक्त सभा के मध्य स्वीकार हुए हों।
- 94. सभा और उसके ऋणदाताओं (creditors) को आपस में सममीता करने की स्वीकृति देने के लिए रिजस्ट्रार की शिक्ति.—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी सभा और उसके ऋणदाता (creditor) या ऋणदाताओं (creditors) या ऋणदाताओं की श्रेणी (class of creditors) के मध्य कोई सममीता या व्यवस्था (arrangement) प्रस्तावित हो, उस दशा में सभा या किसी ऋणदाता (creditor) या उस सभा की दशा में, जिसके सम्बन्ध में उसके समापन (winding up) का आदेश दिया गया हो, विगणिक (liquidator) द्वारा विहित रीति से प्रार्थनापत्र दिए जाने पर रिजस्ट्रार, स्थितिअनुसार, ऋणदाताओं (creditors) या ऋणदाताओं की श्रेणी (class of creditors) की बैटक विहित रीति से बुलाने, करने और विहित रीति से बैटक के संचालन का आदेश दे सकेगा।
- (2) यदि सभा द्वारा ऋणदाताओं अथवा ऋणदाताओं की श्रेणी को देय उधार (debts) के तीन चौथाई की मांग का प्रतिनिधित्व करने वाले ऋणदाताओं अथवा, स्थितिअनुसार, ऋणदाताओं की श्रेणी की, या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रतिपुरुष (proxy) द्वारा बैठक में उपस्थित बहुमंख्या किसी समभौते या व्यवस्था को स्वीकार कर ले तो वह समभौता या व्यवस्था यदि रिजस्ट्रार उसे स्वीकार (sanction) करे, विहित रीति से प्रकाशित होने के पश्चात समस्त ऋणदाताओं या, स्थिति-अनुसार, ऋणदाताओं की श्रेणी पर तथा सभा पर भी वाध्य होगा, या उस सभा की दशा में, जिसके सम्बन्ध में समापन का आदेश (order of winding up) दिया जा चुका हो विगिणिक और उन समस्त व्यक्तियों पर बाध्य होगा जिनसे विगणिक द्वारा धारा 105 के अधीन सभा की सकलसम्पत्ति में अपना अंश देने की अपेना की गई हो या की जाए।

अध्याय 11

दायित्वों को पूरा करवाना तथा वसूलियां प्रवृत्त करना

95. प्रलेखों इत्यादि की सहज लभ्यता.—रिजस्ट्रार तथा किन्हीं भी विहित आयंत्रणों के प्रांत-बन्धाधोन लेखा-परीक्ष (श्रीडिटर), विवाचक (arbitrator) या निरीक्ण अथवा परिपृञ्छा करने वाले धन्य व्यक्ति को हर उचित समय में सभा को या सभा के संरक्षणधीन पुस्तकों, लेखे, धलेख, धांतभूतियां, नकटी तथा अन्य सम्पत्ति अवाध रूप से सहजलभ्य होंगी।

- 96 उपस्थिति बाध्य करने की श्रांकनः इस श्रिधिनयन में जहां कहीं भी यह व्यवस्था हा कि रिजस्ट्रार या रिजस्ट्रार के सामान्य श्रिथवा विशेष लिखित श्रादेश द्वारा इस हेतु विधिपूर्वक प्राधिकृत त्यांक्त धारा 77 के श्रिधीन पिरिपृच्छा करेगा या धारा 76 के श्रिधीन निरोत्त्रण करेगा या सभा का समापन करेगा या विवाचन करेगा उस श्रावस्था में रिजस्ट्रर या, स्थितिश्रानुसार, प्राधिकृत व्यक्ति उन्हीं उपायों द्वारा श्रीर जहां तक हो सके उसी रिति से, जो दीवानी न्यायालयों के लिए सिविल प्रोसीजर कोड, 1908 में व्यवस्थित हैं, गवाहों को तथा साथ हो साथ स्वत्व रखने वाले पत्तों या उन में से किसी को बुलाने श्रीर उनकी उपस्थिति बाध्य करने या उन्हें साह्य देने के लिए वाध्य करने श्रीर प्रलेखों, का प्रस्तुतिकरण बाध्य करने के लिए शिक्तिसम्पन्न होगा।
- 97. देय राशियां चुकाने का निदेश देने की शक्ति. —अध्याय 10 में किसी बात के होते हुए भी रिजस्ट्रार या कोई अन्य विहित व्यक्ति स्वयं या सभा अधवा वित्त प्रवन्धक अधिकोष की लिखित मांग पर उतित परिपृच्छा करने के पश्चात् बाकीटार सदस्य (defaulting.member) द्वारा देय उधार (loan) की वस्ली के लिए एक परिनिर्ण्य दे सकेगा, जिस में वह उक्त सदस्य को ऐसी राशि चुकाने का निदेश दे सकेगा, जो उस से प्राप्य पाई गई हो।
- 98. प्रभार तथा श्रांतिरिक्त प्रभार (charge and surcharge). (1) जहां धारा 71 के श्रंधीन लेखा-परीक्षण करने पर या धारा 76 या धारा 79 के श्रंधीन निरीक्षण करने पर या धारा 77 के श्रंधीन परिष्टच्छा करने पर ऐसे प्रतिवेदन पर जो सभा का समापन करते समय दिया जाय, रिजस्ट्रार को यह प्रतीत हो कि किसी भूतपूर्व पटाधिकारी ने इस श्रंधिनियम का प्रारम्भ होने के पश्चात् श्रोर, स्थितिश्रनुसार, उक्त लेखा-परीक्ण, निरीक्ण, परिष्टच्छा या प्रतिवेदन के दिनांक से पूर्व चार वर्ष की श्रविध में—
 - (क) इस अधिनियम के उपबन्धों के या नियमों के या उपविधियों के विरुद्ध जानवूरसकर कोई चुकती की है या प्राधिकृत की है,
 - (ख) किसी विहित विषय के सम्बन्ध में उसके दंडनीय प्रमाद से सभा को हानि हुई है या उसे घाटा हुआ है, या
 - (ग) ऐसी याश जिसका लेखा रखा जाना चाहिए था, लेखे में नहीं लिखी है, या
 - (घ) सभा की किसी सम्पत्ति का दुरुपयोग किया है या खलपूर्वक वह अपने पास रखी है, तो विकास की परिष्टंच्छा कर सकेगा।
- (2) उक्त परिषृच्छा करने के उपरान्त, उस पदाधिकारी को सुनवाई का अवसर देकर और इस अधिनियम या नियम या उपिनियमों के उपबन्धों के विरुद्ध की गई जुकती की दशा में, इस प्रकार जुकाई गई गीश प्राप्तिकर्ता से वसूल करने और उसे सभा की निधि में जमा कराने का एक अवसर उक्त पदाधिकारी को देकर रिजस्ट्रार नियमों के प्रात्तवन्धाधीन एक लिखित आदेश द्वारा उक्त पदाधिकारी से यह अपेला कर सकेगा कि वह सभा की सकलसम्पत्त में उक्त जुकती या शानि या चाटे की चित्तपूर्ति के रूप में, ऐसी राशि या ऐसी सम्पत्ति जो रिजस्ट्रार उचित समस्ते जमा करा दे या पूर्वकत वापस कर दे और ऐसी राशि जुकाए, जो रिजन्स्ट्रार इस धारा के अर्धान कार्यवाहियों का ज्यय पूरा करने के लिए नियत करें।

- (3) इस बात के हाते हुए भी यह धारा प्रवर्तनीय होगी कि उक्त पहाधिकारियों द्वारा अपने कर्म या अपनी भूल से इस अधिनियम या तत्काल प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन अपराक्षात्मक दायित्व वहन किया गया है।
- 99. रेजिस्ट्रार की दायित्व पूरा करवाने की शक्ति—इस श्रिधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी सभा से इस श्रिविनियम, नियमों या उपविधियों के श्रिधीन कोई कार्यवाही करने की श्रिपेत्ता की गई हो श्रीर वह न की गई हो तो—
 - (क) इस ऋधिनियम, नियमों या उपितिधियों में व्यवस्थित ऋवधि में, या
 - (ग) जहां कोई अविध व्यवस्थित न हो उस दशा में जैसी कार्यवाही हो आरे जितनी कार्यव ही करनी हो उस का ध्यान रखते हुए, जो अविध रिजस्ट्रार लिखित सुचना (नोटिस) द्वारा नियत करे उस अविध में, रिजस्ट्रार सभा के उस अधिकारी को बुलवा सकेगा, जिये वह विहित मिद्धांतों के अनुसार अपने निवेशों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी समके, और मुनवाई का उचित अवसर देने के पश्च त् उक्त पदाधिकारी से यह अपेचा कर सकेगा कि वह प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जब तक कि रिजस्ट्रार के आदिशों का पालन नहीं हो जाता पचीस रुपये से अन्धिक ऐसी राशि, जो रिजस्ट्रार उचित समके, सभा की सकलसम्पनि में दे।
 - 100. धन कैसे वम्मूल किया जायगा.—धारा 105 के अधीन विगणिक (liquidator) या धारा 81 की उपधारा (1) के अधीन रिजस्ट्रार या धारा 88 के खरड (ख) या धारा 87 के अधीन रिजस्ट्रार या उस के द्वारा नामाकित व्यक्तियों, और विवासकों को निर्दिष्ट विवाद के सम्बन्ध में उस का या उन का आदेश या धारा 113 के अधीन की गई अपील पर दिया गया प्रत्येक आदेश, धारा 114 के अधीन पुनराष्ट्रित में दिया गया प्रत्येक आदेश और धारा 113 के अधीन दिए गए आदेश के विकद्ध की गई अपील पर या राज्यशासन का प्रत्येक आदेश, यदि रिजस्ट्रार या विगणिक द्वारा हस्तास्तरित प्रमाणपत्र पर कार्यान्वत न किया जाए तो वह दीवानी न्यायालय की डिकी समभा जायगा और धारा 101 में व्यवस्थित रीति से निष्पादित किया जायगा।
 - 102. प्राप्य राशियों की वसूली.—इस ऋघिनियम के अधीन किसी निश्चय या परिनिर्शाय के अबुसार राज्य शासन या किसी सभा को देथ राशि प्रथम अनुसूची में व्यवस्थिति रीति से प्राप्य होगी:

परन्तु प्रतिवन्ध यह है कि, कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 (Code of Civil Procedure 1908) में या तत्काल प्रचिलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 54 के ऋधीन लिया हुआ उधार या उस की किस्त न चुकाने के सम्बन्ध में धारा 88 और धारा 97 के ऋधीन दिए गए किसी परिनिर्ण्य के अनुसार देय कोई भी राशि—

- (क) यदि सदस्य का वेतन तीस रुपये प्रतिमास से ऋधिक हो तो उतनी किस्तों तक, जो न चुकाई गई हों, उस का वेतन या उस वेतन में से तीस रुपये निकाल कर, जो शेष रहें, उसका ऋप्राधा भाग, इन में से जो भी कम हों, उसे कुर्क करके, तथा
- (ख) यदि सदस्य का वेतन तीस ६१ये प्रतिमास से अधिक न हो तो उतनी किस्तों तक, जो न

चुकाई गई हीं, उस वेतन को या वेतन में से प्रति रूपया एक श्राना, इन में से जो भी कम हो, कुक करके।

- 102. कुछ त्रुटियों के आधार पर सभाओं के कार्य अमान्य नहीं होगे.—(1) सभा या प्रबन्धक-समिति या किसी पदाधिकारी या विगिणिक द्वारा सभा के व्यवसाय के अनुनार सद्माव से किया गया कोई भी कार्य केवल इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि सभा के संगठन या प्रबन्धक समिति की रचना या पदाधिकारी या विगणिक की नियुक्ति या चुनाव में कालांतर में कोई त्रुटि पाई गई है या इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि उक्त पदाधिकारी या विगणिक नियुक्ति के अयोग्य था।
- (2) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा सद्भाव से किया गया कोई भी कार्य केवल्र इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि उस की नियुक्ति इस अधिनियम द्वारा या इस के अधीन कालांतर में दिए गए किसी आदेश से रह कर दी गई है।
- (3) इस विषय का निश्चय रिजस्ट्रार करेगा आयाकि कोई कार्य सभा के व्यवसाय के अनुपालन में सद्भावना से किया गया था या नहीं।

अध्याय 12

सभा का समापन (winding up) ऋौर विघटन (dissolution)

- 103. सहकारी सभा के समापन के लिए आदेश. (1) रिजस्ट्रार लिखित आदेश द्वारा विव निदेश दे सकेगा और यदि इस सम्बन्ध में नियमों द्वारा ऐसा विहित हो तो यह निदेश देगा कि सहकारी सभा का समापन किया जाएगा यदि निम्नलिखित अवस्थाओं में उसकी यह राय हो कि सभा का समापन कर दिया जाना चाहिए—
 - (क) घारा 76 या 79 के श्राधीन निरीक्षण करने या धारा 77 के श्राधीन परिपृच्छा करने के पश्चात्, या
 - (ख) इस हेतु बुलाई गई विशेष सामान्य बैठक में उपस्थित सभा के तीन चौथाई सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार प्रार्थनापत्र देने पर, या
 - (ग) निम्निलिखित सभात्रों की दशा में स्वेच्छापूर्वक—
 - (अ) जिस सभा ने कार्य करना आरम्भ न किया हो, या
 - (त्रा) जिस सभा ने कार्य करना बन्द कर दिया हो , या
 - (इ) जिस सभा के हिस्सों की पूंजी या सदस्यों की जमा पूंजी पांच सौ रुपए से श्राधिक न हो, या
 - (ई) जिस सभा ने इस ऋधिनियम या नियमों या उपविधियों में पंजीयन के लिए व्यवस्थित किसी प्रतिबन्ध का पालन करना बन्द कर दिया हो।
 - (2) उक्त आदेश की एक प्रतिलिपि विहित रीति से सभा और ऐसे विर्त प्रबन्धक अधिकोष, यदि सोई हो, को भेजी जाएगी जिस की सदस्यता में वह सभा सदस्य हो ।

(3) ऋादेश--

- (क) जहां धारा 113 के ऋधीन कोई ऋपील न की गई तो ऋपील करने के लिए ऋनुमत श्रूत्रिध समाप्त हो जाने के पश्चात् प्रभावी होगा , या
- (ल) जहां ऋषील की गई हो उस ऋवस्था में ऋषील प्राधिकारी (appellate authority) द्वारा श्रपील ऋस्वीकार कर दिए जाने पर प्रभावी होगा ।
- 104. विगिश्चिक (liquidator) की नियुक्ति जब धारा 103 के अधीन किसी सभा के ममापन (winding up) का आदेश दिया जा चुका हो, तो रिजस्ट्रार नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को सभा का विगिश्चिक नियुक्त कर सकेगा और उक्त व्यक्ति को पदच्युत कर सकेगा और उसके स्थान पर अन्ये व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा।
- 105. विग एक (liquidator) की शक्तियां. (1) जिस दिनांक से सहकारी सभा के समापन का त्रादेश प्रभावी होता है उसके सम्बन्ध में धारा 103 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 104 के त्राधीन नियुक्त विगणिक (liquidator) त्रापनी नियुक्त के दिनांक से सभा की समस्त सकलसम्पत्ति, सम्पत्ति, सामान (effects) त्रौर कार्यवाहीयोग्य मांगें (actionable claims) या ऐसी समस्त सकलसम्पत्ति, सम्पत्ति, सामान त्रौर कार्यवाहीयोग्य मांगें (actionable claims), जिन की सभा हकदार हो, त्रौर सभा के व्यवसाय से सम्बन्धित समस्त पुस्तकें, त्रभिलेख त्रौर त्रान्य प्रलेख तरन्त त्रापने कब्जे में लेने के लिए शक्तिसम्पन्न होगा।
- (2) जिस दिनांक को सभा का समापन करने का आदेश प्रमावी होता है, उस दिनांक से विगिशिक, नियमों तथा रिजिस्ट्रार के सामान्य (general) निदेश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जहां तक ऐसा करना सभा के समापन के लिए आवश्यक हो, सभा की ओर से उसका व्यवसाय जारी रखने और उक्त समापन के लिए समस्त आवश्यक कार्य करने और समस्त प्रलेखों का निष्पादन करने के प्रयोजनार्थ शक्तिसम्पन्न होगा, और विशेषतया निम्नलिखित शिक्तियों में से ऐसी शिक्तियां प्रयोग करेगा, जो रिजिस्ट्रार समय समय पर निदेशित करे, अर्थात
 - (क) बाद श्रीर श्रन्य वैधानिक कार्यवाहियां चलाना श्रीर उन से प्रतिरत्ता करना;
 - (ख) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सममौता या व्यवस्था करना, जिसके ब्रौर सभा के मध्य कोई विवाद हो, ब्रौर उक्त किसी भी विवाद को विवापन हेतु निर्दिष्ट करना;
 - (ग) सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की सम्पदा द्वारा, उसके द्वारा नामांकित व्यक्तियों, उसके उत्तराधिकारियों या वैधानिक प्रतिनिधियों द्वारा सभा को देथ ऋग् का निश्चय करना;
 - (घ) विगरान के ब्यय की गराना करना और यह निश्चय करना कि वे किस ब्यक्ति द्वारा और किस श्रानुपात से पूरे किये जाएंगे;
 - (च) समा के सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों या मृत सदस्यों की सम्पदात्रों द्वारा, उनके द्वारा नामांकित
 व्यक्तियों, उनके उत्तराधिकारियों, बैधानिक प्रतिनिधियों या भूतपूर्व या वर्तमान पदाधिकारियों

द्व रा सभा की सकलसम्पति में समय समय पर दिए जाने वाले श्रांशदानीं का निश्चय करना, जिस में खरड (ग) और (घ) में वर्णित विषय भी सम्मिलित होंगे;

- (छ) सभा के विरुद्ध की गई समस्त मांगों (claims) की जांच करना (investigate) और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुऐ मांगकर्तीओं की पूर्वता के प्रश्न का निर्णय करना;
- (ज) सभा के विरुद्ध की गई मांगों (जिस में उसके समापन के ब्रादेश के दिनांक तक का ध्याज समिमलित होगा) की पूर्व ता के ब्रानुसार सभा की सकलसम्पत्ति की चभता के भीतर उन की सम्पूर्ण या ब्रानुपातिक (rateably) चुकती करना;
- (भ) ऐसे निदेश देना, जो उसे सभा की सकलक्षमपति (assets) की प्राप्ति, संग्रह श्रौर वितरण के लिए श्रावश्यक प्रतीत हो; श्रौर
- (त) सभा के सदस्यों का परामर्श होने के पश्चात ऐसे ऋतिरेक, यदि कोई हो, की व्यवस्थापना करना, जो सभा के विरुद्ध की गई मांगों की चुकती करने के पश्चात शोष हो।
- 106. विगणिक (liquidator) द्वारा निर्धारित अ'शदानों की पूर्व ता.— प्रोविंशियल इन्सौलवेन्सी ऐक्ट, 1920 (Provincial Insolvency Act, 1920) में किसी बात के होते हुए भी, शोधानमता की कार्यवाहियों में पूर्वता के कम में विगणिक (liquidator) द्वारा निर्धारित अ'शदान शासन या किसी भी स्थानीय प्राधिकारी को देय उधार से दूसरे स्थान पर होगा।
- 107. विगिष्णिक पुस्तकों को जमा करेगा श्रीर श्रान्तिम प्रतिवेदन (final report) देगा.—जब समा के कार्यों का समापन कर दिया गया हो तो विगिष्णिक विहित रीति से सभा के श्रामिलेख जमा करेगा और रजिस्ट्रार को एक प्रतिवेदन देगा।
- 108. सहकारी सभा के समापन के या पंजीयन के आदेश की रह करने का रिजिस्ट्रार की शांकि.—(1) जहां रिजिस्ट्रार की यह राय हो कि कोई सभा जारी रहनी चाहिए तो वह उसके समापन का आदेश रह कर सकेगा।
- (2) अन्य किसी भी दशा में रिजस्ट्रार विगणिक (liquidator) के प्रतिवेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् सभा के पंजीयन को रह करने का आदेश देगा।
- 109. समापन श्रीर विघटन से सम्बद्ध विपयों में वाद चलाने पर रुकावट.—जहां तक इस श्राधिनियम में स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई हो, उस को छोड़ कर, कोई भी दीवानी न्यायालय इस श्रिधिनियम के श्रिधीन किसी सभा के समापन या विघटन से सम्बन्धित किसी भी विषय का संज्ञान (cognizance) नहीं करेगा श्रीर जब समापन का आदेश दिया जा खुका हो तो सभा के विरुद्ध कोई भी वाद या वैधानिक कार्यवाही केवल रिजस्ट्रार की अनुमित से ही श्रीर ऐसी शतों के श्रिधीन रहते हुए, जो वह श्रारोपित करे, की जा सकेगी, श्रान्था नहीं।
- 110. त्र्यतिरिक्त सकलसम्पति (assets) को ठयवस्थापना. जब किसी रद्द की गई सभा के समस्त दायित्व, जिन में प्रदत्त हिस्सों की प्रंजी सम्मिलित होगी, पूरे किए जा चुके हों तो अतिरिक्त सकलसम्पति (assets) इसके सदस्यों में विमाजित नहीं की जाएगी, किन्तु वह सभा की उपविधियों में

विधान उद्देश्य या उद्देश्यों में विनियोजित कर दो जाएगी और जब किसी भी उद्देश्य का इस प्रकार से वर्षा न न हो तो वह सार्वजनिक उपादेयता के किसी भी उद्देश्य में लगा दी जाएगी, जो सभा की सामान्य बैटक द्वारा निश्चित हुआ हो, और सामान्य बैटक द्वारा विहित अविध में उक्त उद्देश्य का निश्चय न हो मकने पर रजिस्ट्रार द्वारा वह पूर्णत्या या अंशतया निम्नलिखित समस्त प्रयोजनीं अध्या इन में से किसी भी प्रयोजन के लिए अमिहस्तांकित कर दी जाएगी:—

- (क) स्थानीय हित की सावजनिक उपादेयता के उद्देश्य में अभिहस्तांकन,
- (ख) चरीटेवल ऐन्डोमेन्ट्स ऐक्ट, 1890 (Charitable Endowments Act, 1890) की धारा 2 में परिभाषित किसी परोपकारी कार्य में अभिहस्तांकर,
 - (ग) वित्त प्रबन्धक अधिकोष में उस समय तक अभिहस्तांकन, जब तक उसी या प्रतिवासी चेत्र में उसी प्रकार के उद्देश्य वाली नई सभा का पंजीयन नहीं होता और तदुपरान्त रिजस्ट्रार की सहमति से उक्त अतिरेक ऐसी नई सभा की आरिन्तित निधि में जमा किया जा सकेगा।

अध्याय 13

च्चेत्राधिकार, अपील तथा पुनरीच्या

- 111. उन्दुक्ति. रजिस्ट्रार या उसके ऋघीनस्थ व्यक्ति या उसके प्राधिकार से काम करने वाले किसी व्यक्ति या ग्यासधारी (trustee) के विरुद्ध इस ऋधिनियम के ऋधीन ऋभिप्रित या सद्भावना से किए गए किसी भी कार्य के लिए कोई भी वाद, ऋभियोजन (prosecution) या वैधानिक कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी।
- 112. न्यायालयों के चित्राधिकार पर स्कावट -(1) इस ऋधिनियम में को गई व्यवस्था को छोड़ कर, कोई भी दावानी या माल न्यायालय निम्नलिखित के सम्बन्ध में चेत्राधिकारसम्पन्न नहीं होगा—
 - (क) सभा या उसकी उपविधियों या सभा के उपविधियों के संशोधन का पंजीयन, या
 - (ख) प्रबन्ध समिति का विघटन (dissolution) श्रीर उसके विघटन पर सभा का प्रबन्ध, या
 - (ग) ऐसा कोई विवाद, जो धारा 87 के अधीन रिजस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या
 - (घ) सभा के समापन ऋौर विघटन (winding up and dissolution) से सम्बन्धित कोई विषय ।
 - (2) जब किसी सभा का समापन किया जा रहा हो तो उक्त सभा के अवसाय से सम्बन्धित कोई भी बाद या अन्य वैधानिक कार्य बाही विगिणिक के विरुद्ध विगिणिक के रूप में या सभा अथवा उसके किसी सदस्य के विरुद्ध केवल रिजिस्ट्रार की अनुमित ले कर आरे ऐसी शतों के अधीन रहते हुए ही चलाई जाएगी या दायर की जा सकेगी, जो वह आरोपित करे, अन्यथा नहीं।
 - (3) इस ऋधिनियम में जो व्यवस्था की गई है उसे छोड़ कर इस ऋधिनियम के ऋधीन, किसी भी आदेश, निश्चय या परिनिर्णाय (award) पर किसी भी न्यायालय में चेत्राधिकार न होने के

ब्राधार से ब्रान्यथा किसी भी प्रकार के ब्राधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा, न ही वह रह किया जा सकेगा, न ही उसमें संपरिवर्त न किया जा सकेगा, न ही उसकी पुनरावृत्ति की जा सकेगी या उसे शूर्य घोषित किया जा सकेगा।

- 113. अपील -दूसरी अनुमूची के दूसरे स्तम्भ में प्रदर्शित आदेश पर अपील उसके तीसरे स्तम्भ में प्रदर्शित प्राधिकारी के पास और उसके चौथे स्तम्म में प्रदर्शित आधिकारी के पास और उसके चौथे स्तम्म में प्रदर्शित अविध में की जाएगी।
- (2) इस अधिनियम में की गई व्यवस्था को छोड़ कर इस अधिनियम के अनुपालन में दिए गए ब्रादेश, किए गए निश्चय या परिनिर्णाय (awards) के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी और प्रत्येक उक्त आदेश, निश्चय या परिनिर्णाय (awards) अन्तिम होगा।
- 114. पुनरीच्या स्त्रीर पुनरावृत्तिः—राज्यशासन इस स्त्रिधिनियम के स्त्रधीन की गई किसी पिरपुच्छा या किए गए किसी निरीच्या के स्त्रभिलेख या रिजस्ट्रार या उसके स्त्रधीनस्थ व्यक्ति या उसके प्राधिकर से काम करने वाले किसो व्यक्ति की कार्यवाहियां मंगवा सकेगा और उनकी जांच कर सकेगा स्त्रीर उन पर ऐसे स्रादेश दे सकेगा, जो वह उचित समभे।
 - (2) रजिट्टार किसी भी समय --

- (क) ऐसे किसी भी ऋादेश की पुनरावृत्ति कर सकेगा, जो उसने स्त्रयं दिया हो, या
- (ख) इस श्रिधिनियम के श्रिधीन की गई किसी परिष्टच्छा या किए गए किसी निरीक्षा के श्रिधिलेख वा उसके श्रिधीनस्थ व्यक्ति या उसके प्राधिकार से काम करने वाले व्यक्ति की कार्यवाहियां मंगवा सकेगा श्रीर उनकी जांच कर सकेगा श्रीर यदि उसे यह प्रतीत हो कि कोई निश्चय, श्रीदेश या परिनिर्णय (award) या इस प्रकार मंगवाई गई कोई कार्यवाहियां किसी कारण से संपर्रिवर्तित या श्रिभिश्चर्य कर दो जानी चाहिए या उल्ट दी जानी चाहिए तो उस पर ऐसे श्रादेश दे सकेगा जो वह उचित समके:

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खगड़ (क) या खगड़ (ख) के श्रधीन कोई भी श्रादेश देने से पूर्व रिजिस्ट्रार ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिस पर उक्त श्रादेश से प्रतिकृत प्रभाव पड़ने को सम्भावना हो, सुनवाई का एक श्रवसर देगा।

अध्याय 14

अपराध, शास्तियां और प्रक्रिया

- 115. कुछ उपपातकों के लिए शास्ति.—जब रजिस्ट्रार को यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों या उपविधियों का :—
 - (क) प्रवन्धक समिति के सदस्य के रूप में बैठ कर या मत दे कर यास भा के मामलों में किसी अपन्य ऐसी सभा जो उक्त सभा की सदस्य हो, के प्रतिनिधि के रूप में

मत दे कर या किसी सभा के सदस्य के नाते ऋधिकार प्रयोग करके उल्लंघन किया है, जबिक उक्त व्यक्ति, स्थितिऋनुसार, इस प्रकार से बैठने या मत देने या उक्त ऋधिकार प्रयोग करने के लिए ऋधिकृत न हो, या

- (ख) किसी ऋगा को ऐसे प्रयोजन में लगा कर उल्लंघन किया है, जो उससे भिन्न हो जिसके लिए ऋगा स्वीकार किया गया हो, तो रिजस्ट्रार नियमों के प्रतिवन्धाधीन श्रीर उक्त व्यक्ति को सुनवाई का श्रवसर देने के पश्चात् एक लिखित श्रादेश से उसे यह निदेश दें सकेगा कि वह शास्ति के रूप में ऐसी राशि जो रिजस्ट्रार प्रत्येक उक्त उल्लंघन के सम्बन्ध में उचित समभें, समा की सकलसम्पत्ति में दें।
- 116. ऋपराध और शास्तियां तीसरी ऋनुसूची के तीसरे स्तम्भ में वर्णित कोई भी व्यक्ति, जो उसके दूसरे स्तम्भ में प्रदर्शित किसी ऋपराध का दोषी हो, इस ऋधिनियम में या तस्काल प्रचलित अन्य किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी ऋपराधी ठहराए जाने पर उस के चौथे स्तम्भ में प्रदर्शित शास्ति का भागी होगा।
- 117. अपरायों का संज्ञान (1) प्रथम श्रेणी के मिजस्ट्रेट के न्यायलय से निम्न श्रेणी का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराधों की अन्वीज्ञा नहीं करगा।
- (2) किमिनल प्रोसीजर कोड, 1898 (Criminal Procedure Code 1898) में किसी बात के होते हुए भी इस ऋधिनियम के ऋभीन प्रत्येक अपराध उक्त कोड के प्रयोजनार्थ अस ज्ञेय (non-cognizable) समक्षे जाए गे।
- (3) रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति के बिना उस ऋधिनियम के अधीन कोई भी अभियोग दायर नहीं किया जारेगा।

अध्याय 15

- 118. नियम बनाने की शिक्ति.—(1) राज्यशासन समस्त हिमान्नल प्रदेश या उसके किसी भाग के लिए और किसी सभा या सभाश्रों की श्रेगी के लिए पूर्वप्रकाशन के पश्चात् इस ऋधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।
- (2) विशेषतया श्रीर पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकृत प्रभाव न डालते हुए उक्त नियमों में निम्निलिखित विषयों में से समस्त या किन्हीं की व्यवस्था की जा सकेगी; श्रर्थात्:
 - (1) धारा 2 के खन्ड (19) में निर्दिष्ट राशियों के साथ ही साथ लाभों में से घटाई जाने वाली राशियां;
 - (2) सहकारी वर्ष की अविध ;
 - (3) इस श्रिघिनियम के किन्हीं भी उपबन्धों से किसी सभा या सभा-श्रेगी की विमुक्ति तथा वह सीमा, जहां तक इस श्रिघिनियम के कोई भी उपबन्ध किसी भी सभा या सभा-श्रेगी पर प्रयुक्त होंगे;
 - (4) वह सीमा, जिस तक ऋौर वह रीति, जिसके अनुसार रिजस्ट्रार की सौंपी गई शक्तियां ऋौर कतव्य ऋन्य व्यक्तियों को टिए जा सकेंगे;

- (5) किसी सभा या सभा श्रे गी के पंजीयन की शर्तें ;
- (6) सभा के हिस्सों को पूंजी का ऋधिकतम ऐसा भाग (portion), जो सदस्य द्वारा धारा 5 के ऋधान रखा जा सकेगा, या;
- (7) सभा के पंजीयन के लिए दिए जाने वाले पत्र का प्रपत्र ऋौर पालन की जाने वाली शर्ते तथा उक्त प्रार्थना पत्र के विषय में प्रक्रिया ;
- (8) सभा के विमाजन तथा सभाओं के एकीकरण (amalgamation) की प्रक्रिया और रातें ;
- (9) सभा की सदस्यता के पंजीयन के लिए प्रिक्तिया और वह सीमा, जिस तक सभा श्रापने सदस्यों की संख्या सीमित कर सकेगी,
- (10) वह विषय, जिसके सम्बन्ध में सहकारी सभा उपविधिया बनाएगी या वना स्वेगी और उपविधियां के संशोधन की प्रक्रिया और शतें:
- (11) वित प्रबन्धक अधिकोष बैंक द्वारा शक्तियों के प्रयोग करने की प्रक्रिया और शतें ;
- (12) सामान्य बठकों को बुलाने ऋौर करने की प्रिक्रिया तथा उक्त बैठकों द्वारा की जाने की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग;
- (13) वे प्रतिबंध, जिन के अन्तर्गत सभा का सद्स्य धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन मतदान हेतु अयोग्य हो जाएगा ;
- (14) धारा 18 के ऋधीन किसी सदस्य द्वारा ऋपने पास ऋधिकतम धारण (maximum holding) के लिए शतें;
- (15) सभा के वार्षिक लेखे बन्द करने का दिनांक;
- (16) सभा की प्रवन्धक रुमिति बनाने की पद्धति जिस में रुमुचित स्वत्वों का प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति भी सम्मिलित होगी;
- (17) विभिन्न श्रे शियों की सभाओं की प्रबंधक समितियों के सदस्यों श्रोर पदाधिकारियों की योग्यताएं, श्रयोग्यताएं, पदावधि, मुश्रतली तथा उन्हें पद से हटाना
- (18) प्रबन्धक समिति की बैठकों में प्रक्रिया श्रीर प्रवन्धक समिति तथा सभा के पदिश्विकरियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां तथा सम्पादित किए जाने वाले कर्तव्य;
- (19) वे परिसिधतयां, जिन में धारा 24 के प्रयोजनार्थ प्रातिनिधि (delegates) चुने जा सकेंगे। वह रीति जिस के अनुसार इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनओं के लिए प्रतिनिधि चुने जा सकेंगे; और वह रीति, जिस के अनुसार उस प्रकार निर्वाचित किए गए प्रतिनिधि मत देंगे:
- (29) धारा 28 के अधीन राज्य के प्रनियुक्त कर्मचारी को प्रनियुक्त करने की शतें तथा उस के द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और सम्पादित किए जाने वाले कर्तव्य;
- (21) सभा की प्रबन्धक समिति के निलम्बन या अप्रतिष्ठान (supersession) की रीति और शर्ते और धारा 30 के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति का ढंग और उनकी योग्यताएं;

- (22) वह प्रिक्ष्या, जिसके ऋतुसार समा का पता और पते में किया गया परिवर्तन पंजीकृत किया जाएगा;
- (23) विभिन्न श्रे एयों की समाश्रों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले वेतन पर काम करने वाले कर्मचारीगए। की संख्या श्रीर उनकी यांग्यताएं;
- (24) वे लेखे, पुस्तकें श्रीर पंजियां को सभाएं श्रपने पास रखेंगी तथा वे विवरग्पत्र जो सभाएं प्रस्तुत करेंगी, वह प्रपत्र, जिसमें तथा वे व्यक्ति, जिन के द्वारा उक्त लेखें पुस्तकें श्रीर पंजियां रखी जा सकेंगी तथा उक्त विवरण पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे, उक्त लेखों, पुस्तकों श्रीर पंजियों को सुर्गद्धित रखने श्रीर समाप्त करने का ढंग तथा वे शुल्क जो ऐसे विवरणात्रों वो, जो नियमों के श्रनुपालन में प्रस्तुत न किए गए हों तैयार करने के लिए निर्धारित किए जा सकेंगे श्रीर लगाए जा सकेंगे;
- (25) वे प्रलेख, जो किसी सभा द्वारा धारा 34 के त्राधीन निरीक्षण के लिए खुलें रखे जाएँगे;
- (26) वह रीति जिस में धारा 25 के अवीन सन्तुलन,पत्र (balance sheet) प्रकाशित किया जायेगा;
- (27) वह रीति, जिस में सभा धारा 37 के ऋधीन ऋपनी निधियों को विनियोजित कर सकेगी या जमा कर सकेगी;
- (28) वे शर्तें, जिन में, श्रीर वह सीमा, जिस तक, धारा 38 के श्रधीन समा के लाम उस के सदस्यों में बांटे जा सकेंगे;
- (29) वह अनुपात (proportion), जो प्रत्येक वर्ष सभा के शुद्ध लागों में से निकाल कर आरिक्त निधि में रख दिया जाएगा, वह सीमा जिस तक कोई सभा अपनी आरिक्त निधि अपने व्यवसाय में प्रयोग कर सकेगी और आरिक्त निधि के विनियोजन का ढंग;
- (39) श्रंशदान की वह राशि या श्रद्धपात, जो सभा धारा 41 के श्रधीन मिक्य-निधि (provident fund) में दे सकेगी;
- (31) वह रीति, जिस में सभा को धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन सुनवाई का अवसर दिया जा सकेगा;
- (32) वे शर्तें जिन पर श्रौर वह सीमा जिस तक धारा 42 की उपधारा (1) के उपबन्धों में दी गई छूट (relaxation) के श्रनुसार ऋगा दिए जा सकेंगे श्रौर सभा द्वारा श्रपने सदस्यों के श्रिधिकतम तथा असामान्य ऋगों का निश्चय;
- (33) वे सहकारी प्रयोजन, जिन के लिए सभा धारा 46 के अधीन अपने शुद्ध लाभों की प्रतिशतता का अंशदान देगी, ऐसे अंशदान की सीमा, जो धारा 40 के अधीन दिया जा सकेगा और उक्त अंशदान देमे की रीति;
- (34) ऐसे ऋषा पत्रों को, जो सभा द्वारा जारी किए गए हीं जारी करने, उनके मोर्चन (redemption), उन्हें पुन: जारी करने, उनके इल्तांतरण, उनके प्रतिस्थापन या परिवर्त न

(conversion) की प्रक्रिया ग्रौर शर्ते;

- (35) वे प्रतिबन्ध और शर्तें, जिन के अधीन और वह रीति. जिस के अनुसार, और वह सीमा जिस तक, सभा हिस्सों, (शेयरों), निद्धेष, ऋगुषपत्रों द्वारा या अन्यथा निधियां जुटा सकेगी और वह रीति, जिस में द्रव साधनों (fluid resources) के संधारण की व्यवस्था की जाएगी;
- (36) न्यासधारी ऋौर सभा के मध्य न्यास के विलेख में परिवर्त न करने की प्रक्रिया ऋौर रुतें ;
- (57) सभा से ऋगा मांगने वाले सदस्यों द्वारा की जाने वाली चुकितयां श्लीर श्रनुपालनीय शर्ते तथा वह श्रविध, जिसके लिए उधार दिए जाए गे श्लीर वह राशि, जो किसी एक सदस्य की दी जाएगी;
- (38) धारा 51 के अधीन किसी प्रलेख के प्रमाणिकण का टंग, प्रलेखों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने की प्रक्रिया और शतें और व शुल्क, जो प्रमाणित प्रतिलिपियां देने के लिए आरोपित किए जा सकेंगे:
- पद्धति तथा धारा 52 और धारा 69 के ऋधीन किसी सभा द्वारा मृत सदस्य के नामांकित व्यक्ति के प्रतिस्थापन (substitution) के लिए और सभा द्वारा धारा 52 के ऋधीन कार्यवाही करने का निश्चय निश्चित करने के लिए प्रक्रिया और शर्ते और धारा 52, धारा 68 और धारा 69 के प्रयोजनार्थ उसे देय राशियों के ऋग्गणन के लिए प्रक्रिया;

(39) किसी सदस्य या इस्तांतरग्रहीता द्वारा नामांकन के लिए प्रिक्रया और शर्तें तथा नामांकन की

- (40) वह प्रक्रिया, जिस के द्वारा श्रीर वे शर्ते, जिन के श्रधीन धारा 55 या धारा 57 के श्रन्तर्गत सुरज्ञा (गारन्टी) या वित्तीय सहायता दी जा सकेगी;
- (41) धारा 57 के अधीन ऋगा पत्रों की सुरत्ता (गारन्टी। के लिए मूलधन की अधिकतम राशि, ब्याज का मान (rate) और अन्य शर्ते;
- (42) वे निषेध ग्रौर श्रायन्त्रण, जिन के श्रधीन रहते हुए सभाएं ऐसे व्यक्तियों के साथ व्यवसाय कर सकेगी, जो सभा के सदस्य न हों;
- (43) सभा के दायित्व के रूप में पश्वितन करने के लिए प्रक्रिया ऋौर शर्ते;
- (44) ऐसी प्रत्येक दशा में, जिस में इस अधिनियम या नियमों के अधीन कोई सूचना (नेटिस) या प्रसर (process) जारी किया गया हो---
 - (क) स्चना (नोटिस) या प्रसर (process) का प्रपत्र;
 - (ख) दी जाने वाली सूचना (नोटिस) की अवधि;
 - (ग) व व्यक्ति, जिन पर या जिन के विरुद्ध सूचना (नोटिस) या प्रसर (process) जारी किया जाएगा; और
 - (घ) वे शर्तें, जो उक्त सूत्रना (नोटिस) या प्रसर (process) की तामील (service) का प्रमाण स्थापित करने के लिए पूरी की जाएंगी;

- (45) वे परिस्थियां, जिनमें किसी सभा के पत्त में कोई प्रभार पूरा किया जाएगा ऋौर वह सभा, जिस तक ऋौर वह कम, जिस में सम्पत्ति प्रभार के ऋघीन रहते हुए उसे पूरा करने के प्रयोग में लाई आएगी;
- (46) धारा 62 द्वारा अपेत्तित मांग के लिखित दिवरण का प्रारूप;
- (47) घारा 64 स्त्रीर 65 के ऋधीन प्रार्थ ना-पत्र का प्रारूप, घारा 64 स्त्रीर 65 द्वारा अपेद्धित मानचित्र स्त्रीर विवरण का प्रारूप स्त्रीर उसके प्रकारन की गीत, तथा धारा 64 स्त्रीर 65 में व्यवस्थित जल-कर स्त्रीर तटबंद सुरह्मा-कर लगाने की गीत;
- (48) वे परिस्थितियां ऋौर रीति, जिसमें कोई सदस्य त्याग पत्र दे सकेगा या सभा से निकाला जा सकेगा;
- (49) वह प्रक्रिया, जिसके द्वारा कोई सभा ऋशोध्य-ऋण (irrecoverable loan) की गणना करेगी श्रोर उसका अपलेखन करेगी;
- (50) वह दिनांक जिसा तक वार्षिक लेखा-परीक्षण किया जाएगा और लेखापरीजा-प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, लेखा परीक्षण करने वाले लेखा परीक्षक की प्रक्रिया, वे विषय, जिन पर वह प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, वह प्रपत्र, जिसमें उसके लेखा परीक्षण के लिए लेखों का दिवरण तैयार किया जाएगा, वे सीमाएं, जिन के भीतर वह सभा के अप्रार्थिक व्यवहारों की जांच कर सकेगा, उसके लेखा-परीक्षण के प्रतिवेदन तथा परीक्षित लेखों के विवरण का प्रारूप और वे शुल्क, यदि कोई हों, जो सभा द्वारा लेखा परीक्षा के लिए दिय जाएंगे;
- (51) घारा 82 के उपबन्धाधीन योजना का विस्तृत व्योरा और परिपृच्छा अधिकारी की नियुक्ति;
- (52) वह रीति, जिस में परिवृच्छा की जाएगी श्रीर धारा 83 के श्रधीन प्रतिवेदन के विषय;
- (53) धारा 85 के उपबन्धाधीन स्चना (नोटिस) के विषय ख्रीर योजना का सम्पादन;
- (54) मध्यस्थ की योग्यताएं श्रौर उसकी नियुक्ति का ढंग, श्रध्याय 10 के अधीन कार्य-वाहियों मैं पालन की जाने वाली प्रक्रिया श्रौर उक्त कार्यवाहियों से श्रानुषंगिक शुल्कों की गणना करने श्रौर उक्त कार्यवाहियों में किए गए निश्चयों के प्रवृत करने का ढंग;
- (55) वह रीति, जिसमें समापित सभा की सकल-सम्पत्ति के अतिरेक की व्यवस्थापना की जाएगी और उसके अभिलेख जमा कराए जाएंगे;
- (56) कुकों (distrant) को प्रभावी करने की रीति और कुर्क की गई सम्पत्ति (ऐसी सम्पत्ति सहित, जो नष्ट होने वाली हो) की संरत्त्व। करने, सुरत्वा करने स्त्रीर विकय करने की रीति, कुर्क की गई सम्पत्ति में अभियुक्त को छोड़ कर दूसरे व्यक्तियों के

श्रिधिकार या स्वत्वों की मांगों की जांच त्र्योर उक्त जांच होने पर क्रय का ग्रागे के लिए स्थगन;

- (57) वह रीति, जिसके अनुसार ऐसा ऋगा नापस लिया जाएगा, जो उस प्रयोजन में न लगाया गर्या हो, जिस के लिए वह दिया गया था;
- (58) वे शतें, जो उस व्यक्ति द्वारा पृरी की जाएंगी, जो सभा का सदस्य बनने के लिए प्रार्थनापत्र दे रहा हो या सभा का सदस्य बनाया गया हो, सदस्य के प्रवेश उन्हें निकालने और उनके पदत्याग के लिए प्रक्रिया और वे शतें; जिन के अप्रतार सदस्य सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग करेंगे;
- (59) वे दशाएं, जिन में श्रौर वे शर्तें, जिन के श्रधीन किसी सभा के समापन का श्रादेश देने में रिजस्ट्रार वाध्य होगा;
- (60) राज्यश सन को की जाने वाली ऋपीलों की दशा में, वह प्राधिकारी, जिसे ऋपील सुनने की शक्ति सौंप' जा सकेगा;
- (61) रिजस्ट्रार के कार्यालय में प्रलेखों का निरीद्याण करने की प्रक्रिया तथा शर्ते ज्यौर शुल्क, यदि कोई हों, जो उक्त निरद्धाण के लिये आरोपित किए जाए;
- (62) ऐसे व्यैयों, प्रभारां या खर्चों, के जिनका आरोपण इस अधिनियम या नियमों के अधीन अपेद्यित हो, आगणन की प्रक्रिया, और उन के आगणन का ढंग;
- (63) इस ऋधिनियम या नियमों के ऋधीन देय राशियों की वस्ली के लिए प्रक्रिया और उन्हें वस्न करने का ढंग;
- (64) एसा कोई भी आदेश, नियम या परिनिंग प पहुंचाने या उसके प्रकाशन का ढंग, जिसे पहुंचाना या जिसका प्रकाशन इस अधिनियम या नियमों के अधीन अपेंचिंत हो;
- (65) धारा 90 के ऋधीन सप्रतिबन्ध कुर्की की प्रकिया;
- (66) धारा 94 के ऋधीन प्रार्थना पत्र के लिए प्रपत्र ऋौर प्रकिया तथा उस धारा के अधीन बैटक बुलाने, करने, लगाने ऋोर उस के संचालन की प्रक्रिया;
- (67) धारा 95 श्रौर 96 द्वारा पटत, शक्तियों के प्रयोग की प्रक्रिया प्रतिबन्ध श्रौर ढंग;
- (68) वे व्यक्ति, जो धारा 97 के अधीन परिनि एर्य दे सर्केंगे;
- (96) धारा 98 के अधीन परिपृच्छा करने और उस की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिंध्ट विषयों के सम्बम्ध में प्रक्रिया और सिद्धान्त:
- (70) धारा 99 द्वारा प्रदत शक्तियों के प्रयोग के लिये प्रक्रिया ऋौर सिद्धांत;

- (71) विगणिक की मियुक्ति स्रौर उसे हटाने तथा उसके परिलाम चुकाने की प्रक्रिया, उक्त नियुक्ति की शर्ते, वे प्रतिबन्ध , जिन के स्रनुसार रिजस्ट्रार विगणिक पर नियन्त्रण रखेगा तथा उसे धारा 104 के स्रधीन स्रपनी शक्तियों का प्रयोग करने का निदेश देगा तथा स्रध्याय 12 के स्रधीन कार्यवाहियों में स्रनुपालनार्थ प्रक्रिया;
- (72) घारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग।
- (3) इस श्रिधिनियम के श्रिधीन कोई भी नियम बनाते समय राज्य शासन यह निदेश दे सकेगा कि, जो व्यक्ति उसका उल्लाधन करेगा न्यायालय द्वारा श्रिपाधी टहराए जाने पर पचास रुपया तक के श्रिधी दन्ड का भागी होगा श्रीर जहां उल्लंधन निरन्तर ही उस श्रिबस्था में पहले दिन के पश्चात् प्रतिक ऐसे दिन के लिए 10 रुपया तक के श्रिधी दन्ड का भागी होगा, जिसके मध्य श्रपराधी ठहराएँ जाने के पश्चात उल्लंधन जारी रहे।

अध्याय 16

प्रकीर्ण

- II9. निरसन (repeal).—कोप्रेटिय सोसायटीज ऐक्ट, II (सॅट्रल) 1912, (Co-operative Societies Act, II (central) 1912) का जहां तक कि वह हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रयुक्त हुँ है एतत् द्वारा निरसन किया जाता है।
- 120. वर्तमान सभाश्रों का बचाव.—(1) प्रक्षेक विद्यमान सभा, जो कोपेटिव के डिट सोसायाटीज ऐक्ट II, 1912 के अधीन पंजीकृत हो चुकी हो इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत मानी जाएगी और इसकी उपविधियां जहां बक कि वो इस अधिनियम के स्पष्ट उपवस्थों से असंगत न हों तब तक प्रचलित रहेंगी, जब तक कि उन्हें आपिरिवर्तित या अमुश्हन्य (resind) न किया जाए।
- (2) कोप्रेटिय सुसायटीज ऐक्ट, 1912 के ऋषीन की गई समस्त नियुक्तियां, बनाए गए नियम और दिए गए ऋदिश जारी की गई समस्त ऋषिसूचनाएं ऋौ सूचनाएं (नोटिस) कए गए समस्त व्यवहार ऋौर उनकी कार्यवाहियों में दायर किए गए समस्त वाद, जहां तक हो सके, इस ऋषिनियम के ऋषीन बनाए गए, जारी किए गए, या दायर किए गए समस्ते जायोंगे।
- · 121. इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1913 प्रयुक्त नहीं होगा.—इन्डियन कम्पनीज ऐक्ट के उपबन्ध पंजीकृत सभात्रों पर प्रयुक्त नहीं होंगे।
- 122. राज्य से वाहर को सभात्रों की शाखाएं.—हिमाचल प्रदेश से बाहर पंजीकृत प्रत्येक ऐसी सभा, जिस की हिमाचल प्रदेश में कोई शाखा या व्यवसाय स्थान हो या जो हिमाचल प्रदेश में कोई शाखा स्थापित करे, इस श्रिषिनियम का प्रारम्भ होने से या उक्त शाखा या व्यवसाय स्थान की स्थापना से छः मास के भीतर रिजस्ट्रार को अपनी उपविधियों और संशोधनों की एक प्रतिलिपि देगी और उन विवरणपत्रों तथा

सूचनात्रों के साथ ही साथ, जो उसराज्य के रिजस्ट्रार को प्रस्तुत की जाती हीं जहां पर वह व जीकृत हो ऐसे विवरण्वत्र ऋौर ऐसी सृचनाएं, जो हिमान्नल प्रदेश में उसी प्रकार की सभाऋों द्वारा प्रस्तुत की जाती हों, रिजस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी।

123. वादों में आवश्यक सूचना — जब तक लिखित रूप में एक ऐसी सूचना, जिस में वाद मूल (cause of action), वादी का नाम, व्योरा और निवास स्थान तथा सहायता जो उसने मांगी हो, प्रदर्शित हो, रिजस्ट्रार को प्रदान कर दिए जाने या उसके कार्यालय में पहुंचा दिए जाने के पश्चान दो मास व्यतीत न हो गए हों तब तक किसी भी सभा या उस के किसी पदाधिकारी के विरुद्ध, सभा के व्यवसाय से सम्बन्द्ध किसी भी कार्य के सम्बन्ध में कोई भी वाद दायर नहीं किया जायगा और वादपत्र में यह विवरण होगा कि उक्त सूचना उक्त रूप से प्रदान कर दी गई थी या पहुंचा दी गई थी।

प्रथम अनुस्ची

कम संख्या

देय राशि का नाम

वसूली का ढंग

- धारा 72 के अधीन सभा के लेखे को पूरा करवाने में 1 किया गया व्यय तथा धारा 99 के अधीन परिनिर्णीत राशियां।
- रजिस्ट्रार के मांग पत्र पर कलेक्टर द्वारा भुराजस्व के बकाए के रूप में या धारा 72 की दशां में रजिस्ट्रार की ऋनुमति से लेखा-परीचक द्वारा।
- घारा 78 के ऋधीन परिप्रन्धा या निरीक्त का ऋभि-2 भाजित व्यय, धारा 97 के ऋन्तर्ग त परिनिर्णीत देय राशियों की वसूली, धारा 98 के अन्तर्गत चतिपूर्ति के रूप में परिनिर्णात ऋ शदान ऋौर धारा 115 के ऋधीन

परिनिर्णीत राशियां।

- रजिस्ट्रार के मांग पत्र पर कलेक्टर द्वारा भूराजस्व के बकाए के रूप में।
- धारा 78 के ऋधीन दिए गए किसी ऋदिश द्वारा या धारा 89 के ऋधीन अन्तिम बन्धक डिकी के समान प्रभाव-शाली परिनिर्णय द्वारा किसी सहकारी सभा के पच में परिनिर्णीत राशियां।
- जस्व के बकाए के रूप में सभा के प्रार्थना पत्र पर किसी स्थानीय चे त्राधिकार सम्पन्न दीवानी न्यायालय द्वारा उसी रीति, में जैसे कि उस की डिक्री।

सभा के मांग-पत्र पर कलेक्टर द्वारा भूश-

- विगणिक द्वारा धारा 105 के ऋषीन अंशटानों के रूप
 - रजिस्ट्रार या विगिशिक के मांग-पत्र पर में निर्धारित राशियां। कलैक्टर द्वारा भूराजस्व के बकाए के रूप में ।
- इस ऋघिनियम के ऋघीन बनाए गए किसी नियम के विहित रीति में। 5 श्रन्तग त देय राशियां।

द्सरी अनुसूची

		4/1/1 20 3/2/21	
कम २ ०	त्रपील योग्य त्रादेश 2	व व्यक्ति, जिनके द्वारा श्रीर वे प्राधिकारी, जिन के पास श्रपील को जा सकेगी 3	परिसीमा ऋवधि 4
समा या १ उपविधि	हे अर्थोन किसी सहकारी बारा 12 के अर्थोन किसी के संशोधन के पंजीयन कृति का आदेश।	सभा के किसी भी सदस्य द्वारा— (क) यदि रिजस्ट्रार द्वारा दिया गया हो तो राज्यशासन के पास, या (ख) यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया हो तो रिजस्ट्रार के पास।	
श्रादेश य प्रबन्धक स तथा सभ	त अधीन अयोग्यता का ाधारा 30 के अधीन तमिति का विघटन करने ता के कार्यों का प्रबन्ध तए व्यक्ति को नियुक्ति	प्रबन्धक समिति के किसी भी सदस्य द्वारा— (क) यदि रिजस्ट्रार द्वारा दिया गर्या हो तो राज्यशासन के पास, या (ख) यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया हो तो रिजस्ट्रार के पास।	स्रादेश सभा को दिया गया
गए सिंच ग्रधीन तै दोत्र के स	न केत्र या धारा 65 कें गैयार किए गए रिजत प्रान चित्र के विवरण में गोई प्रतिध्टि या उस से	किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा कलेक्टर के पास ।	
घारा 6	के श्रधीन जल-कर या 5 के श्रधीन तटबद्ध रकानिर्घीरण।	किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रार के पास।	विवरण का प्रकाशन होने के दिनांक से एक मास।
		किसी भी पीडित व्यक्ति द्वारा डिस्ट्रिक्ट ज ज के पास।	उस दिनांक से एक मास जब पीड़ित व्यक्ति को त्रादेश दिया गया हो।

दसरी अनुसूची- क्रमागत

2 3" - 1 1 4

किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा - उस दिनांक से एक मास जब 6 धारा 88 या 89 के श्रधीन रजि-(क) यदि रजिरट्रार द्वारा दिया स्टार या विवाचक का कोई आदेश त्रादेश निश्चय या परिनिर्णय

गया हो तो राज्यशासन के निश्चय या परिनिर्णय। पीड़ित व्यक्ति को दिया गया

पास, या

हो । (ख) यदि किसी दूसरे व्यक्ति

द्वारा दिया गया हो तो

रजिस्ट्रार के पास । सभा के किसी भी सदस्य द्वारा- उस दिनांक से दो मास जब 7 बारा 103 के श्रधीन सभा के समा-

गया हो तो राज्यशासन के पास, या

पन का ऋदिश। ै

(ख) यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया हो ती रजिस्ट्रार के पास ।

50 किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा उस दिनांक से दो मास जब

8 धारा 105 के अधीन विगणिक का श्रादेश, निश्चय या परिनिर्णय । रजिस्ट्रार के पास ।

. हो। The second second second 9 धारा 98 या 99 के ऋधीन दिया किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारी उस दिनांक से तीन मास जब ं स्रादे पीड़ित व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट जज के पास । गया आदेश।

10 ऐसा कोई भी ब्रादेश या निश्चय, उस व्यक्ति द्वारा जो नियमों द्वारा विहित ऋवि । विहित प्राधिकारी के पास जो इस अधिनियम के अधीन

नियमों द्वारा ऋपील योग्य घोषित अपील करने के लिए सचम घोषित हो । हुत्रा हो।

PRODUCT OF THE

(क) यदि रजिस्ट्रार द्वारा दिया सभा को ऋदिश दिया गया

हो ।

श्रादेश निश्चय या निर्णय पीड़ित व्यक्ति को दिया गया

दिया गया हो।

तीसरी अनुमूची

क्रम ·	श्च पराघ	उत्तरदायी व्य क्ति	शास्ति
ख्य 1	2	3	4
1	किसी ऐसे नाम या शीर्ष के में शब्द "सहकारी" का अप्राधिकृत प्रयोग, जिसके अधीन धारा 7 का उल्लंघन करके व्यवसाय चलाया जा रहा हो।	जिस मैं यह शब्द इस प्रकार प्रयोग होता हो उस नाम या शीर्ष क के ऋषीन व्यवसाय चलाने वाली कम्पनी, सभा या व्यक्ति ।	ऐसा श्रर्थं दन्ड, जो 50 ६० तक हो सकेगा, श्रौर यदि श्रपराध जारी रहे तो श्रपराधी ठहराए जाने के पश्चान प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें श्रपराध जारी रहे पचात ६पए तक का पुन: श्रर्थं दन्ड।
2	िक्सी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य करने, कोई विवरण बनाने या सूचना देने में प्रमाद करना या इन्कार करना जिसे करने, बनाने या प्रदान करने की इस ऋधिनियम या नियमों के ऋधीन ऋषेचा की गई हो।	कार्य करने, विवरण बनाने या सूचना प्रदान करने में प्रमाद करने वाला या उस से इन्कार करने वाला व्यक्ति।	ऐसा ऋर्थ दन्ड, जो 50 रू तक हो सकेगा और यदि ऋपराध जारी रहे तो ऋपराधी ठहाराए जाने के के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें ऋपराध जारी रहे पचास रुपए तक पुन: ऋर्थ दन्ड ।
3	जान बूभ कर भूटा विवरण बनाना या भूटी सूचना प्रदान करना, जिसे बनाना या प्रदान करना इस ऋधिनियम या नियमों के ऋधीन ऋषेत्ति हो।	जानवृक्ष कर भूटा विवरण् बनाने वाला या भूटी सूचना प्रदान करने वाला व्यक्ति।	ऐसात्र्यर्थंदन्ड जो एक सौ रुपए तक हो सकेगा।
4	सभा को घोखा देने के विचार से या सभा के प्रथम प्रभार के प्रतिकृत कांई कार्य करने के विचार से ऐसी सम्पत्ति को हटाना या व्यवस्थापित कराना या ऐसी	वह व्यक्ति, जिस द्वारा थे, जिस की स्रोर से सम्पत्ति हटाई गई हो या निराकत की गई हो या कार्य किया गया हो।	ऐसा कारावास जो आहः महीने तक का होगा या ऐसा जुर्माना जो पांच सौ रुपए तक होगा।

तीसरी अनुसूची — क्रमागत

1

2

3

4

सम्पति हटाने या ब्यवस्थापित करने में सहायता करना जिस पर धारा 70 के ऋषीन सभा का प्रथम भार हो ।

5 कोई ऐसा कृत्य या ऐसी भूल जो नियमों द्वारा अप्रपराध बोषित हो।

ऐसा व्यक्ति जिसे नियमों द्वारा उत्तरदायी टहराया गया हो।

नियमों में न्यवस्थित शास्ति।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

को-स्राप्ते टिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1912, हिमाचल प्रदेश में प्रयुक्त किया गया था। यह ऐक्ट बहुल पुराना है स्नौर भारत में बहुत से राज्यों ने इस सम्बन्ध में अपने विधान बना लिए हैं। गत 40 वर्षों में सहकारी झांदोलन ने प्रशंसनीय प्रगति की है और इस दिशा में अत्याधिक अनुभव प्राप्त हो गया है, अतः प्रतिदिन की स्नावश्यकताओं की पृर्ति के लिए तथा सहकारी आंदोलन के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए यह स्नावश्यक है कि सहकारी सभाओं से सम्बन्धित विधि का संकलन किया जाए। इस विधेयक का उद्देश हिमाचल प्रदेश में सहकारी सभाओं से सम्बन्धित विधि का संकलन तथा संशोधन करना है। और साथ ही साथ इस में सभाओं के एकीकरण और विभाजन की प्रक्रिया और कृषि सभाओं के पंजीयन की भी व्यवस्था की गई है। और यह विधेयक कुछ परिस्थितियों में शिद्धा-निधि की भी व्यवस्था करता है।

पग्न देव

बन्सी घर शर्मा सचिव हिमाचल प्रदेश, विधान सभा ।

